



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2019/ श्रावण 9, 1941

No. 227]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2019/ SHRAVANA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. और वियतनाम से वेल्ड किये हुए स्टेनलैस स्टील पाइप और ठ्यूब के आयातों के संबंध में संविदीर्घी जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 6/22/2018 – डी जी ए डी.—सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) तथा उसके सीमा प्रशुल्क (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया (इसके पश्चात प्रतिसंतुलनकारी नियमावली अथवा “नियमावली” “नियमावली के रूप में भी संदर्भित”) के संबंध में;

### क. मामले की पृष्ठभूमि

- जबकि, मैसर्स स्टेनलैस स्टील पाइप एंड ठ्यूब्स मैन्युफेक्चर एसो., नई दिल्ली, मैसर्स स्टेनलैस स्टील पाइप एंड ठ्यूब मैन्युफेक्चरर्स एसो., अहमदाबाद, मैसर्स साउथ इण्डिया स्टेनलैस स्टील पाइप एंड ठ्यूब मैन्युफेक्चर एसो. और मैसर्स हरियाणा स्टेनलैस स्टील पाइप एंड ठ्यूब मैन्युफेक्चर एसो. (इसके पश्चात “याचिकाकर्ताओं” के रूप में भी संदर्भित)

ने चीन जन. गण. और वियतनाम (इसके पश्चात् “संबद्ध देशों” के रूप में भी संदर्भित) से बेल्ड किये हुए स्टेनलैस स्टील पाइप और घूब (इसके पश्चात् “संबद्ध वस्तुओं” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” के रूप में भी संदर्भित) के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात् “प्राधिकारी” के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की है।

2. और, जबकि प्राधिकारी ने इन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कथित सभिस्डी के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निश्चरण करने तथा सभिस्डीरोधी/ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क यदि उसे लगाया जाये, जो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए समुचित होगा की सिफारिश करने के लिए नियम 6 के अनुसार संबद्ध जांच आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 9 अगस्त, 2018 से अधिसूचना सं. 6/22/2018 – डी जी ए डी के संदर्भ में एक आम सूचना जारी की।

#### **ख. प्रक्रिया**

3. यहां नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है :
  - क. प्राधिकारी ने इस जांच को आरंभ करने की कार्यवाही करने से पूर्व वर्तमान सभिस्डीरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में चीन जन. गण. और वियतनाम के दूतावासों को सूचना दी।
  - ख. प्राधिकारी ने सभिस्डी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी करार (ए एस सी एम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने और आपस में सहमत समाधान पर पहुंचने के उद्देश्य से विचार विमर्श के लिए संबद्ध देशों की सरकारों को आमंत्रित किया। प्राधिकारी ने नई दिल्ली में दिनांक 17 जून, 2018 को चीन जन. गण. की सरकार के प्रतिनिधियों (इसके पश्चात् “जी ओ सी” के रूप में भी संदर्भित) तथा दिनांक 6 जुलाई, 2018 को वियतनाम की सरकार के प्रतिनिधियों (इसके पश्चात् “जी ओ वी” के रूप में भी संदर्भित) के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा विचार विमर्श के दौरान भाग लिया गया था। संबद्ध देशों की सरकारों के द्वारा स्पष्ट किये गये तथ्य और प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/ सूचना, यदि कोई हो, को रिकार्ड पर लिया गया था।
  - ग. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/ सभिस्डीरोधी जांच आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 9 अगस्त, 2018 को एक आम सूचना जारी की।
  - घ. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावास, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, घरेलू उद्योग से ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को इन याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार दिनांक 9 अगस्त, 2018 को जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें।
  - ड. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार भारत में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावास को इस आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
  - च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली के एक प्रति भी संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।
  - छ. प्राधिकारी ने विभिन्न योजना/ कार्यक्रमों जहां यह आरोप लगाया गया था कि इन सरकारों/ सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रतिकार योग्य लाभ दिया गया है, के संबंध में संगत तथ्यों/ सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से संबद्ध देशों की सरकार को प्रश्नावली भेजी।
  - ज. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :

- i. शेन जिन 1-टच बिजनेस सर्विस लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ii. बूकसी जोयरे इंटरनेशनल कॉर्पो., चीन जन. गण.
- iii. लियनझाँग स्टेनलैस स्टील कॉर्पो., चीन जन. गण.
- iv. फोशांग लिटेंग इकोनोमी एंड ट्रेड कं. लिमि., चीन जन. गण.
- v. फोशांग गंगदुओ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमि., चीन जन. गण.
- vi. फूजियन फुक्सिन स्पेशनल स्टील कं., लिमि., चीन जन. गण.
- vii. निंबो टियर्सलिया इम्पो. एंड एक्स. कं., लिमि., चीन जन. गण.
- viii. शेनजेन ज़ियोंग स्पेशलिटी स्टील कं., लिमि., चीन जन. गण.
- ix. सिचुंग डायंग ट्रेडिंग कं. लिमि., चीन जन. गण.
- x. शेनझेंग ज़ोंगचुआंग यू स्टील इंडस्ट्री कं., लिमि., चीन जन. गण.
- xi. मिनमेटल्स स्टील कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xii. जियंग सिटी बयोवेई स्टेनलैस स्टील कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xiii. फोशांग सन मिंग ट्रेडिंग कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xiv. पोहंग (ज्ञांगजियांग) स्टेनलैस स्टील प्रोसेसिंग कं. लिमि., चीन
- xv. जियोमेन ग्रेट कोर्पोरेशन, चीन जन. गण.
- xvi. गुआंगडॉग फोरन ट्रेड इम्पो. एंड एक्स. कं., चीन जन. गण.
- xvii. निंबो चाइनावर्ल्ड ग्रांट इम्पोर्ट एंड एक्स. कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xviii. शांडॉग हुयेई स्टेनलैस स्टील प्रॉडक्ट्स कं. चीन जन. गण.
- xix. एक्सपोर्ट कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xx. बीजिंग जिंगनानफंग डेकोरेशन इंजीनियरिंग कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxi. जियोमेन गोल्डन हुनान इम्पो. एंड एक्स. कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxii. यू गांग इम्पो. एंड एक्स. ट्रेडिंग कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxiii. शांकसी ताइगांग स्टेनलैस स्टील कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxiv. मियांझू होंडा ट्रेडिंग कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxv. जियोमेन टांगचेंग इम्पो. एंड एक्स. कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxvi. फोशान विगोर ड्रागोन इम्पो. एंड एक्स. कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxvii. फोशान इंटरनेशनल ट्रेड कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxviii. शंघाई हिस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxix. टी सिंगशांग होलिंडग ग्रुप शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxx. एक्स. कं. लिमिद्र नानजिंग रोविसन, चीन जन. गण.
- xxxi. सोकल स्टील कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxxii. गोमिंग डिस्ट्रिक ऑफ फोशान सिटी ओकटोपस स्टेनलैस स्टील कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxxiii. फोशांग गुआंग यू स्टेनलैस स्टील कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxxiv. ज़ेजियांग, वन ऑफ क्वालकॉम इंटरप्राइजेज सर्विसिस लिमि., चीन जन. गण.
- xxxv. किनफोरो हेनन कंस्ट्रक्शन मशीनरी कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxxvi. चाइना वेस्टर्न पावर इंडस्ट्रीयल कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxxvii. ननहाई शुग टांग इम्पो. एंड एक्स. कं. लिमि. ऑफ फोशन चीन जन. गण.

- xxxviii. टाइकू (जियोमेन) एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग कं. लिमि., चीन जन. गण.
- xxxix. टी ए पी इंटरनेशनल, जे एस सी, वियतनाम
- xl. इनोक्स होआ बिन्ह जे एस सी, वियतनाम
- xli. सोनहा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वियतनाम
- xlii. ओएसएस डाई डुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
- xliii. विनेनोक्स, वियतनाम
- xliv. मिंग हू लियन जे एस सी, वियतनाम
- अ. इसके उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातिकों/ उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातिक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया :
- i. झेजियांग जियूली हाई-टेक मेटल्स् कं. लिमि., चीन जन. गण.
  - ii. सोनहा एस एस पी वियतनाम सोल मेम्बर कं. लिमि., वितयनाम
  - iii. नाम कूओनग मेटल कं. लिमि., वितयनाम
  - iv. ओ एस एस डाई हूओनग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कं. वियतनाम
  - v. हूअन डाट मेटल कं. लिमि., वितयनाम
  - vi. विनलॉग स्टेनलैस स्टील (वियतनाम) कं. लिमि., वितयनाम
  - vii. स्टील 568 कं. लिमि., वियतनाम
  - viii. जियान्ह ज्वाइंट कं. लिमि., वियतनाम
  - ix. हा अन्ह स्टेनलैस स्टील कं. लिमि., वियतनाम
  - x. जिया अन्ह हूअंग येन कं. लिमि. वियतनाम
- अ. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के अनुसरण में संबद्ध देशों के उपर्युक्त उत्पादकों/ निर्यातिकों के अलावा वियतनाम सरकार ने भी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया। हालांकि, चीन सरकार ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ट. प्राधिकारी ने इन नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातिकों/ प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजीं :
- i. मारचि कुमा स्टील घ्यूब प्रा. लिमि.
  - ii. मेप्पीय इंटरनेशनल लिमि.
  - iii. पोस्को-इंडिया दिल्ली स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लिमि.
  - iv. यू - लाइक एक्सपोर्ट
  - v. पोस्को-इण्डिया पूणे स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लिमि.
  - vi. आदिनाथ मेटल
  - vii. शारदा मोटर इंड. लिमि.
  - viii. जे के बी इंटरनेशनल
  - ix. मिनोक्स मेटल प्रा. लिमि.
  - x. अनंतइनोक्स
  - xi. नवनिधि स्टील इंजीनियरिंग कं. प्रा. लिमि.
  - xii. शिवा यूटेनसिल्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.
  - xiii. आटोमेटिव स्टील पाइप इंडिया प्रा. लिमि.

- xiv. राजपूताना स्टेनलैस लिमि.
- xv. स्टेनोक्स एलॉय प्रा. लिमि.
- xvi. राधा रमन स्टेनलैस स्टील प्रा. लिमि.
- xvii. पोस्को इंडिया चैन्नई स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्रा.
- xviii. जानकी मेटल स्ट्रीप्स प्रा. लिमि.
- xix. टेनेको ऑटोमेटिव इंडिया प्रा. लिमि.
- xx. एम एम मेटल इंटरनेशनल
- xxi. रिलायंस फेब्रिकेशन प्रा. लिमि.
- xxii. मुकेश स्टल ट्रेडिंग
- xxiii. आई डी एम सी लिमि.
- xxiv. सनराइज स्टेनलैस प्रा. लिमि.
- xxv. नवनिधि स्टील इंजीनियरिंग कं. प्रा. लिमि.
- xxvi. कोन इलेक्ट्रोट्रॉनिक्स प्रा. लिमि.
- xxvii. पहारपुर कूलिंग टावर्स लिमि.
- xxviii. लार्सन एंड टब्रो लिमि.
- xxix. इनोक्स इंडिया लिमि.
- xxx. गोदरेज एंड बोर्ड मैनिफेक्चरिंग कं. लिमि.
- xxxi. रिनेसेन्स बायोकेमिकल प्रा. लिमि.
- xxxii. सुल्जर इंडिया लिमि.
- xxxiii. इसगेक हेवी इंजीनियरिंग लिमि.
- xxxiv. मनक ओवरसेस लिमि.
- xxxv. सनसिटी स्ट्रीप्स एंड व्ह्यूब्स प्रा. लिमि.
- xxxvi. शाह फ्रायल्स लिमि.
- xxxvii. रेपूट एक्सिम
- xxxviii. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि.
- xxxix. दिव्या किचनवेयर प्रा. लिमि.
- xl. एपेक्स व्ह्यूब्स प्रा. लिमि.
- xli. पंजाब स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्रीज
- xlii. होनेस्ट इंटरप्राइज लिमि.
- ठ. किसी भी आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि, मैसर्स पाक्सल कोरपोरेशन ने इस सुनवाई के दौरान अनुरोध प्रस्तुत किये हैं।
- ड. प्राधिकारी ने इन हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य/ किये गये निवेदनों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- ढ. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से यह अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का तेज देन वार ब्यौरा उपलब्ध करायें जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान उद्देश्य से डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

- ण. उत्पादक की लागत और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और इसकी विक्री करने के लिए लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एन आई पी) निर्धारित की गई है जिससे कि यह पता चल सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन की तुलना में कमतर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/ आंकड़े का मौके पर सत्यापन उस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। जहां भी लागू हुआ आवश्यक संशोधनों के साथ केवल इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।
- थ. उत्पादकों/ निर्यातकों और वियतनाम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया है और उस सीमा तक जिस सीमा तक इन पक्षकारों ने सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराये हैं और इस पर विश्वास वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से किया गया है।
- द. वर्तमान सब्सिडीरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2018 (12 महीने) तक है। हालांकि, क्षति की जांच की अवधि को 2014-15, 2015-16, 2016-17 से तथा जांच की अवधि तक की अवधि के रूप में माना गया है।
- ध. इस नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी दिया कि वे दिनांक 15 फरवरी, 2019 को हुई सुनवाई में अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करें। उन सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये इन विचारों को लिखित निवेदनों के रूप में प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की प्रतियां प्राप्त करें और उनके खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।
- न. इन हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए लिखित निवेदनों/ प्रति उत्तरों में दिये गये तर्कों पर उस सीमा तक वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है जिस सीमा तक उसे वर्तमान उद्देश्यों से संगत और आवश्यक माना गया।
- प. जहां भी संगत पाया गया, इस जांच की अवधि के दौरान इन हितबद्ध पक्षकारों किये गये निवेदनों का निवारण प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।
- फ. इन हितबद्ध पक्षकारों गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की उपयुक्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक हुआ प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न किये गये के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।
- ब. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा इस जांच में काफी हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम में दर्ज किया है।
- भ. प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों को 19 जुलाई, 2019 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य निहित थे और प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 27 जुलाई, 2019 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनिमय दर यू एस डॉलर 1 = 65.33 है।

- ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**
4. जांच शुरूआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को “वेल्ड किया हुआ स्टेनलैस स्टील पाइप और ट्यूब” के रूप में परिभाषित किया गया था।
- ग. 1. घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन**
5. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किये गये अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :
- क. विचाराधीन उत्पाद “वेल्ड किया हुआ स्टेनसैल स्टील पाइप एंड ट्यूब” है। विचाराधीन उत्पाद व्यापक तौर पर या तो 200 सीरिज अथवा 300 सीरिज के स्टील (यद्यपि 400 सीरिज के पाइप के लिए भी कुछ बाजार है) से बनाया जाता है और स्टील के विभिन्न सीरिजों के बनाये गये पाइपों की कीमत काफी हद तक अलग अलग होती है।
  - ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और उन वस्तुओं जिनका आयात किया गया है समान वस्तु हैं।
  - ग. पी सी एन-वार आंकड़ों का उपयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमत में बहुत अधिक अंतर है।
  - घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस आरोप की याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाव दिये गये पी सी एन - पद्धति त्रुटिपूर्ण थी, के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि उपयोग किये गये स्टील के सीरिजों के आधार पर कच्चे माल की लागत काफी हद तक अलग होती है और परिवर्तन लागत कुल लागत का केवल 10 से 12 प्रतिशत होता है। इसके अलावा, उत्तर देने वाले निर्यातकों ने यह नहीं दर्शाया है कि उपयोग किये गये स्टील में अंतर के कारण लागत और कीमत की संरचनाओं में कोई अंतर नहीं है।
  - इ. 200 सीरिजों के संबद्ध वस्तुओं का मुख्य रूप से उपयोग अलंकारी उद्देश्यों से किया जाता है, 300 सीरिजों के संबद्ध वस्तुओं का मुख्य रूप से उपयोग औद्योगिक और संरचनात्मक उद्देश्यों से किया जाता है जबकि 400 सीरिज के संबद्ध वस्तुओं का उपयोग निकास नलियों के लिए किया जाता है। हालांकि, ट्यूब और पाइप के बीच कीमत में अंतर इसके प्रयोग के कारण नहीं बल्कि उपयोग किये गये स्टील की श्रेणी के कारण किया जाता है।
  - ज. औद्योगिक प्रकारों उप प्रकारों के संबंध में तर्कों का उत्तर देते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि विभिन्न प्रयोगों के उद्देश्य से इन पाइपों के बीच वास्तव में कोई बहुत अधिक कीमत और लागत का अंतर नहीं है।
  - झ. इस तर्क के संबंध में कि केवल मैसर्स तरनामणि मेटल्स और ट्यूब लिमि. औद्योगिक पाइपों के उत्पादन में लगा हुआ है, यह अनुरोध किया जाता है कि अन्य उत्पादकों जैसे हिसार स्टील्स प्रा. लिमि., सुमन स्टील इंड., पारस भवानी स्टील प्रा. लिमि., पी एस राज स्टील्स प्रा. लिमि. आदि भी इस उत्पाद का उत्पादन करते हैं।
  - ज. आयातक के इस तर्क के संबंध में कि वियतनाम से संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता घरेलू स्तर पर उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता से बेहतर है। यह अनुरोध किया जाता है कि भारतीय उत्पादक वी आई एस मानकों के इनपुट का उपयोग करते हैं जबकि वियतनाम के उत्पादक चीन से इनपुट की खरीद करते हैं। इसके साथ ही, वियतनाम के उत्पादक “मेक इन इंडिया” टैग के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं की विक्री कर रहे हैं जो अपने आप में यह दर्शाता है कि उनका उत्पाद भारतीय निर्माताओं के उत्पाद से श्रेष्ठतर नहीं है।
  - झ. इस तर्क का उत्तर देते हुए कि वियतनाम में निर्मित उत्पादों का रेंज भारत में उपलब्ध नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि भारतीय निर्माताओं ने विभिन्न श्रेणियों स्टेनलैस स्टील का उपयोग करते हुए विभिन्न आकारों अथवा मोटाई के संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। किसी भी स्थिति में, विभिन्न आकारों के पाइपों और ट्यूबों को छोटे-मोटे रिटूलिंग के साथ उसी मशीनों पर बनाया जा सकता है।

## ग. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं -
- क. वियतनाम में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद धातु शोधन और परिकरण के मामले में बहुत अधिक अच्छी गुणवत्ता का है।
  - ख. वियतनाम के उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों की रेंज भारत में उपलब्ध नहीं है। उच्च आकारों और माप के पाइपों और ट्यूबों का निर्माण घरेलू उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है और यदि उसका निर्माण किया भी जाता है तब लागतों पर रोक लगी रहती है।
  - ग. भारत में उत्पादित वस्तुओं की नाप में बहुत अंतर होता है जो अंततः इसके उपयोग को हानि पहुंचाता है।
  - घ. चूंकि प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के संबंध में और न कि पी सी एन के आधार पर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना की मांग की है, पी सी एन आधारी पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की कोई संगतता नहीं है।
  - ड. 200 सीरिज और 300 सीरिज के अंतर्गत उप श्रेणी बनाये जाने के लिए अपनाई गई पद्धति त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह लागत और कीमत में अंतरों के कारण उत्पाद उप श्रेणियों में अंतर को प्राप्त नहीं करती है।
  - च. भारत में और पूरे विश्व में, स्टेनलैस स्टील पाइपों का मौटे पर तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है अर्थात् (क) अलंकारित और संरचनात्मक ट्यूब, (ख) निकास ट्यूब, और (ग) औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ट्यूब और पाइप।
  - छ. औद्योगिक ट्यूब और पाइप के लिए बाजार को आगे (क) यंत्रीकरण और द्रव चालित ट्यूब, (ख) हीट एक्सचेंजर ट्यूब, (ग) स्वास्थ्यकर ट्यूब, (घ) यांत्रिक ट्यूब, (ड) प्रोसेज पाइप और (च) ट्यूब और पाइप में बांटा जा सकता है जिसका उपयोग भट्टी, हिटर, ऐयरकूलर, कंडेन्सर और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के संघटक के रूप में किया जाता है।
  - ज. पी सी एन सभी हितबद्ध पक्षकारों को उचित अवसर देने के बाद और तीन व्यापक श्रेणियों अर्थात् (क) अलंकारित और संरचनात्मक ट्यूब, (ख) निकास ट्यूब और (ग) औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ट्यूब और पाइप के आधार पर तय किया जा सकता है।
  - झ. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र का चार संघों पर विचार करते हुए गलत तरीके से निर्धारण किया गया है जो अपने आप में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में नहीं लगे हुए हैं। केवल उन उत्पादकों को घरेलू उद्योग और न कि संघों के रूप में माना जा सकता है।

## ग. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु जिसकी पेशकश घरेलू उद्योग द्वारा की गई है, के कार्यक्षेत्र के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों को नोट किया है।
8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जिसे जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में परिभाषित किया गया है “वेल्ड किया हुआ स्टेनलैस स्टील पाइप और ट्यूब” है। वेल्ड किये हुए पाइप और ट्यूब के लिए इनपुट सामग्री स्टेनसैल स्टील की शीट/स्केल्प/क्वाइल/प्लेट्स हैं जिसे अपेक्षित आकार में बनाया जाता है और जिसे उपयुक्त वेल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से वेल्ड किया जाता है। पाइप और ट्यूब आमतौर पर समान उत्पादन प्रक्रिया से बनाये जाते हैं। इसके अलावा, आवश्यकता के आधार पर शीट/स्केल्प/क्वाइल/प्लेट्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं।
9. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग अलंकारी उद्देश्यों, औद्योगिक और संरचनात्मक उद्देश्यों से तथा निकास नलियों में किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 73 के अंतर्गत किया जाता है और आगे उसका वर्गीकरण सीमा शुल्क उपशीर्ष 73064000, 73066100, 73066900, 73061100

और 7306210 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. प्राधिकारी ने पी सी एन का प्रस्ताव किया है और दिनांक 6 मार्च, 2019 के पत्र के संदर्भ में पी सी एन पद्धति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां प्राप्त करने और उसका मूल्यांकन करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 14 मार्च, 2019 के पत्र के संदर्भ में प्राधिकारी द्वारा तय किये गये पी सी एन की सूचना दी। अपनाई गई पी सी एन पद्धति इस कारण से उपयोग की गई स्टील की श्रेणी पर आधारित है कि संबंधित वस्तुओं की लागत और कीमत पर व्यापक रूप से उपयोग किये गये कच्चे माल की लागत का प्रभाव पड़ता है। तदनुसार, अपनाई गई पी सी एन पद्धति नीचे दिये गये अनुसार है :
  - क. 200 सीरिज के स्टेनलैस स्टील का पाइप और ठूब
  - ख. 300 सीरिज के स्टेनलैस स्टील का पाइप और ठूब
  - ग. 400 सीरिज के स्टेनलैस स्टील का पाइप और ठूब
11. प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं की तुलना विशेषताओं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वस्तुओं का वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग से उसकी खरीद भी की है।
12. संबद्ध वस्तुओं और समान वस्तुओं जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है कि गुणवत्ता के संबंध में तर्कों के बारे में, यह नोट किया जाता है कि जबकि आयातकों ने घरेलू और आयात किये गये उत्पाद में अंतरों का आरोप लगाया है, विदेशी उत्पादकों ने ऐसी कोई चिंता व्यक्त नहीं की है। गुणवत्ता में अंतरों का आरोप लगाते समय आयातकों ने आयात किये गये और घरेलू स्तर पर उत्पादन किये गये वस्तुओं की गुणवत्ता में अंतरों को दर्शनी के लिए सत्यापन योग्य सूचना और साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये हैं। आयातक ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यह वी आई एस मानकों के स्टील का उपयोग करता है। इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं और उन वस्तुओं जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग किया जाता है के बीच निष्पक्ष और उपर्युक्त तुलना करने के उद्देश्य से, पी सी एन पद्धति अपनाई गई है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आयात किये गये उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये वस्तुओं के बीच गुणवत्ता में किन्हीं अंतरों को दर्शाया नहीं गया है।
13. इस तर्क के संबंध में की घरेलू उद्योग उत्पाद के कार्यक्षेत्र में शामिल किये गये संबद्ध वस्तुओं के सभी प्रकारों, आकार और मोटाई का उत्पादन नहीं करता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने किसी उत्पाद प्रकार का उल्लेख नहीं किया है जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया है और न ही यह दर्शनी के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद के किसी प्रकार अथवा आकार को उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। इस कारण से निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता है कि संबद्ध वस्तुओं के सभी प्रकारों, आकारों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।
14. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की गई समान वस्तु संबद्ध देशों आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
15. **घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और उसकी स्थिति**
- घ. 1. **घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**
15. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और उसकी स्थिति के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :

- क. यह याचिका चार संघों द्वारा दायर की गई थी। बारह उत्पादकों ने आवेदन के चरण में क्षति और लागत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई। जांच शुरूआत के पश्चात् और जांच शुरूआत के उत्तर में, दस और उत्पादकों ने अपनी लागत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है।
- ख. इन उत्पादकों ने जांच शुरूआत के बाद भाग लिया, के आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए। विगत में भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन उत्पादकों को जोड़ा है जिन्होंने घरेलू उद्योग के भाग के रूप में जांच आंरभन के पश्चात संगत सूचना उपलब्ध कराई है।
- ग. चूंकि यह याचिका चार संघों द्वारा दायर की गई है और विचाराधीन उत्पाद के सभी उत्पादक एक अथवा दूसरे संघ के सदस्य हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए कि आवेदन “घरेलू उद्योग की ओर” दिया गया है और इसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया है जिसका सामूहिक उत्पादन कुल उत्पादन के पांच प्रतिशत से अधिक होता है।
- घ. भाग लेने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है।
- ड. चूंकि कुल उत्पादन के संबंध में सार्वजनिक तौर पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और यह उद्योग व्यापक स्तर पर एम एस ई क्षेत्र से संबंधित है, अतः जांच की अवधि में उत्पादन पर बाजार में कच्चे माल की आपूर्ति के आधार पर विचार किया गया है।
- च. याचिकाकर्ताओं ने आर टी आई के अंतर्गत सांखिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से सूचना मांगी थी। हालांकि, मंत्रालय ने संगत सूचना के मौजूद न होने का उल्लेख किया है।
- छ. चूंकि मैसर्स जिंदल स्टेनलैस भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कच्चे माल का बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। यह कंपनी इस देश में विभिन्न उत्पादकों द्वारा बाजार के आकार और उत्पादन पर विस्तृत अनुसंधान करती है और भारत में कच्चे माल की खपत पर नजर रखती है क्योंकि इसकी विपणन आवश्यकता और उसका उपयोग भारतीय उत्पादन को सथापित करने के लिए किया जा सकता है।
- ज. सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर बनाम जी. एम. एक्सपोर्ट ने उच्चतम न्यायालय से निर्णय के बाद प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली का नियम 2(ब) को ए एस सी एम के अनुच्छेद 16.1 के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा के साथ सुसंगत रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस कारण से नियम 2(ब) में उपयोग किये गये शब्द “गा” की व्याख्या ए एस सी एम के प्रावधानों के अनुरूप “सकता” है, को समझने के लिए किया जाना चाहिए। तदनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ उन उत्पादकों जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, को वर्तमान उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में मानने का अधिकार है। इस प्रकार के उत्पादकों को स्वतः बाहर नहीं किया जाना चाहिए। कुछ घरेलू उत्पादकों के मध्यम आकार की कंपनी होने के कारण कुछ घरेलू उत्पादक घोटा/हानि वाली कीमतों उत्पादन क्रियाकलाप जारी रखने की स्थिति में नहीं थे और वे घरेलू और आयात किये गये उत्पाद के बीच बहुत अधिक कीमत अंतर के कारण आयात करने के लिए बाध्य थे। घरेलू और आयात किये गये उत्पाद के बीच बहुत अधिक कीमत अंतर के कारण ये उत्पादक अपनी उत्पादन सुविधाओं को निपक्ष रखने और बदले में उक्त उत्पाद का आयात करने के लिए बाध्य हुए जो अपने आप में उस क्षति का साक्ष्य है जो इन आयातों के कारण हो रही है।
- झ. यदि घरेलू उत्पादक जिन्होंने संबंध वस्तुओं का आयात किया है, को अपात्र घरेलू उद्योग मान भी लिया जाता है तब भाग लेने वाले शेष उत्पादक का घरेलू उत्पादन में एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा।
- ज. भाग लेने वाले घरेलू उत्पादकों का बहुत बड़ा हिस्सा है चाहे आयात करने के बाले उत्पादकों को पात्र अथवा अपात्र घरेलू उद्योग माना गया हो।
- ट. इस तर्क के उत्तर में की घरेलू उद्योग ने आयातकों के संबंध में कोई घोषणा की है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी उत्पादकों जिन्होंने याचिका में आंकड़े उपलब्ध कराये थे, ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

- ठ. अन्य उत्पादकों के लिए भाग लेने वाले घरेलू उत्पादकों के हिस्से में वृत्रि होती है यदि उन उत्पादकों जिन्होंने आयात किया है, को बाहर रखा जाता है और आयातों के तथ्य की सूचना नहीं देकर याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया जाना था। हालांकि, याचिकाकर्ता का यह भी स्वार्थ है कि उन उत्पादकों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये आयात आवश्यकता के आधार पर किये गये थे।
- ड. इस तर्क के उत्तर में की संघ के सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई थी, यह दर्शाया गया था कि उसे उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि सदस्यों की सूची इसका उल्लेख किये जाने पर उपलब्ध कराई गई थी।
- ढ. इस तर्क के उत्तर में कि 22 कंपनियों के ब्यौरे गोपनीय रहते हैं, यह अनुरोध किया जाता है कि लागत संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत करने वाले पत्रों का अगोपनीय पाठ निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल का हिस्सा था और इस प्रकार से कंपनियों के ब्यौरे की जानकारी सभी पक्षकारों थी।
- ण. इस तर्क के उत्तर में कि ये संघ घरेलू उत्पादक नहीं हैं, यह अनुरोध किया जाता है कि यह संघ केवल याचिकाकर्ता हैं और न कि घरेलू उद्योग। नियम 6(1) के अंतर्गत, आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जा सकता है।
- त. विरोधी पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने किसी उत्पादक को आयातों के कारण बाहर नहीं रखा था और इस स्थिति का निर्धारण सकल भारतीय उत्पादन के आधार पर किया गया था।
- थ. जबकि निर्यातिक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस आवेदन में दिये गये कुल घरेलू उत्पादन के अनुमानों पर प्रश्न उठाया है, इनमें से कोई भी पक्षकार घरेलू उत्पादन के ठोस साक्ष्य और दावे के साथ इन अनुमानों को खंडन नहीं कर पाया है।
- द. इस तर्क में कोई दम नहीं है कि जब घरेलू उद्योग का निर्धारण कुल घरेलू उत्पादन से बड़े अनुपात के आधार पर किया जाता है तब आयातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन को बाहर नहीं रखा जा सकता है और न ही किसी भी प्रकार से इस नियमावली में ऐसा प्रावधान है कि यदि आयात करने वाले उत्पादकों को बाहर रखा जाता है तब शेष सभी घरेलू उत्पादकों पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि इन निर्यातिकों द्वारा तर्क दिया गया है।
- ध. इन हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत मैसर्स मावन स्टेनलैस ने निर्धारित समय के भीतर अर्थात् 23 अक्टूबर, 2018 को अपने आंकड़े प्रस्तुत किये थे।

## घ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन

16. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और स्थिति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :
- क. इस तथ्य को मानने के बावजूद कि आवेदकों के पास संबद्ध वस्तुओं के आयातकों के संबंध में कोई सूचना नहीं है, उन्होंने आयात करने के बहाने बड़ी संख्या में उत्पादकों को बाहर रखा है।
- ख. जिंदल सर्विसिस कोरपोरेट मेनेजमेंट सर्विसिस प्रा. लिमि. केवल जिंदल स्टेनलैस ग्रुप कंपनी के आंतरिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है और संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन के संबंध में कोई सूचना नहीं रखता है।
- ग. चूंकि काफी संख्या में उत्पादक एम एस ईम ई क्षेत्र से संबंधित हैं अतः उत्पादन के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके फलस्वरूप 25 प्रतिशत के मानदंड के मूल्यांकन में कोई दम नहीं है।
- घ. भारत में घरेलू उत्पादन के संबंध में सूचना देने की जिम्मेदारी आवेदकों की होती है और वह कंपनी जो इस प्रकार की सूचना संग्रह करने के कार्य में नहीं लगी हुई है, द्वारा एकमात्र रिपोर्ट पर तब तक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसकी समीक्षा करने और उसे गलत साबित करने का अवसर सभी पक्षकारों को नहीं दिया जाता है।

- ड. चीन के मामले में पैनल की रिपोर्ट – पाटनरोधी और संयुक्त राज्य से ब्रायरल उत्पादों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क राशि और डी जी टी आर के एस ओ पी के मैनुअल में घरेलू उत्पादन को सिद्ध करने के महत्व को दर्शाया गया है। उन मामलों में जहां भारी संख्या में उत्पादक एम एस एम ई क्षेत्र से हैं, विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का सत्यापन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
- च. सभी आवेदकों में से, केवल मैसर्स रतनमणि मेटल्स एंड स्ट्रूब लिमि. जो एक आयातक भी है, औद्योगिक पाइपों के उत्पादन में लगा हुआ है। चूंकि कोई भी अन्य आवेदक औद्योगिक पाइपों के उत्पादन में नहीं लगे हुए हैं अतः उन्हें विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिए।
- छ. घरेलू उद्योग (क) संपूर्ण रूप में घरेलू उत्पादक, (ख) घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा और (ग) संबद्ध वस्तुओं के आयातकों को छोड़कर घरेलू उत्पादक का निर्धारण करने के लिए तीन पद्धतियां हैं। जब घरेलू उद्योग को कुल घरेलू उत्पादन से बड़े हिस्से के अनुसार परिभाषित किया गया है तब आयाताकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन को बाहर नहीं रखा जा सकता है। तीसरी पद्धति के अंतर्गत, किसी भी उत्पादक को बाहर नहीं रखा जा सकता है यदि उन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया हो।
- ज. चूंकि मैसर्स रतनमणि मेटल्स एंड स्ट्रूब लिमि. ने यह माना है कि इसने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, आवेदकों को असहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए।
- झ. प्राधिकारी ने उन आंकड़ों को रिकार्ड पर लिया है जिन्हें 23 अक्टूबर, 2018 की अंतिम समय सीमा का उल्लंघन करते हुए बाद के चरण में मैसर्स मावन स्टेनलैस द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- ञ. क्योंकि अनेक उत्पादक अब आयातक हो गये हैं अतः आवेदक घरेलू उद्योग के संघटकों को संशोधित करने की मांग करेंगे और आयात करने वाले उत्पादकों को अन्य अतिरिक्त उत्पादकों से प्रतिस्थापित करने की मांग करेंगे। प्राधिकारी को आवेदकों को उनकी सुविधा के अनुसार सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- ट. याचिका यह दर्शाती है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के काफी संख्या में उत्पादक भी आयात कर रहे हैं।
- ठ. रतनमणि को एक घरेलू उत्पादक के रूप में और आयातकों की सूची में भी शामिल किया गया है।
- ड. नियम 2(ख) में “गा” शब्द के उपयोग का यह आशय है कि प्राधिकारी का इस उत्पादक को बाहर करने के संबंध कोई अधिकार नहीं है जिसमें संबद्ध वस्तुओं का आयात किया।
- ढ. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से उनके द्वारा अथवा उनके सहयोगी पक्षकारों द्वारा आयातों के बारे में घोषणा नहीं की है।
- ण. याचिकाकर्ताओं ने क्षमता, अन्य भारतीय उत्पादकों के लिए उत्पादन जैसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। उनके न होने से, घरेलू उद्योग होने के उनके दावे का सत्यापन नहीं किया जा सकता है।

### घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-
- “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाठित वस्तु के नियर्तकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”
18. भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के निम्नलिखित संघों द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर की गई है

- i. स्टेनलैस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैनिफेक्चर एसो., नई दिल्ली,
- ii. स्टेनलैस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैनिफेक्चर्स एसो., अहमदाबाद,
- iii. साउथ इण्डिया स्टेनलैस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैनिफेक्चर एसो.,
- iv. हरियाणा स्टेनलैस स्टील पाइप एंड ट्यूब मैनिफेक्चर एसो।
19. याचिका के चरण में, उपर्युक्त संघों के सदस्य होने के नाते बाहर (12) घरेलू उत्पादकों ने संगत क्षति संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और लागत से संबंधित अपेक्षित सूचना दी है। जांच की शुरूआत के पश्चात्, भारत में संबद्ध वस्तुओं के 10 (10) और उत्पादकों ने इसका उत्तर दिया है और लागत संबंधी सूचना के साथ क्षति से संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराया है। इन उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सभी हितवद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।
20. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी सूचना के न होने पर, याचिकाकर्ताओं ने भारत में कच्चे माल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाया है। विरोधी पक्षकारों ने घरेलू उत्पादन का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार के दृष्टिकोण/ पद्धति के उपयोग का प्रतिवाद किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान उद्योग एम एस ई क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद में वाणिज्यिक लेन देन के लिए उपयोग की गई माप की इकाई मानक इकाई नहीं है और यह या तो लंबाई अथवा संख्या अथवा वजन के मामले में हो सकता है। आवेदक ने अनुरोध किया कि इन कारणों से, प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की तुलना करने के बाद पात्र भारतीय उत्पादक की मात्रा निर्धारित संभव नहीं था।
21. चूंकि भारतीय उत्पादन के संबंध में कोई ठोस सूचना संकलित नहीं की गई है और न ही यह इन संघों अथवा किसी अन्य एजेंसी के पास उपलब्ध है जिसे सार्वजनिक सूचना के रूप में इन संघों द्वारा प्राप्त किया जायेगा; वर्तमान मामले के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना का सहारा लेना तर्कसंगत और उचित है। उद्योग के अलग अलग टुकड़ों में बटे होने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने में आने वाली दिक्कतों की सही रूप में पहचान कर ली गई है। जबकि, इन हितवद्ध पक्षकारों ने जिंदल स्टेनलैस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के उपयोग पर आपत्ति की है। अतः यह नोट किया जाता है कि इन हितवद्ध पक्षकारों ने यह दर्शनी के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि निर्धारित किये गये घरेलू उत्पादन को कम करके बताया गया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान मामले जैसे तथ्यों और परिस्थितियों में घरेलू उत्पादन की मात्रा का निर्धारण उस आधार पर किया जा सकता है तो भारत में कच्चे माल की खपत हो सकती है। चूंकि मैसर्स जिंदल स्टेनलैस इस देश में कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और इसका भारतीय उत्पादन का पता लगाने में सीधा हित है, अतः भारतीय उत्पादन के संबंध में इसकी सूचना संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का एक विश्वसनीय अनुमान है। उक्त स्टील खपत के आधार पर, घरेलू उत्पादन का अनुमान 1,60,000 मी. ट. से 1,70,000 मी. ट. के बीच लगाया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कुल घरेलू उत्पादन के रूप में इन दोनों की औसत 1,65,000 मी. ट. को माना है।
22. यह स्पष्ट किया जाता है कि कच्चे माल के उत्पादक द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना अपनी ही विक्री तक सीमित नहीं है। उक्त सूचना सकल भारतीय उत्पादन पर आधारित है। केवल इस कारण से कि सूचना कच्चे माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई है, का आशय यह नहीं होता है कि वह केवल उस पक्षकार के उत्पादन और विक्री से संबंधित है। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सूचना भाग लेने वाली कंपनियों के उत्पादन, विक्री और क्षति संबंधी अन्य आंकड़ों पर आधारित है।
23. हितवद्ध पक्षकारों ने अतिरिक्त 10 उत्पादकों जिन्होंने जांच शुरूआत पश्चात् क्षति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, का विरोध किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि निम्नलिखित कारणों से निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र के भीतर इन कंपनियों को शामिल करना उपयुक्त होगा।
- क. एक ओर, हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का आकार छोटा है जबकि दूसरी ओर हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि और अधिक उत्पादकों की सूचना को जांच शुरूआत के पश्चात्

नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी है। इसके विपरीत जांच में अपेक्षाकृत अधिक भागेदारी के फलस्वरूप और अधिक निरूपत आंकड़े आयेंगे और जांच की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित होगा।

- ख. ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण रूप में घरेलू उत्पादकों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है, नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे उन उत्पादकों पर विचार करें जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
- ग. यूरोपीय समुदाय में अपीलीय निकाय – चीन से कुछ लौह एवं इस्पात फास्टनर पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क में अपीलीय निकाय (डब्ल्यू टी/ डी एस397/एबी/आर) ने यह टिप्पणी की कि घरेलू उद्योग को उस प्रकार से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे कि क्षति के विश्लेषण में गलतबयानी के खतरे को कम किया जा सके। इस प्रकार से यह इस तथ्य को अनुपालन करता है कि भाग लेने वाले उत्पादकों का हिस्सा जितना अधिक होगा क्षति के निर्धारण में गलतबयानी की संभावना उतनी ही कम होगी।
- घ. इनके अतिरिक्त घरेलू उत्पादकों को शामिल करने से केवल यह सुनिश्चित होता है कि घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र संपूर्ण रूप में घरेलू उत्पादकों का निरूपक है।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, समेकित क्षति सूचना का अगोपनीय पाठ मौखिक सुनवाई के समक्ष हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया था। वास्तव में निर्धारित मौखिक सुनवाई इन हितबद्ध पक्षकारों को अपने आप को उपयुक्त रूप से और समुचित रूप से बचाव करने के लिए भी अनुमति देने हेतु स्थगित की गयी थी। इस कारण से हितबद्ध पक्षकारों को सूचना के संबंध में टिप्पणी करने और अपने हित की रक्षा करने के लिए उचित अवसर मिल गया।
- च. घरेलू उत्पादकों ने उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के सत्यापन के लिए सहमति दी और उनकी सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया, जिसे सार्वजनिक फाइल में रखा गया था। तदनुसार, फाइल की गई सूचना का उचित सत्यापन के पश्चात इसको स्वीकार किया गया है।  
पूर्व में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच के आरंभ होने के बाद 10 उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों पर विचार किया है।
- 24. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इस जांच में भाग लेने वाले कुछ घरेलू उत्पादकों ने सबद्ध वस्तुओं का आयात भारत में किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अनेक उत्पादक विचाराधीन उत्पादक के आयातक हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया है कि कुछ आयात कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा अपने स्वयं के नाम पर आयात करने की बजाय कुछ सहयोगी कंपनियों के माध्यम से किया होगा। इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई है। डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किये गये आयात संबंधी आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया है। प्राधिकारी ने इस तथ्य का पता लगाने के लिए कि क्या उनमें से किसी ने इस उत्पाद का आयात किया है, डी जी सी आई एंड एस ने याचिकाकर्ताओं के नामों की जांच की है। यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादकों में से तीन उत्पादक अर्थात् मैसर्स रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब लिमि., मैसर्स क्वालिटी स्टेनलैस प्रा. लिमि. और मैसर्स ए एस बी ट्यूब्स ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है।
- 25. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी को इस उत्पाद का आयात करने वाले घरेलू उत्पादक को पात्र स्वदेशी उद्योग के रूप में विचार करना चाहिए। हालांकि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानते हैं कि सी वी डी नियमावली की भाषा पर विचार करते हुए, यदि इस प्रकार के उत्पादक अपने आप में संबद्ध वस्तुओं के एक आयातक अथवा आयातक से संबंधित अथवा निर्यातक हों तब घरेलू उत्पादक को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानना उपयुक्त नहीं होगा। उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि मैसर्स रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब लिमि., मैसर्स क्वालिटी स्टेनलैस प्रा. लिमि. और मैसर्स ए एस बी ट्यूब्स को पात्र घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- 26. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर घरेलू उत्पादकों को बाहर रखा है कि वे संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं। इसके उत्तर में, याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उत्पादक को स्थिति सिद्ध करते समय घरेलू उत्पादन से बाहर नहीं रखा गया है। 1,65,000 मी. ट. के उत्पादन पर ऊपर में उल्लेख किये

गये कारणों से सकल घरेलू उत्पादन के रूप में विचार किया गया है और उस पर वर्तमान मामले में स्थिति को सिद्ध करने के लिए विचार किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादकों, जिन्हें संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जाना पाया गया है, के उत्पादन को अब इस नियमावली के अंतर्गत यथाअपेक्षित स्थिति के निर्धारण के लिए याचिकाकर्ताओं के कुल पात्र घरेलू उत्पादन और पात्र उत्पादन से बाहर रखा गया है।

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान में 19 पात्र याचिकाकर्ता कंपनियों का कुल उत्पादन का 49.44 प्रतिशत है। आगे यह नोट किया जाता है कि जांच के आरंभ किये जाने के पश्चात् संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाली 86 और प्रतिष्ठानों/ कंपनियों में इस याचिका के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया है। किसी घरेलू उत्पादक द्वारा इस याचिका का कोई विरोध नहीं किया गया है। इस कारण से सी वी डी नियमावली के मामले में घरेलू उद्योग की स्थिति की आवश्यकता पूरी कर ली गई है। आगे यह नोट किया जाता है कि जांच शुरूआत के समय 12 याचिकाकर्ता कंपनियों के साथ भी स्थिति की आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
28. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि भाग लेने वाले पात्र घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के आशय से यह घरेलू उद्योग है।

#### **ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**

##### **ड. 1. घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन**

29. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :
- क. भाग लेने वाले निर्यातकों ने नियम 8 के प्रावधानों, गोपनीयता से संबंधित प्रथा और व्यापार सूचना का उल्लंघन किया है।
  - ख. इस उत्तर का अगोपनीय पाठ गोपनीय सूचना को उचित रूप से समझने की अनुमति नहीं देता है और निर्यातकों ने एक अगोपनीय सार उपलब्ध नहीं कराने के लिए कोई कारण नहीं दिये हैं।
  - ग. निर्यातकों ने इन उत्तरों के अगोपनीय पाठ से कुछ तथ्यों को पूर्ण रूप से विलोपित किया है।
  - घ. निर्यातकों ने उस सूचना का दावा किया है जो सार्वजनिक क्षेत्र में गोपनीय के रूप में आसानी से उपलब्ध है।
  - ड. इस आरोप के उत्तर में कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, यह अनुरोध किया गया था कि वास्तविक आधार पर और इसकी गोपनीयता के दावों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए अधिकांश आंकड़े व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुरूप है।
  - च. याचिकाकर्ताओं ने क्षति से संबंधित सभी मापदंडों की वास्तविक संख्या और प्रवृत्तियां उपलब्ध कराई हैं जो इस मामले के गुणों पर तर्क करने के लिए विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के लिए पर्याप्त हैं और संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों की तुलना में बहुत अधिक सूचना प्रकट की है।
  - छ. भाग लेने वाले उत्पादक की वार्षिक रिपोर्टें और लागत संबंधी प्रपत्रों ने इस प्रकार के उत्पादकों के उत्पादन, विक्री, विक्री की कीमत, विक्री की लागत, लाभ और निवेश पर आय की तुलना में व्यापार संवेदनशील सूचना है और इसे प्रकट नहीं किया जा सकता।
  - ज. जांच शुरूआत के पश्चात् अत्यतीत याचिका भी व्यापार सूचना संख्या 10/2018 को जारी किये जाने के पूर्व अर्थात् 23 अगस्त, 2018 को दायर किया गया था।

##### **ड. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन**

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :
- क. याचिकाकर्ता निर्यातकों से गोपनीय के रूप में सब्सिडी का आकलन नहीं कर सकते हैं।
  - ख. व्यापार सूचना 10/2018 के उल्लंघन में, याचिकाकर्ताओं ने (क) विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ घरेलू उत्पादकों के साथ याचिकाकर्ताओं का संबंध; (ख) सभी अन्य भारतीय उत्पादकों के नाम और पते; (ग)

घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य उपलब्ध कराने में असफल रहा है। घरेलू उद्योग ने वास्तविक अंकों में उपर्युक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

- ग. हितबद्ध पक्षकारों के बचाव के अधिकार का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि पर्याप्त आंकड़ों को इस याचिका में अगोपनीय पाठ में उचित रूप से अनुक्रमित नहीं किया गया है।
- घ. खंड VI में, अनुबंध 6 अथवा वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लिया गया है जिसे व्यापार संवेदनशील सूचना होने के आधार पर गोपनीय होने का दावा किया गया है।

### **छ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

31. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है :

“गोपनीय सूचना। (1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बाबजूद, नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संक्षेप संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक कराने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।”

32. प्राधिकारी ने निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

33. घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संगत मानी गई सीमा तक गोपनीयता के संबंध में किये गये निवेदनों की जांच प्राधिकारी द्वारा की गई थी और तदनुसार, उसका समाधान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न किया गया माना गया है। जहां भी संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के रूप में अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना का दावा किया है।

34. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में सब्सिडी के अपने आकलन को समुचित रूप से प्रकट किया है। कोई विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया है जहां याचिकाकर्ताओं ने किसी सूचना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रकट नहीं किया है। तब यह देखा गया है कि इन याचिकाकर्ताओं ने व्यापार सूचना 10/2018 के अंतर्गत निर्धारित संगत सूचना उपलब्ध कराई है। कोई विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया है जहां याचिकाकर्ताओं ने उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई सूचना को प्रकट नहीं किया है बल्कि वर्तमान याचिका में गोपनीय के रूप में

दावा किया। प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रकृति से लागत संबंधी सूचना गोपनीय है और इसका संक्षेपण नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को लागत संबंधी सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा करने के लिए सतत रूप से अनुमति देते रहे हैं क्योंकि इस सूचना को प्रकट करने से उन पक्षकारों के कानूनी अधिकारों को बहुत अधिक हानि हो सकती है।

### **च. विविध निवेदन**

#### **च. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन**

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

- क. वियतनाम से आयात (क) वस्तुओं की उत्कृष्ट गुणवत्ता, (ख) स्थाई कीमत, और (ग) स्थाई सुपुदर्गी समय सारणी के कारण आवश्यक हो गया है। दूसरी ओर घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तु संतोषजनक नहीं है, कीमतें स्थिर नहीं हैं और सुपुदर्गी त्रुटिपूर्ण है।
- ख. वह आधार जिस पर जांच आरंभ की गई है में कोई दम नहीं है क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि वियतनाम के निर्माता ने संबद्ध वस्तुओं में सब्सिडी दिया है।
- ग. इन वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता भारत में अपने कुल उत्पादन का केवल 15 से 20 प्रतिशत निर्यात करते हैं और वह भी उत्कृष्ट पाइपों के लिए अत्यधिक मांग को देखते हुए बार बार विश्वास दिलाये जाने के बाद निर्यात करते हैं।
- घ. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से इस ठोस संबंध को खतरा पहुंच सकता है जो वियतनाम और भारत के बीच पिछले 5 दशकों से चलता आ रहा है।
- ङ. मैसर्स रतनमणि मेटल्स एंड ट्यूब प्रा. लिमि, और अन्य घरेलू उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट के अगोपनीय पाठ को सार्वजनिक फाइल में ए एस सी एम के अनुच्छेद 12 और यूरोपीय यूनियन – पी ई टी (पाकिस्तान) में डब्ल्यू टी ओ के पैनल की रिपोर्ट के अनुसार रखा जाना चाहिए।

#### **च. 2. घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन**

36. घरेलू उत्पादकों के निवेदनों के उत्तर में, घरेलू उद्योग ने नीचे दिये गये अनुसार अनुरोध किया है :

- क. चूंकि अनेक उत्पादक एम एस एम ई क्षेत्र से संबंधित हैं और उसमें निहित मार्जिन मामूली है अतः उस उत्पादकों को आयात करने के लिए मजबूर किया गया है।
- ख. अपेक्षाकृत लघु अवधि में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर विचार करना मरम्मत करने के लिए कठिन होगा, इस शुल्क को भूत लक्षित प्रभाव से लगाये जाने की आवश्यकता है।
- ग. इस तर्के के संबंध में कि प्रतिसंतुलनकारी जांच वियतनाम के साथ अनुकूल संबंधों को क्षति पहुंचायेगी, यह अनुरोध किया जाता है कि ए एस सी एम के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत सरकार और वियतनाम सरकार दोनों प्रतिकारणीय सब्सिडी नहीं देने पर सहमत हुए हैं जो अन्य देश के उद्योग को क्षति पहुंचायेगा और अपने उद्योग को इस प्रकार की सब्सिडी से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आयात करने वाले देश के विशेषाधिकार को स्वीकार किया है।
- घ. इस बात की भी अवश्य जांच की जानी चाहिए कि वियतनाम से निर्यात रियायती सीमा शुल्क का दावा करने के लिए अपेक्षित मूल्यवर्धन की जांच से गुजर रहे हैं। कच्चे माल का आयात वियतनाम में किया जाता है और संबद्ध वस्तुओं को बनाने के लिए मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत से कम है जबकि ए आई एफ टी ए के अंतर्गत उत्पत्ति के नियम में 35 प्रतिशत का मूल्यवर्धन अपेक्षित है। हालांकि, संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत में वियतनाम के मूल रूप में किया जाता है।
- ङ. निर्यातक मूल्यवर्धन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप भारत सरकार को 125-150 करोड़ रुपए की हानि हो रही है।

- च. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध है, यह अनुरोध किया जाता है कि भारत में जनहित पर टिप्पणी करना वियतनाम सरकार का कार्य नहीं है। विदेशी उत्पादकों ने भारतीय घरेलू उद्योग को वास्तविक अति पहुंचाई है और उसका उत्तर वियतनाम सरकार द्वारा अवश्य ही दिया जाना चाहिए। यह शुल्क भारतीय और विदेशी दोनों आपूर्तिकर्ताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा और इससे संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा।
- छ. इस तर्क के संबंध में कि वियतनाम से आयात आवश्यक है, यह अनुरोध किया जाता है कि भारत में निर्मित संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन बी आई एस मानक के स्टेनलैस स्टील का उपयोग करते हुए किया जाता है और इस कारण से माप में अंतर के कारण अथवा किसी अन्य कारण से निम्नतर गुणवत्ता का प्रश्न नहीं उठता है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं का कीमत निर्धारण क्रोम, आयरन, निकल, कॉपर आदि की स्थानीय कीमतों पर निर्भर करता है और इस कारण से इसमें परिवर्तन हो सकता है। सुपुदर्भी समय सारणी के संबंध में यह अनुरोध किया गया था कि वियतनाम से भारत में पारगमन का समय उस समय से बहुत अधिक है जो इस अदेश को कार्यान्वित करने के लिए घरेलू उत्पादक द्वारा लिया जाता है।

### **च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

37. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क यदि उसे लगाया जाये वियतनाम से आयातों को नहीं रोकेगा बल्कि संबद्ध देशों कथित रूप से सभिसडीयुक्त आयातों द्वारा किये गये तोड़ मरोड़ को समाप्त करेगा।
38. वियतनाम से आयातों की बहुत अधिक मात्रा पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वियतनाम से निर्यातिक भारत में अपने उत्पादन का केवल एक मामूली हिस्से की आपूर्ति करते हैं।
39. इन देशों के बीच संबंधों पर शुल्क लगाये जाने के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक शुल्क आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ के सदस्य देश द्वारा पूरी जांच किये जाने के बाद ही लगाया जाता है। इस जांच को ए एस सी एम और घरेलू सभिसडीरोधी कानूनों के द्वारा विनियमित किया जाता है और इस कारण से यह निष्पक्ष प्रकृति का है। इस कारण से तमाम अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया कोई व्यापार उपचारात्मक शुल्क ए एस सी एम के अनुसार है और यह वैश्विक व्यापार के लिए डब्ल्यू टी ओ के नियमों की भावना के अनुरूप है।
40. सत्यापन रिपोर्ट के अगोपनीय पाठ के लिए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी प्रथा के रूप में सार्वजनिक फाइल में किसी हितबद्ध पक्षकार की सत्यापन रिपोर्ट को नहीं रखते हैं। इसके अलावा, सत्यापन रिपोर्ट इन आंकड़ों और सूचना जिसे पहले ही हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है की पुष्टि करने, समर्थन करने और प्रमाणित करने के लिए है। सत्यापन रिपोर्ट का उद्देश्य उस सूचना जिसका सत्यापन किया गया है और जिसका सत्यापन नहीं किया जा सकता है के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को अधिसूचित करना है।
41. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि वियतनाम से आपूर्ति किये गये वस्तु उत्पत्ति के नियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित मूल्यवर्धन के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, यह नोट किया जाता है कि आयात करते समय जांच करने की जिम्मेदारी सीमा शुल्क अधिकारियों की है और यह वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है।
- छ. **सभिसडी और सभिसडी मार्जिन का निर्धारण**
42. यह याचिका घरेलू उद्योग दायर की गई थी जिसने संबद्ध देशों में प्रतिकारिणीय सभिसडी के मौजूद होने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए अनुरोध किया कि किस प्रकार से इस याचिका में पहचान की गई प्रत्येक योजना को याचिका में निश्चित रूप से शामिल किया गया था और उसकी जांच की जानी अपेक्षित थी।
- क. **चीन के संबंध में सभिसडी जांच**
43. चीन की सरकार (जी ओ सी) को विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था जो नई दिल्ली में 27 जून, 2018 को आयोजित की गई थी।

44. इन योजनाओं जिसे याचिका में दिया गया है, के बारे में परामर्श और जांच किये जाने के बाद, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तीन कार्यक्रमों की पहचान की जिसमें जांच आवश्यक नहीं थी। इस कारण से इन कार्यक्रमों के संबंध में कोई जांच आरंभ नहीं की गई थी :

- i. कार्यक्रम सं. 1 : राज्य की प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि
- ii. कार्यक्रम सं. 13 : तदर्थ सब्सिडी
- iii. कार्यक्रम सं. 17 : पेंशन निधि अनुदान

45. प्राधिकारी ने निम्नलिखित सी वी डी कार्यक्रमों के लिए जांच आरंभ की जिसमें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को संभवतः प्रतिकारणीय लाभ मिला है।

#### I. अनुदान के रूप में कार्यक्रम

1. कार्यक्रम सं. 2 : प्रसिद्ध ब्राण्ड कार्यक्रम
2. कार्यक्रम सं. 3 : जियांशु प्रांत द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान
3. कार्यक्रम सं. 4 : पाटनरोधी जांच के लिए अनुदान
4. कार्यक्रम सं. 5 : सुपर स्टार उपक्रम अनुदान
5. कार्यक्रम सं. 6 : अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान
6. कार्यक्रम सं. 7 : नियर्ति सहायता अनुदान
7. कार्यक्रम सं. 8 : वायोशन स्टील को अनुदान
8. कार्यक्रम सं. 9 : शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए अनुदान
9. कार्यक्रम सं. 10 : गुआंगडॉग प्रांत में उद्योगों के बाहरी विस्तार के लिए निधि
10. कार्यक्रम सं. 11 : राजकोषीय और प्रौद्योगिकीय अभिनवता के लिए प्रांतीय निधि के माध्यम से दिया गया अनुदान।
11. कार्यक्रम सं. 12 : शॉगडॉग प्रांत को दिया गया विभिन्न अनुदान
  - क. कार्यक्रम सं. 12 (क) : प्रमुख उपक्रम प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए शॉगडॉग प्रांत की विशेष निधि
  - ख. कार्यक्रम सं. 12 (ख) : प्रमुख उर्जा बचत प्रौद्योगिकी से औद्योगिकीकरण के लिए शॉगडॉग प्रांत का अवार्ड निधि
  - ग. कार्यक्रम सं. 12 (ग) : शॉगडॉग प्रांत का पर्यावरणीय संरक्षण उद्योग अनुसंधान और विकास निधि
  - घ. कार्यक्रम सं. 12 (घ) : प्रमुख उद्योगों के संवर्धन के लिए शॉगडॉग प्रांत की निर्माण निधि
12. कार्यक्रम सं. 14 : हेबई प्रांत द्वारा दिया गया अनुदान
  - क. हेबई प्रांत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान
  - ख. शिजियाझुआंग सिटी सरकार एक्सपोर्ट अवार्ड
13. कार्यक्रम सं. 15 : फुयांग सिटी को किया गया विभिन्न अनुदान
  - क. करों में 10 मिलियन आर एम बी से अधिक का भुगतान करने वाले उपक्रमों के लिए अनुदान
  - ख. उप-संविदा सेवा कार्यक्रम के नियर्ति के अंतर्गत अनुदान
  - ग. उत्कृष्ट नये उत्पाद/ प्रौद्योगिकी अवार्ड के अंतर्गत अनुदान
  - घ. प्रमुख उद्योगों के लिए फुयांग सिटी सरकार से निवेश अनुदान

- ड. प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों को चलाने वाले उपकरणों के लिए अनुदान
- च. नियर्यात ऋण बीमा शुल्कों पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार का क्षतिपूर्ति अनुदान
- छ. इनिसियल पब्लिक ऑफरिंग (आई पी ओ) हांगज़ाऊ प्रीफेक्चर और फुयांग सिटी (झेजियांग प्रांत) और (अनहुई प्रांत) से अनुदान
14. कार्यक्रम सं. 16 : अनुदान – विदेशी व्यापार के स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधि
15. कार्यक्रम सं. 18 : प्रांतीय सरकार – उपकरण अनुदान
16. कार्यक्रम सं. 19 : ट्रेजरी बाण्ड ऋण अथवा अनुदान
17. कार्यक्रम सं. 20 : घरेलू और विदेशी मेले में भाग लेने के लिए झॉगशम इंटरप्राइजेज के लिए भत्ते का निधि प्रबंधन का अंतरिम उपाय
18. कार्यक्रम सं. 21 : नियर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
19. कार्यक्रम सं. 22 : उर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष निधि
20. कार्यक्रम सं. 23 : लघु और मध्यम आकार के उपकरणों की सहायता के लिए निधि
21. कार्यक्रम सं. 24 : तियाजिन बिनहाई न्यू एरिया एंड तियाजिन आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी अधिकार क्षेत्र में दी गई समिस्डी
22. कार्यक्रम सं. 25 : प्रमुख उद्योग और नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकियों का संवर्धन करने के लिए राज्य विशेष निधि
- II. नियर्यात वित्त पोषण और नियर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम**
23. कार्यक्रम सं. 26 : नियर्यात विक्रेता का ऋण
24. कार्यक्रम सं. 27 : नियर्यात क्रेता का ऋण
25. कार्यक्रम सं. 28 : राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य नियर्यात वित्त पोषण
- III. कर और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम**
26. कार्यक्रम सं. 29 : विदेशी लेखकों द्वारा एफ आई ई लाभ के फिर से निवेश के लिए आयकर वापसी
27. कार्यक्रम सं. 30 : 10 वर्षों से कम की अवधि तक चलने वाले निर्धारित उत्पादक एफ आई ई के लिए कम की हुई कर की दर
28. कार्यक्रम सं. 31 : उन्नत प्रौद्योगिकी एफ आई ई के लिए आयकर में कटौती
29. कार्यक्रम सं. 32 : एफ आई ई और विदेशी उपकरणों तथा कुछ घरेलू स्तर पर स्वामित्व वाली कंपनियों जिनकी इनमें अपनी स्थापना अथवा जगह है और जो घरेलू तौर पर उत्पादित उपकरण की खरीद करने के लिए व्यापार कार्य अथवा उत्पादन में लगे हुए हैं, के लिए अधिमान्य कर नीतियां
30. कार्यक्रम सं. 33 : अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्च की कटौती के लिए कर नीतियां
31. कार्यक्रम सं. 34 : एफ आई ई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां
32. कार्यक्रम सं. 35 : उन कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जिसकी पहचान उच्च और नये प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में की गई है, के लिए अधिमान्य कर नीतियां

33. कार्यक्रम सं. 36 : घरेलू तौर पर उत्पादन के लिए उपकरण की खरीद करने वाली एफ आई ई के लिए मूल्यवर्धित कर की वापसी
34. कार्यक्रम सं. 37 : केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायत
35. कार्यक्रम सं. 38 : व्यापक संसाधन उपयोग (विशेष कच्चा माल) में लगे हुए उपक्रमों के लिए आयकर रियायत
36. कार्यक्रम सं. 39 : विशेष उपकरण की खरीद के संबंध में कर ऋण
37. कार्यक्रम सं. 40 : तियानजिन पोर्ट फ्री ट्रेड जॉन ने आयकर की दर में कटौती के लिए उपक्रम
38. कार्यक्रम सं. 41 : घरेलू प्रौद्योगिकी नवीकरण में निवेश के लिए आयकर शुल्क
39. कार्यक्रम सं. 42 : उपक्रम आयकर कानून के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आयकर कटौती
40. कार्यक्रम सं. 43 : विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में स्थापित विदेशी निवेश वाले उपक्रम (एफ आई ई) के लिए अधिमान्य कर नीतियां
41. कार्यक्रम सं. 44 : पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपक्रमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति
42. कार्यक्रम सं. 45 : आयात किये गये उपकरण के लिए प्रशुल्क और मूल्यवर्धित कर में छूट
43. कार्यक्रम सं. 46 : एफ आई ई में अनुसंधान और विकास के लिए कर में छूट
44. कार्यक्रम सं. 47 : उन कंपनियों जो कम लाभ पर कार्य करते हैं, को उपलब्ध कर अधिमान्यता
45. कार्यक्रम सं. 48 : नियांत उन्मुख एफ आई ई के लिए कर में कटौती
46. कार्यक्रम सं. 49 : प्रौद्योगिकी अथवा ज्ञान संकेंद्रित एफ आई ई के लिए कर में कटौती
47. कार्यक्रम सं. 50 : विभिन्न स्थानीय कर छूट (शॉगडॉग प्रांत, चॉगकिंग सिटी, गुआंक्सी रिजिन झुआंग, कर विशेष लाभ केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों का विकास करने के लिए)
48. कार्यक्रम सं. 51 : केंद्रीय क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों पर कटौती
49. कार्यक्रम सं. 52 : उच्च प्रौद्योगिकी उपलब्धि वाणिज्यिकरण परियोजनाओं के लिए शंघाई नगर कर वापसी
50. कार्यक्रम सं. 53 : उत्पादक एफ आई ई के लिए स्थानीय आयकर और कटौती कार्यक्रम
51. कार्यक्रम सं. 54 : शंघाई के पुड़ौन क्षेत्र में स्थापित एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
52. कार्यक्रम सं. 55 : गुआंगडॉग और हाईनान टापू में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और/ अथवा कटौती
53. कार्यक्रम सं. 56 : इस्पात उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक पार्क
54. कार्यक्रम सं. 57 : मानशंग की अन्य कर सुविधा

#### **IV. वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम**

55. कार्यक्रम सं. 58 : समुचित और निष्पक्ष बाजार मूल्य प्रतिफल से कम के लिए बिजली का प्रावधान
56. कार्यक्रम सं. 59 : समुचित प्रतिफल से कम के लिए जल का प्रावधान

57. कार्यक्रम सं. 60 : एस ओ ई के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार
58. कार्यक्रम सं. 61 : समुचित प्रतिफल से कम के लिए इस्पात के स्क्रेप हेतु सरकारी प्रावधान
59. कार्यक्रम सं. 62 : समुचित प्रतिफल से कम के लिए कूकिंग कोयले का प्रावधान
60. कार्यक्रम सं. 63 : निष्पक्ष बाजार मूल्य से कम पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हॉट रोल्ड स्टील (एच आर एस)
61. कार्यक्रम सं. 64 : समुचित प्रतिफल से कम के लिए कोल्ड रोल्ड का प्रावधान
62. कार्यक्रम सं. 65 : निष्पक्ष बाजार मूल्य से कम पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कच्चा माल
63. कार्यक्रम सं. 66 : भूमि के उपयोग शुल्क, भूमि लगान दरों और भूमि खरीद की कीमतों में कटौती
64. कार्यक्रम सं. 67 : औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनियों के लिए प्रशासनिक शुल्क से छूट और एल टी ए आर के लिए भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान – कुछ औद्योगिक और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भूमि के उपयोग का इनकार
65. कार्यक्रम सं. 68 : कोक पर निर्यात संबंधी प्रतिबंध
66. कार्यक्रम सं. 69 : उत्सर्जन में कमी के लिए कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों को शंघाई नगर निगम सब्सिडी
67. कार्यक्रम सं. 70 : समुचित प्रतिफल से अधिक के लिए सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद

#### **V. अधिमान्य ऋण और सुधार के रूप में कार्यक्रम**

68. कार्यक्रम सं. 71 : ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए छूट
69. कार्यक्रम सं. 72 : नीतिगत ऋण
70. कार्यक्रम सं. 73 : एस ओ ई (राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम) के लिए अधिमान्य ऋण
71. कार्यक्रम सं. 74 : चीन सरकार द्वारा सुधार ऋण गारंटी
72. कार्यक्रम सं. 75 : चीन से आयात-निर्यात बैंक से वित्तपोषण करने वाला अधिमान्य निर्यात

#### **VI. इक्विटी सम्मिश्रण के रूप में कार्यक्रम**

73. कार्यक्रम सं. 76 : इक्विटी के बदले ऋण
74. कार्यक्रम सं. 77 : कर्ज माफी
75. कार्यक्रम सं. 78 : डीड कर
76. कार्यक्रम सं. 79 : योग्य स्थानीय उपक्रमों के बीच लाभांश में छूट
77. कार्यक्रम सं. 80 : भुगतान न किये गये लाभांश
78. कार्यक्रम सं. 81 : इक्विटी सम्मिश्रण
46. जांच शुरूआत के पश्चात, चीन की सरकार और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/ निर्यातकों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें और उन्हें इस प्रकार की सब्सिडी, यदि कोई

हो के मौजूद होने और उसकी मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए कथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था।

47. चीन की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। मैसर्स ब्रेजियांग जूली हाई टेक मेटल्स कं. लिमि. ("जूली हाई टेक") चीन का एक मात्र उत्पादक/ निर्यातक है, जिसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

### **घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन**

48. घरेलू उद्योग द्वारा इस याचिका में और वर्तमान जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं।
- i. संबद्ध देशों की सरकार विचाराधीन उत्पाद के अपने उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रतिबंधित अथवा कार्य योग्य सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। घरेलू उद्योग ने प्रथम दृष्टया विधान और नीति से संबंधित दस्तावेजों सहित ऐसी सब्सिडी योजनाओं के होने का साक्ष्य उपलब्ध कराया है।
  - ii. याचिकाकर्ता ने संगत कानूनों एवं विनियमों, डब्ल्यू टी ओ की रिपोर्टें, मीडिया रिपोर्टें, सरकारी रिपोर्टें, स्वतंत्र रिपोर्टें और अध्ययनों, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच अन्य जांच प्राधिकारी के निर्धारण जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं। याचिकाकर्ता ने विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक सूचना उपलब्ध कराई है।
  - iii. पहचान किये गये कार्यक्रमों में निम्नलिखित कारणों से प्रतिकारणीय सब्सिडी है :
    - क. सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान किया जाता है जहां सरकारी प्रथा में नियंत्रियों का सीधा अंतरण (अर्थात् अनुदान, ऋण और इक्रिटी डालना) शामिल है, सरकारी राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है परंतु उसका त्याग कर दिया गया है अथवा उसका संग्रहण नहीं किया गया है (अर्थात् कर ऋण जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन), सरकार सामान्य अवसंरचना को छोड़कर वस्तुओं अथवा सेवाएं उपलब्ध कराती है या वस्तुओं को खरीदती है।
    - ख. विचाराधीन उत्पाद के चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों को लाभ दिया जाता है; और
    - ग. यह कार्यक्रम भारतीय नियमावली और ए एस सी एम के आशय से विशिष्ट है।  - iv. संगत कानून एवं विनियम, डब्ल्यू टी ओ की रिपोर्ट, विभिन्न सरकारी रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट और स्वतंत्र अध्ययन एवं विश्लेषण, अपने सब्सिडीरोधी जांचों में अन्य जांच एंजेंसियों के जांच परिणाम स्पष्ट रूप से संबद्ध देशों में प्रतिकारणीय सब्सिडी कार्यक्रम के मौजूद होने का पर्याप्त साक्ष्य है। इन साक्ष्यों को सरकारों और संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।
  - v. "चीन जन. गण. राज्य की सरकार" में परिभाषित शब्द में सरकार के सभी स्तर अर्थात् संघीय, केंद्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय सरकार जैसे नगर अथवा शहर अथवा टाउनशिप की सरकारें, जैसे सभी स्तर शामिल हैं। ग्राम अथवा स्थानीय विधायिका, प्रशासनिक अथवा न्यायिक एंजेंसियों/ निकाय और राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम जो चीन की सकारार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं जो एस सी एम यथा परिभाषित शब्दावली के आधिकार से "सार्वजनिक निकाय" के रूप में कार्य करते हैं।
  - vi. उत्तर देने वाले निर्यातक ने शायद ही कथित योजनाओं में से प्राप्त लाभों के संबंध में कोई व्यौरा दिया है। इस कारण से चीन की सरकार द्वारा उत्तर न दिये जाने की स्थिति में इन योजनाओं की प्रतिकारणीयता को मान लिया जाना चाहिए।
  - vii. उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दायर की गई प्रश्नावली का उत्तर इस निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रश्नावली के प्रपत्र के अनुरूप नहीं है। उत्तर देने वाले निर्यातकों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है और प्रश्नावली का पूरा जवाब प्रस्तुत किया है।

- viii. यह जांच प्राधिकारी द्वारा सबिसडी कार्यक्रम की मौजूदगी और उसकी प्रकृति के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य की छानबीन के बाद ही आरंभ किया गया है।
- ix. याचिका में कानूनी आधार, योजना की प्रकृति, वित्तीय अंशदान और विशिष्टता, वे उपक्रम जो पात्र हैं और विशेष योजना के अंतर्गत जिन्होंने लाभ उठाया है, यह दर्शते हुए कि यह योजना वास्तव में मौजूद है और उसका निर्धारण निर्धारित किये गये सबिसडी मार्जिन के साथ प्रतिकारणीय के रूप में किया गया है अन्य जांच प्राधिकारियों का निर्णय और कोई अन्य वेव अनुसंधान के रूप में साक्ष्य निहित है।
- x. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा लाभ प्राप्त करने के संबंध में सूचना के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा पहचान की गई विभिन्न योजनाओं को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, (क) एकव्यापी कार्यक्रम, (ख) खंड विशिष्ट कार्यक्रम, (ग) क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम।
- xi. याचिकाकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को या तो विचाराधीन उत्पाद अथवा उपक्रम अथवा क्षेत्र जहां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले उपक्रम स्थित हैं, के साथ जोड़ने के उद्देश्य से पर्याप्त साक्ष्य दिये हैं। याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों के साथ इस कार्यक्रम को संबंधित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- xii. चीन की सरकार की योजनाओं के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने आगे नीचे दिये गये अनुसार अनुरोध किया है -
- (क) संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों को सरकारों के विभिन्न स्तरों के निम्नलिखित श्रेणियों जिसे छ: व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, के अंतर्गत प्रतिकारणीय सबिसडी प्राप्त हुई है। इन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न कार्यक्रमों का नीचे उल्लेख किया गया है :
- I. अनुदान
  - II. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण
  - III. कर और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन
  - IV. एल टी ए आर पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान
  - V. अधिमान्य ऋण और सुझाव
  - VI. इक्विटी डालना
- (ख) चूंकि चीन की सरकार ने न तो प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और न ही कथित सबिसडी कार्यक्रम के संबंध में कोई सार्थक सूचना उपलब्ध कराई है। अतः इन योजनाओं की प्रतिकारणीयता और कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। प्राधिकारी को प्रतिकूल अनुमान लगाना चाहिए और योजनाओं के मौजूद होने तथा उनकी प्रतिकारणीयता के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करनी चाहिए।
- (ग) प्राधिकारी ने सबिसडी योजनाओं से कार्य करने की क्षमता पहले ही स्थापित और दी है और चीन में संबद्ध वस्तुओं के कच्चे माल पर मार्जिन की मात्रा का निर्धारण कर दिया है। निर्यातक को अपने कच्चे माल और अन्य इनपुट की खरीद का पूरा ब्यौरा देना चाहिए और यह सिद्ध करना चाहिए कि इसमें कोई सबिसडी नहीं है।
- (घ) जूली ने अपने द्वारा प्राप्त की गई सभी सबिसडी को प्रकट नहीं किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रमित करने तथा अपेक्षाकृत कम सबिसडी मार्जिन प्राप्त करने के उद्देश्य से तथ्यों को छिपाया है और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।
- (ङ) इस कार्यक्रम की प्रकृति कार्यक्रम और लाभ को परिभाषित करने के लिए निर्धारिक कारक है। इन कार्यक्रमों की नामावली का महत्व नहीं है जब तक कि कोई योजना लागू है और वह लाभ देती है। प्राधिकारी को इस कार्यक्रम को परिभाषित करने के लिए योजना की प्रकृति और इसके पीछे कानूनी आधार पर विचार करना चाहिए।

(च) यह जांच उस योजना तक प्रतिवंधित नहीं है जिसके बारे में आरोप याचिका में लगाया गया है और इसमें जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा न कहीं गई किसी लाभ के संबंध में कोई सूचना शामिल नहीं रहेगी।

### अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. प्राधिकारी द्वारा आरंभ किये गये 78 सब्सिडी कार्यक्रमों में से, उत्तर देने वाले निर्यातिक, मैसर्स झेजियांग जूली हाईटेक मेटल्स कं. लिमि. ने निम्नलिखित योजनाओं में से लाभ प्राप्त करने को स्वीकार किया है :
  - क. कार्यक्रम सं. 7 : निर्यात सहायता अनुदान
  - ख. कार्यक्रम सं. 33 : अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां
  - ग. कार्यक्रम सं. 35 : उन कंपनियों जिनकी पहचान उच्च एवं नये प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में किया गया है के लिए अधिमान्य कर नीतियां
  - घ. कार्यक्रम सं. 39 : विशेष उपकरण की खरीद के संबंध में कर ऋण
  - ङ. कार्यक्रम सं. 42 : उपक्रम आयकर कानून के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आयकर में कटौती
- ख. प्राधिकारी ने इन कार्यक्रमों की जांच आरंभ की जिनके लिए याचिकाकर्ताओं उचित आरोप भी नहीं लगाया है। याचिकाकर्ता तीन तथ्यों जिसमें प्रतिकारणीय सब्सिडी अर्थात् (क) वित्तीय अंशदान, (ख) लाभ और (ग) विशिष्टता शामिल है, के मौजूद होना सिद्ध नहीं किया।
- ग. प्राधिकारी को (क) क्या इसमें सब्सिडी देने के संबंध में साक्ष्य की पर्याप्तता और सटीकता का आकलन किया है; और (ख) यह आधार जिस पर यह मानते हैं कि याचिका में कथित प्रत्येक सब्सिडी के लिए समुचित और सटीक सूचना दी गई है, को न्यायोचित ठहराना चाहिए।
- घ. इन याचिकाकर्ताओं द्वारा पहचान किये गये किसी भी कार्यक्रम की पुष्टि तथ्यों और आंकड़ों से नहीं की गई है जो याचिका में सूचीबद्ध उत्पादक/निर्यातिक को लाभ पहुंचा रहे हैं। वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने याचिका में स्वयं यह मान लिया है कि इनके पास यह सिद्ध करने का कोई साक्ष्य नहीं है कि इस उत्पाद के प्रत्येक उत्पादक द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर ली गई है।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क तब लगाया जा सकता है जब शुल्क लगाये जाने के समय सब्सिडी दी गई हो।
- च. जब याचिकाकर्ता सब्सिडी के प्रभावों का आकलन करने में सक्षम नहीं हैं तब प्राधिकारी जांच के आरंभन के समय यह निर्धारित नहीं कर सके थे कि सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।
- छ. याचिकाकर्ता निर्यातिक से गोपनीय के रूप में सब्सिडी का आकलन नहीं कर सकते हैं।
- ज. कोई अतिरिक्त सूचना प्राधिकारी द्वारा जूली से नहीं मांगी गई है, जो इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करता हो कि जूली द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर पूर्ण है।
- झ. चीन की सरकार द्वारा असहयोग के फलस्वरूप जूली द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर को अस्वीकार नहीं करता है। निर्यातिक को अलग अलग मार्जिन का लाभ दिया जाना चाहिए।
- ञ. राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों से जूली द्वारा प्राप्त किया गया ऋण सब्सिडी के क्षेत्राधिकार से बाहर आता है क्योंकि ब्याज की दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है।
- ट. निर्यात सहायता अनुदान विदेशी प्रवृत्तियों में भाग लेने के लिए निर्यातिक को हूहाऊ कॉमर्स ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार का अनुदान ए एस सी एम के अनुच्छेद 3 के मामले में एक निर्यात सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह निर्यात कार्य निष्पादन पर निर्भर नहीं करता है।

- ठ. नियम 11 में विशेष रूप से अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए इस वस्तु का निर्माण करने, उत्पादन करने और निर्यात करने में लगे व्यक्तियों को दिये गये सब्सिडी कार्यक्रम से बाहर रखा जाता है। आर एंड डी खर्च के लिए करों में कटौती को प्रतिकारणीय सब्सिडी के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाता है।
- ड. उपक्रम आयकर कानून के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आयकर में कटौतियों को नये और उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था और यह इन सभी उपक्रमों के लिए उपलब्ध है जो पात्रता के मानदंड को पूरा करते हैं। इस कारण से यह विशिष्ट नहीं है।
- ढ. विशेष उपकरण की खरीद के संबंध में कर क्रृष्ण पारि-अनुकूल उपकरण को उन्नत करने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था जिसे नियम 11(1)(ग)(iii) के अंतर्गत प्रतिकारणीय सब्सिडी के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- ण. ए एस सी एम/ नियमावली में इस जांच की अवधि के दौरान पहचान किये गये नये कार्यक्रम को शामिल करने के लिए किसी कार्यपद्धति का प्रावधान नहीं है। जूली के वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किये गये अधिकांश कार्यक्रम इन संबद्ध वस्तुओं से संबंधित नहीं हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए कुछ हद तक विशिष्टता और लाभ है तब यह जूली को पूरक प्रश्नावली जारी कर सकता है और जूली अपेक्षित सूचना उपलब्ध करायेगा।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

50. चीन की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। एकमात्र उत्तर देने वाले उत्पादक/ निर्यातक, मैसर्स झेजियांग जूली हाई टेक मेटल्स कं. लिमि. ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और निम्नलिखित योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है :
- क. कार्यक्रम सं. 7 : निर्यात सहायता अनुदान
  - ख. कार्यक्रम सं. 33 : अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां
  - ग. कार्यक्रम सं. 35 : उन कंपनियों जिनकी पहचान उच्च एवं नये प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में किया गया है के लिए अधिमान्य कर नीतियां
  - घ. कार्यक्रम सं. 39 : विशेष उपकरण की खरीद के संबंध में कर क्रृष्ण
  - ड. कार्यक्रम सं. 42 : उपक्रम आयकर कानून के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आयकर में कटौती
51. उत्पादक के प्रश्नावली के उत्तर में उपर्युक्त स्वीकारोक्ति उपर्युक्त योजनाओं/ कार्यक्रमों के होने को दर्शाता है। हालांकि, जब चीन की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है तब उक्त उत्पादक द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली के उत्तरों का सत्यापन किया गया था जिसमें चीन में स्थल पर सत्यापन शामिल है।

### **अनुदान**

52. निर्यातक मैसर्स झेजियांग जूली हाई टेक मेटल्स कं. लिमि. ने प्रश्नावली के उत्तर में अपने आप कार्यक्रम सं. 7 : कॉलम निर्यात सहायता अनुदान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है।
53. एकमात्र उत्तर देने वाले उत्पादक/ निर्यातक मैसर्स झेजियांग जूली हाई टेक मेटल्स कं. लिमि. की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंपनी ने चीन में सरकारी प्राधिकारियों से सब्सिडी प्राप्त की है और उसकी सूचना परिसंपत्ति, आय और वित्त से संबंधित अनुदानों के लिए “सरकारी सब्सिडी” शीर्ष के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट में सूचना दी है।
54. तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि अनुदान के रूप में सरकारी सब्सिडी संबंधित कंपनी को लाभ देने वाले एक सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान है और यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं है। तदनुसार, वार्षिक रिपोर्ट में सूचित ‘अनुदान’ शीर्ष के अंतर्गत सब्सिडी मार्जिन पर सी वी डी मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए विचार किया

गया है। इस उद्देश्य से “सरकारी सब्सिडी” शीर्ष के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट में सूचित कुल राशि पर विचार किये गये लाभ के रूप में किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई सी वी डी मार्जिन की राशि \*\*\* प्रतिशत है।

### कर एवं मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन

55. चीन की सरकार और उसकी एजेंसियां अनेक कर कार्यक्रम चलाती हैं जो कुछ श्रेणी के उपक्रमों को उनकी अवस्थिति अथवा उपक्रमों की प्रकृति अथवा प्रौद्योगिकीय अभिनवता के आधार पर कर में छूट/ कटौती प्रदान करती है।
56. प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात मैसर्स झेजियांग जूली हाई टेक मेटल्स कं. लिमि. ने कार्यक्रम सं. 33 : अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। निर्यातिक ने यह तर्क दिया है कि यह एक स्वीकृति सब्सिडी है क्योंकि इसका संबंध आर एंड डी से है। हालांकि, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह कार्यवाही योग्य सब्सिडी है। इस आधार पर सब्सिडी का मार्जिन \*\*\* प्रतिशत होता है।
57. प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात मैसर्स झेजियांग जूली हाई टेक मेटल्स कं. लिमि. ने कार्यक्रम सं. 35 : उन कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जिसकी पहचान उच्च और नये प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में किया गया है, के लिए अधिमान्य कर नीतियां/ आयकर में कटौती के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। प्राधिकारी ने मार्जिन का निर्धारण \*\*\* प्रतिशत के रूप में किया है।
58. प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातिक मैसर्स झेजियांग जूली हाई टेक मेटल्स कं. लिमि. ने कार्यक्रम सं. 39 : विशेष उपकरण की खरीद के संबंध में कर क्रूण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किये गये कर छूट के आधार पर सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया है। इस प्रकार निर्धारित सब्सिडी मार्जिन \*\*\* प्रतिशत है।
59. घरेलू उद्योग ने कार्यक्रम सं. 51 : केंद्रीय क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों पर कंपनियों द्वारा प्राप्त मूल्यवर्धित पर छूट की मात्रा उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले निर्यातिक द्वारा और वर्ष 2016-17 तक स्थायी संपत्तियों में वृद्धि को लेकर तथा विभाजक के रूप में बिक्री कारोबार लेकर उस पर प्राप्त मूल्यवर्धित कर छूट को लेकर सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित सी वी डी मार्जिन \*\*\* प्रतिशत है।

### समुचित प्रतिफल से कम (एल टी ए आर) के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रावधान

#### क. भूमि के उपयोग का अधिकार

60. प्राधिकारी चीन की सरकार से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त न होने को नोट करते हैं, जिसमें चीन के उत्पादकों को भूमि से उपयोग के आधार की उपलब्धता के संबंध में आवश्यकता है। प्राधिकारी ने पूर्व की जांचों में भूमि के उपयोग के अधिकारों के रूप में प्रतिकारणीय सब्सिडी के मौजूद होने की जांच की थी और यह नोट किया था कि चीन की सरकार समुचित प्रतिफल से कम पर उस उपक्रमों को भूमि के उपयोग का अधिकार दे रही है जो कुछ प्रकार के उपक्रमों तक सीमित होने के कारण वित्तीय अंशदान, परिणामी लाभ और विशिष्टता के आधार पर प्रतिकारणीय सब्सिडी होती है। इस कारण से प्राधिकारी ने पूर्व में यह नोट किया कि चीन की सरकार द्वारा भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान प्रतिकारणीय सब्सिडी कार्यक्रम है।
61. प्राधिकारी ने निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए वर्तमान जांच में जांच आरंभ की -
  - क. कार्यक्रम सं. 60 : औद्योगिक और अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि के उपयोग का अधिकार
  - ख. कार्यक्रम सं. 61 : एस ओ ई के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार
  - ग. कार्यक्रम सं. 62 : एफ आई ई के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार

चूंकि प्राधिकारी ने विगत में भूमि के उपयोग के अधिकारों की प्रतिकारणीयता की जांच की है और इसके अलावा चीन की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, चीन की सरकार (जी ओ सी) से पर्याप्त सहयोग नहीं

मिलने के कारण प्राधिकारी ने नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी मार्जिन के समतुल्य प्रतिकारणीय सब्सिडी के रूप में भूमि के उपयोग के अधिकार पर विचार किया है।

#### **ख. उपयोगिता (विद्युत)**

62. जांच शुरूआत की सूचना समुचित प्रतिफल से कम के लिए बिजली के प्रावधान के संबंध में सब्सिडी कार्यक्रम सं. 58 के संदर्भ में है। पूर्व के सी वी डी जांच में यह नोट किया गया है कि चीन में सार्वजनिक निकाय समुचित प्रतिफल से कम पर औद्योगिक उपकरणों को बिजली उपलब्ध कराते हैं और तदनुसार इस पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है। चीन की सरकार से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त न होने को ध्यान में रखकर प्राधिकारी कार्यक्रम सं. 58 को प्रतिकारणीय मानते हैं। निर्धारित सब्सिडी मार्जिन \*\*\* प्रतिशत है।

#### **ग. कच्चा माल**

63. घरेलू उद्योग के बारे में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पूर्व में वर्ष 2017 में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने के लिए उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (अर्थात स्टेनलैस स्टील का कुछ हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद) ने 18.95 प्रतिशत के रूप में सब्सिडी का निर्धारण किया है। इसके अलावा, चीन के उत्तर देने वाले एकमात्र निर्यातक से यह कहा गया था कि वे इसके स्रोत सहित कच्चे माल की खरीद का ब्यौरा प्रस्तुत करें। उक्त निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में यह दर्शाया कि कंपनी ने चीन के बाजारों के भीतर और आयातों के द्वारा भी कच्चे माल की काफी मात्रा में आपूर्ति की है। इस प्रकार से प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के विशेषण से प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया कि घरेलू और आयात की गई खरीद कीमतों के बीच कीमत में अंतर \*\*\* प्रतिशत था। उत्तर देने वाले निर्यातक ने घरेलू तौर पर खरीदे गये और आयात की गये कच्चे माल के बीच किसी अंतर की सूचना नहीं दी है। इस कारण से कच्चे माल में सब्सिडी का मार्जिन का निर्धारण \*\*\* प्रतिशत के रूप में किया गया है।

#### **अधिमान्य ऋण और उधार**

64. प्राधिकारी ने कार्यक्रम 71, 72, 73, 74 और 75 के संबंध में बात आरंभ की। जबकि चीन की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, एकमात्र उत्तर देने वाले निर्यातक ने यह तर्क दिया कि ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये हैं चूंकि चीन की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अतः प्राधिकारी इस तथ्य की जांच नहीं कर पाये हैं कि क्या बैंकों द्वारा दिये गये वाणिज्यिक ऋण किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा बिना किसी निदेश अथवा नियंत्रण के हैं।
65. प्राधिकारी ने पूर्व में इस तथ्य का निर्धारण किया है कि चीन की सरकार रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है। प्राधिकारी ने नोट किया कि अधिमान्य उधार के फलस्वरूप निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान मिला है और वाणिज्यिक बैंचमार्क ब्याज दर के साथ ऋण प्राप्त करने वाले निर्यातक से राज्य के स्वामित्व वाले बैंक द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर की तुलना करते हुए इस प्रकार के अधिमान्य उधार के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का निर्धारण किया है। यह लाभ विशिष्ट है क्योंकि यह चीन में इस प्रकार के उपकरणों तक सीमित है।
66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से उपकरणों के ऋण (जिसमें विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक भी शामिल है) ऋण उपकरणों को लाभ प्रदान करता है। चूंकि प्राधिकारी ने विगत में इन कार्यक्रमों की प्रतिकारणीयता की जांच की है और इसके अलावा उसे चीन की सरकार ने निर्धारित रूप और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकारी ने यह विचार किया कि विचाराधीन उत्पाद के चीन के उत्पादकों को बैंचमार्क दरों से कम पर ऋणों से लाभ प्राप्त हुआ है। रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि \*\*\* प्रतिशत का लाभ विचाराधीन उत्पाद के चीन के उत्पादकों को प्रदान किया जाता है।

#### **चीन में सी वी डी योजना के संबंध में निष्कर्ष**

67. पूर्व में किये गये उल्लेख को ध्यान में रखकर प्राधिकारी यह पाते हैं कि चीन के उत्पादकों को प्रतिकारणीय सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। की गई जांचों, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा चीन की सरकार से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त न होने पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गये अनुसार विभिन्न सब्सिडी योजनाओं में सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण किया है -

क्र. सं.	योजना का नाम	सबिसडी मार्जिन मैसर्स जूली	सबिसडी मार्जिन शेष
I	अनुदान कार्यक्रम	0-5%	0-5%
II	कर और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन (क+ख+ग+घ नीचे दिए गए अनुसार)	0-5%	0-5%
IIक	• उच्च और नये प्रौद्योगिकी उपक्रमों के लिए कर में छूट	0-5%	0-5%
IIख	• मूल्यवर्धित कर में छूट	0-5%	0-5%
IIग	• पूँजीगत परिसंपत्तियों पर कर ऋण	0-5%	0-5%
IIघ	• आर एंड डी पर कर में छूट	0-5%	0-5%
III	एल टी ए आर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रावधान (क+ख+ग नीचे दिए अनुसार)	25-30%	25-30%
IIIक	• कच्चा माल	20-25%	20-25%
IIIख	• भूमि के उपयोग का अधिकार	0-5%	5-10%
IIIग	• विजली एल टी ए आर	0-5%	0-5%
IV	अधिमान्य ऋण और उधार	0-5%	0-5%
	कुल सबिसडी मार्जिन (रेंज)	<b>25%-35%</b>	<b>30%-40%</b>

#### ख. वियतनाम के संबंध में सबिसडी की जांच

68. वियतनाम की सरकार को परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था जो नई दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई, 2018 को  
आयोजित की गई थी।
69. याचिका में दी गई योजनाओं के विचार विमर्श और जांच के बाद, प्राधिकारी ने दो कार्यक्रमों की पहचान की है  
जिसमें जांच आवश्यक नहीं थी। इस कारण से इन कार्यक्रमों के संबंध में कोई जांच आरंभ नहीं की गई थी।
- कार्यक्रम सं. 4 : अधिमान्य आयात का शुल्क
  - कार्यक्रम सं. 12 : निर्यात वित्तपोषण/ क्रियाकलाप के लिए वियतन बैंक
70. प्राधिकारी ने निम्नलिखित सी वी डी कार्यक्रमों के लिए जांच आरंभ की
- कर प्रोत्साहन और शुल्क के रूप में पहचान की गई योजना**
    - कार्यक्रम सं. 1 : डिक्री 24 के अध्याय V के अंतर्गत आयकर अधिमान्यता (उपक्रम आयकर पर  
कानून का कार्यान्वयन)
    - कार्यक्रम सं. 2 : कच्चे माल के लिए आयात शुल्क में छूट अथवा प्रतिपूर्ति
    - कार्यक्रम सं. 3 : उपक्रमों के लिए कारपोरेट आयकर पर छूट
  - निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में पहचान की गई योजनाएं**
    - कार्यक्रम सं. 5 : निर्यातिकों को अधिमान्य उधार
    - कार्यक्रम सं. 6 : निर्यातिक संवर्धन कार्यक्रम
    - कार्यक्रम सं. 7 : वियतनाम डेवलपमेंट बैंक से निर्यात ऋण
    - कार्यक्रम सं. 8 : निर्यात सहायता ऋण

**III. निवेश प्रोत्साहन के रूप में पहचान की गई योजनाएं**

8. कार्यक्रम सं. 9 : निवेशकों के लिए अधिमान्य उधार
9. कार्यक्रम सं. 10 : निवेश उधार क्रृष्ण का ब्याज दर
10. कार्यक्रम सं. 11 : विदेशी निवेशकों जिन्होंने लघु और मध्यम उपक्रमों को पाठित करने पर निवेश किया, को निवेश सहायता।

**IV. बैंकों से लाभ के रूप में पहचान की गई योजनाएं**

11. कार्यक्रम सं. 13 : वियतिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी

**V. विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित होने के लिए पहचान की गई योजनाएं**

12. कार्यक्रम सं. 14 : डिक्री 142 के अंतर्गत प्रोत्साहित उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों में उपक्रमों के लिए भूमि अधिमान्यता

**VI. उपयोगिता के उपयोग पर प्रोत्साहन के लिए पहचान की गई योजनाएं**

13. कार्यक्रम सं. 15 : समुचित प्रतिफल से कम के लिए भूमि का सरकारी प्रावधान और भूमि एवं जल के लगानों से छूट अथवा कमी।

71. जांच आरंभ करने के बाद चीन की सरकार और इस उत्पाद के उत्पादक/ निर्यातक को सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित रूप और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें और उन्हें इस प्रकार की सब्सिडी यदि कोई हो की मौजूदगी और मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए कथित सब्सिडी कार्यक्रम के मौजूद होने, उसकी सीमा और प्रभाव के संबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए समुचित समय और अवसर दिये गये थे।

72. वियतनाम की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और कुछ योजना/ कार्यक्रमों के संबंध में कुछ सूचना उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, वियतनाम के संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।

- i. सोन्हा एस एस पी वियतनाम सोल मेम्बर कं. लिमि.
- ii. नाम कुआंग मेटल कं. लिमि.
- iii. ओ एस एस डाई डुआंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
- iv. टुअन डाट मेटल कं. लिमि.
- v. गिया अन्ह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
- vi. हा अन्ह स्टेनलैस स्टील कं. लिमि.
- vii. गियाअन्ह हुंग येन कं. लिमि.
- viii. विनलॉग स्टेनलैस स्टील (वियतनाम) कं. लिमि.
- ix. स्टील 568 कं. लिमि.

73. उपर्युक्त उत्पादकों/ निर्यातकों तथा वियतनाम की सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों की जांच की गई थी और उनका सत्यापन किया गया था।

**छ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन**

74. वियतनाम की योजनाओं के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने आगे निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- (क) संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक/ नियांतक को सरकारों के विभिन्न स्तरों के निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिकारिणीय समिस्ती प्राप्त हुई है -
- (i) कर प्रोत्साहन और छूट
  - (ii) नियांत वित्तपोषण और नियांत क्रण
  - (iii) निवेश प्रोत्साहन
  - (iv) बैंकों से लाभ
  - (v) विशिष्ट क्षेत्रों में लाभ
  - (vi) उपयोगिताओं के उपयोग पर प्रोत्साहन
  - (vii) आशियान, भारत-आशियान, चीन-आशियान सहित खुला व्यापार करार
- (ख) वियतनाम के उत्पादक समुचित प्रतिफल से कम पर चीन से इस्पात, प्रमुख कच्चा माल की आपूर्ति कर रहा है। चूंकि खरीद सरकारी कार्यक्रम (चीन-आशियान व्यापार करार) के अंतर्गत किया जाता है। अतः प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच और इस पर विचार करना चाहिए कि चीन से खरीदे गये इस्पात में समिस्ती की वर्तमान उद्देश्यों से उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- (ग) चूंकि वियतनाम में नियांतकों ने चीन से हॉट रोल्ड इस्पात का आयात किया है और वियतनाम में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए इसे परिष्कृत किया है, मूल्यवर्धन तब तक भारत-आशियान करार के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं हो सकता है जब तक वियतनाम से उत्पादक अपने उत्पादन के भाग के रूप में चीन से निर्माण को शामिल नहीं कर लेते हैं। वियतनाम के उत्पादकों ने संबद्ध वस्तुओं का नियांत किया है और चीन से उत्पादन के बल पर ही आशियान-भारत खुला व्यापार करार (ए आई एफ टी ए) के अंतर्गत चीन की रियायती दर का लाभ लेने के उद्देश्य से उसे वियतनाम के मूल का होने का दावा किया है। वियतनाम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ए-। फार्म यह दर्शता है कि वियतनाम के उत्पादकों ने दावा किया है और वियतनाम एवं भारत में ऐसे सक्षम प्राधिकारी ने दो देशों – वियतनाम और चीन में किये गये निर्माण के आधार पर मूल्यवर्धन स्वीकार किया है।
- (घ) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को की गई घोषणा और निर्दिष्ट प्राधिकारी को की गई घोषणा के अनुसार वियतनाम के उत्पादकों द्वारा शुरू की गई उत्पादन की प्रक्रिया अलग अलग नहीं हो सकती है। यदि अलग प्रक्रिया का दावा किया गया है तब निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी मामले में प्रश्नावली के उत्तर को यह मानते हुए अस्वीकार करें कि वियतनाम के उत्पादकों ने भारत में दो प्राधिकारियों के बीच विरोधाभासी दावे किये हैं। यदि वियतनाम के उत्पादकों ने चीन ओर वियतनाम में नियोजित उत्पादन प्रक्रिया का दावा मूल्यवर्धन की शर्त को पूरा करने के लिए उनके द्वारा की गई प्रक्रिया के रूप में किया है तब निर्दिष्ट प्राधिकारी को वर्तमान उद्देश्यों से उस पर विचार करना चाहिए। यदि प्राधिकारी को प्रकट किया गया इनपुट इस्पात है और लगभग 10 प्रतिशत के मूल्यवर्धन को दर्शाया गया है तब यह स्पष्ट रूप से भारत में दो प्राधिकारियों के समक्ष विरोधाभासी दावे करने और तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का स्पष्ट मामला है।
- (ङ) यदि स्केप का उपयोग नहीं किया जाता है तब संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने में मूल्यवर्धन अधिमान्य प्रशुल्क विवेचन का दावा करने के लिए आशियन-भारत एफ टी ए के अंतर्गत निर्धारित मूल्यवर्धन से बहुत कम होगा। हालांकि, वियतनाम में सरकारी प्राधिकारियों ने वियतनाम को उत्पत्ति देश के रूप में दर्शाते हुए और करार के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक मूल्यवर्धन दर्शाते हुए प्रमाण पत्र जारी किये हैं। या तो वियतनाम सरकार इस बात पर सहमत हो कि इसने मूल देश के संबंध में जाली प्रमाण पत्र के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का नियांत करने के लिए वियतनाम के उत्पादकों को अनुमति दी है अथवा वियतनाम सरकार इस बात पर सहमत हो कि मूल्यवर्धन का दावा दो देशों – चीन और वियतनाम में किये गये उत्पादन के आधार पर किया गया है।
- (च) किसी स्केप से स्टील बनाने की उत्पादन प्रक्रिया की सूचना इस उत्पाद के उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादन प्रक्रिया के रूप में उचित की गई है अतः वियतनाम के उत्पादकों को हॉट और कॉल्ड रोलिंग के चरण तक

चीन की सब्सिडी प्राप्त इस्पात से लाभ मिला है। इस प्रकार की सब्सिडी देने की मात्रा का निर्धारण पूर्व की सी डी डी जांचों में प्राधिकारी द्वारा 18.95 प्रतिशत के रूप में किया गया है।

- (छ) चूंकि ए-। फार्म मूल्यवर्धन चीन में उत्पादन की प्रक्रिया पर आधारित है। अतः यह माना गया है कि वियतनाम के उत्पादकों ने इस उत्पाद का उत्पादन करने और उसकी विक्री करते हुए उत्पादन की प्रक्रिया अपनाई है। ए-। फार्म में वियतनाम के उत्पादकों द्वारा किये गये दावे के लिए कोई अलग स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है।
- (ज) वियतनाम के उत्पादकों को लेन देन वार इस्पात का खरीद से संबंधित पूर्ण व्यौरा और आपूर्तिकर्ता के देश को दर्शाते हुए उपलब्ध कराना चाहिए। यदि यह सूचना नहीं दी जाती है तब प्राधिकारी इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि क्या वियतनाम के उत्पादकों को उस उत्पादन प्रक्रिया से लाभ प्राप्त हुआ था जिसे चीन में उनके द्वारा किये गये के रूप में माना गया है।
- (झ) वियतनाम की सरकार ने अपने निर्यातिकों को प्रतिकारणीय सब्सिडी दी है, जिसने उन्हें भारतीय बाजार में क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात करने की अनुमति दी है।
- (ञ) वियतनाम सरकार को इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की अनुमति देते समय वियतनाम के उत्पादकों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में निश्चित रूप से पूरी जानकारी रही होगी। इसके अलावा, वियतनाम की सरकार आवधिक तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वियतनाम के उत्पादकों द्वारा की गई घोषणाएं सही हो, व्यापार करार के अंतर्गत प्राप्त अधिदेश के अनुसार सत्यापन किया होगा। इस कारण से वियतनाम की सरकार अब जानकारी न होने का तर्क नहीं दे सकती है।
- (ट) वियतनाम के उत्तर देशे वाले निर्यातिकों जैसे ओ एस एस डाई डॉग और विनलॉग स्टेनलैस स्टील द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावली का उत्तर चीन से अथवा चीन की एक संबंधित कंपनी/ मूल कंपनी से कच्चे माल की खरीद को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- (ठ) चीन को गलाने के चरण से या तो वियतनाम ने अथवा आशियान के भीतर कोई उत्पादन सुविधा नहीं थी। किसी भी परिस्थिति में उस चरण से लेकर विचाराधीन उत्पाद तक या तो वियतनाम अथवा आशियान के भीतर उपलब्ध उत्पादन सुविधा और मूल्यवर्धन के फलस्वरूप नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी सूचना ए-१ फार्म में (जो \*\*\* प्रतिशत के मूल्यवर्धन को दर्शाता है) की सूचना दी जा रही है।
- (ड) वियतनाम सरकार डब्ल्यू टी ओ के अंतर्गत गैर कार्यवाही योग्य सब्सिडी के संबंध में कानूनी स्थिति पर प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि 1999 के अंत में ये प्रावधान समाप्त हो गये थे। प्रतिकारी शुल्क नियमावली के नियम 11 को ए एस सी एम के अनुच्छेदों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।
- (ढ) याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 4 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/18/2015 – डी जी ए डी के संदर्भ में कच्चे माल में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सब्सिडी मार्जिन के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना के आधार पर वियतनाम से उत्पादकों/ निर्यातिकों दोनों के लिए सब्सिडी मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया है।
- (ण) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें यह अपेक्षित हो कि प्रतिकारी शुल्क तभी लगाया जा सकता है जब लगाये जाने के समय सब्सिडी हो। यदि जांच की अवधि के दौरान सब्सिडी की मौजूदगी और उसकी अधिप्राप्ति को सिद्ध किया गया हो तब प्रतिकारी शुल्क लगाया जा सकता है, चाहे इस प्रकार की सब्सिडी मौजूद हो अथवा प्रतिकारी शुल्क लगाये जाने के समय इसका लाभ उठाया गया हो। स्थायी परिसंपत्तियों के लिए सब्सिडी को समग्र ए यू एल की अवधि के दौरान विचार किया जा सकता है।
- (त) यदि संबद्ध देशों की सरकारों और उत्पादकों/ निर्यातिकों असहयोगी हों तब रिकार्ड पर पहले से उपलब्ध साक्षों के आधार पर इन योजनाओं की प्रतिकारनियता का निर्धारण और सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण करने में आगे की कार्यवाही करनी चाहिए।

## छ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन

75. वियतनाम की योजनाओं के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नीचे दिये गये अनुसार अनुरोध किया है :

- क. चूंकि भारत और वियतनाम तेजी से दोस्ताना संबंध बढ़ा रहा है अतः द्विपक्षीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान विचार विमर्श के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रतिकारी जांच वियतनाम में भारत के निवेश करने वाले उपक्रमों के हितों को नुकसान पहुंचायेगा।
- ख. इस याचिका में उल्लिखित सभी प्रत्यक्ष कर कार्यक्रमों के संबंध में वियतनाम से निर्यात करने वाले उत्पादकों के लिए लाभ के होने का कोई साक्ष्य नहीं है।
- ग. डिक्री 24/2007 / एनडी-सीपी को कानून सं. 14/2008/क्यूएच 12 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इस कारण से जांच की अवधि के दौरान यह लागू नहीं था।
- घ. प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि वियतनाम के निर्यातकों को वियतनाम की सरकार से कोई प्रतिकारणीय सबिसडी प्राप्त नहीं हुई थी।
- ङ. निर्यातकों को वियतनाम की सरकार अथवा वियतनाम डेवलपमेंट बैंक से कोई क्रहण प्राप्त नहीं हुआ था और सभी बकाया क्रहण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज के बाजार दरों पर और बिना किसी छूट के दिया गया था।
- च. जबकि पांच निर्यातकों को कोई आयकर प्राप्त नहीं हुआ अथवा आयकर शुल्क अधिमानता नहीं मिली थी, छठे निर्यातक द्वारा प्राप्त किये गये लाभ असुविधाजनक क्षेत्र में इसकी अवस्थिति के आधार पर थी। इस कारण से यह प्रतिकारणीय सबिसडी नहीं होती है क्योंकि यह लाभ असुविधाजनक क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर थी और इस कारण से इस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
- छ. सभी पांच निर्यातकों को भूमि के लगान, विजली और जल शुल्क के संबंध में कोई छूट अथवा कमी नहीं मिली थी।
- ज. भारत सरकार भी विशेष आर्थिक क्षेत्र में, कम विकसित क्षेत्रों में स्थित इकाईयों को कर प्रोत्साहन, विशेष उद्योगों, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए प्रोत्साहन तथा निर्यातकों को ड्रा बैंक, यूओयू, ई पी सी जी आदि जैसे प्रोत्साहन देती है।

### ग. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भाग लेने वाले कुछ उत्पादकों/ निर्यातकों ने सत्यापन के दौरान उनसे मांगा गया अपेक्षित ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। तदनुसार, इन मामलों में सबिसडी के मार्जिन का निर्धारण नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।
- I. कर प्रोत्साहन के रूप में पहचान किये गये कार्यक्रम :-
- क. कार्यक्रम सं. 1 : डिक्री 24 के अध्याय V के अंतर्गत आयकर अधिमान्यताएं (उपक्रम आयकर संबंधी कानून का कार्यान्वयन) और
- ख. कार्यक्रम सं. 3 : उपक्रमों के लिए कोरपोरेट आयकर पर छूट
77. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि इन कार्यक्रमों को वियतनाम सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है और वित्त मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया कि उपक्रम आयकर 2003 – कानून सं. 09/2003/क्यू एच 11 के अंतर्गत शेष अवधि के लिए ये प्रोत्साहन (अर्थात् शेष लाभ) मिलता जारी है। याचिकाकर्ताओं ने आगे यह अनुरोध किया कि यदि उपक्रम आयकर प्रोत्साहन (कर दर प्रोत्साहन) और कर छूट और कमी की अवधि सहित इस कानून में उल्लिखित कर प्रोत्साहन राशि के तुलना में कम है, इस कानून के अंतर्गत कर प्रोत्साहन शेष अवधि के लिए लागू होते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया है कि विक्री सं. 218/2013/एन डी – सी पी का अनुच्छेद

20.2 स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि निवेश परियोजनाओं वाले उपक्रम और 2013 की कर अवधि के अंत तक कोरपोरेट आयकर की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। अन्य शब्दों में याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि जब इस कानून को निरस्त कर दिया जायेगा तब भी शेष लाभ इन उपक्रमों के लिए उपलब्ध हैं जो पूर्व में उनके लिए पात्र थे। कार्यक्रम सं. 1 को कार्यक्रम सं. 3 से प्रतिस्थापित किया गया है। उत्तर देने वाले कुछ निर्यातिकों ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने कार्यक्रम सं. 3 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है।

78. वियतनाम के उत्तर देने वाले निर्यातिकों नाम कुओंग मेटल कं. वियतनाम, डाई डुओंग ओ एस एस कं. लिमि., तुआन डाट मेटल कं. लिमि., विनलॉग स्टेनलैस स्टील (वियतनाम) कं. लिमि., स्टील 568 कं. लिमि., जियाअन्ह ज्वाइंट स्टॉक कं., हा अन्ह स्टेनलैस स्टील कं. लिमि., जियाअन्ह हुआग येन ने अनुरोध किया कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान आवेदन नहीं किया है अथवा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है क्योंकि उसकी बिक्री 2009 में समाप्त हो गई है। हालांकि इन कंपनियों ने पूर्व के कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध शेष लाभों के संबंध में किसी बात का उल्लेख नहीं किया है।
79. सान्हा एस एस पी वियतनाम सोल मेम्बर कं. लिमि., ने उल्लेख किया है कि इस कानून को 2009 में समाप्त किया गया है और इसमें राष्ट्रीय सभा के दिनांक 19/06/2013 के कानून सं. 32/2013 आई क्यू एच 13 के द्वारा संशोधन किया गया है और उसे पूरा किया गया है जिसने 1 जनवरी 2014 से लागू उपक्रम आयकर पर कानून के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन किया और उसे पूरा किया। इसके अलावा, यह कहा गया है कि राष्ट्रीय सभा की कानून सं. 7112014 आई क्यू एच 13 दिनांक 26/11/2014 में संशोधन किया गया था और 01/01/2015 से लागू कर कानून के कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। कंपनी ने यह भी उल्लेख किया है कि डिक्री सं. 218/2013/एनडी-सीपी दिनांक 26/12/2013 के कोरपोरेट आयकर संबंधी कानून जो 15/02/2014 से लागू है, के बारे में विकसित विवरण और मार्गदर्शन दिया है। जब किसी कंपनी उक्त मानदंड के अंतर्गत नहीं आती है, अतः कंपनी को कोई लाभ नहीं मिला है।
80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये कार्यक्रम प्रतिसंतुलनीय हैं। कुछ उत्पादक/ निर्यातिकों ने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ उठाया है जबकि कुछ उत्पादक/ निर्यातिकों ने लाभ नहीं उठाया है। तदनुसार, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सबिडी मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

#### **ग. कार्यक्रम सं. 2 : कच्चे माल के लिए आयात शुल्क छूट अथवा प्रतिपूर्ति**

81. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि इन कार्यक्रमों को वियतनाम सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है और इसका संचालन वित्त मंत्रालय और वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है जिसमें आगे उत्पादन के लिए वियतनाम ने कच्चे माल का आयात करने के लिए आयात शुल्क के भुगतान पर छूट का प्रावधान है जो निर्यात कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है।
82. वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया कि निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले आयातिक कच्चे माल के लिए आयात शुल्क में छूट दी जाती है। छूट की राशि तैयार वस्तुओं जिनका निर्यात किया जाता है, के उत्पादन में वास्तविक रूप में उपयोग किये जाने वाले आयातिक माल के मूल्य से सदृश्य शुल्क की राशि के बराबर है। इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वियतनाम सीमा शुल्क सामान्य विभाग (जी डी वी सी) द्वारा किया जाता है। इस नीति के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जी डी वी सी (1) स्केप और परित्याग उत्पादों जो उत्पादन की प्रक्रिया में गायब हो जाते हैं (जिसे 'खपत मानदंड' कहा जाता है) सहित निर्यात उत्पादों के उत्पाद के लिए वास्तव में खपत किये गये आयातिक माल की मात्रा; और (2) क्या निर्यात किये गये उत्पाद इस्पातों का वास्तव में निर्यात किया गया है, पर निजर रखने के लिए एक प्रणाली के विकास का प्रभार है।
83. उत्तर देने वाले निर्यातिक सोन्हा एस एस पी वियतनाम सोल मेम्बर कं., स्टील 568 कं., हा अन्ह स्टेनलैस स्टील कं. लिमि., टुअन डाट मेटल कं. लिमि., ओ एस एस डाई डुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक, जिया अन्ह हाँग येन कं. लिमि., नाम कुओंग मेटल कं. लिमि. ने दावा किया है कि उन्हे आयात किये गये कच्चे माल के लिए आयात शुल्क में छूट अथवा उसकी प्रतिपूर्ति के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि प्रशुल्क समय सारणी 0 प्रतिशत शुल्क

दरों पर निर्धारित की गई है। विनलॉग स्टेनलैस वियतनाम कं. लिमि. ने यह उल्लेख किया है कि उन्हें उक्त कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं मिला है क्योंकि वे नियंति प्रसंस्करण उपक्रम हैं और वे किसी आयात/नियंति शुल्क एवं मूल्यवर्धित कर की छूट के अध्यधीन नहीं हैं।

84. वियतनाम सरकार द्वारा किये गये निवेदनों के संबंध में उत्तर देने वाले नियंतिक स्टील 568 कं., हा अन्ह स्टेनलैस स्टील कं. लिमि. टुअन डाट मेटल कं. लिमि., ओ एस एस डाई ब्लांग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक, जिया अन्ह हुआग येन कं. लिमि., नाम कुअंग मेटल कं. लिमि. ने उल्लेख किया कि आशियान-भारत खुला व्यापार करार (ए आई एफ टी ए) के अनुसार, कच्चे माल के लिए आयात किये जाने के समय लागू आयात शुल्क 0 प्रतिशत था और इस कारण से कोई भी शुल्क भुगतान के योग्य नहीं था और कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता था।

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त कार्यक्रम में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और नियंति किये गये वस्तुओं के लिए कच्चे मालों पर आयात शुल्क में छूट के लिए लाभ दिया जाता है, यह छूट लगाये गये शुल्क की राशि से अधिक नहीं हो सकता है, अन्यथा छूट दी गई अधिक राशि प्रतिसंतुलनीय लाभ देता है।

#### **घ. कार्यक्रम सं. 5 : नियंतिकों को अधिमान्य उधार देना**

86. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि नियंतिकों को अधिमान्य उधार से संबंधित कार्यक्रम सं. 5 वियतनाम सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है और वित्त मंत्रालय, राज्य एजेंसियों, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम और अन्य वाणिज्यिक बैंकों, राज्य पूँजी निवेश निगम (एस सी आई सी); वियतिन बैंक (एस ओ ई बैंक), वियतनाम डेवलपमेंट बैंक जो कम ब्याज पर ऋण देता है और जहां ऋण का 50 प्रतिशत जो वियतनाम में राज्य की स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाती, द्वारा संचालित किया जाता है क्योंकि वियतनाम ने बैंकिंग क्षेत्र वियतनाम के राज्य के स्वामित्व वाले स्टेट बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अधिकतम ब्याज दरों को तय करता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि ब्याज दर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों ने कम दर पर ऋण प्राप्त किया है। वियतनाम ने उत्पादकों को ब्याज के कम दर के रूप में लाभ मिला है।

87. वियतनाम की सरकार ने उल्लेख किया कि ऐसी कोई नीति नहीं है जो बैंकों को वियतनाम में राज्य अथवा राष्ट्र की नीति के अनुसार चलाने के लिए निदेश दें और यह कि वाणिज्यिक बैंक ऋण प्राप्तकर्ताओं के संबंध में विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद स्वतंत्र रूप से उधार देने का निर्णय करते हैं और इन निर्णयों का सरकारी प्राधिकारी से कोई संबंध नहीं है। वियतनाम डेवलपमेंट बैंक राज्य की स्वामित्व वाला वाणिज्यिक बैंक है और उसकी स्थापना मई 2006 को निर्णय 108/2006/ क्यूडी-टी टीजी के द्वारा किया गया था। डिक्री सं. 32/2017/एनडी-सीपी के अंतर्गत, राज्य के निवेश ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। बैंक तीनों प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं, नियंतिकों को अधिमान्य ऋण उनमें से एक है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आरोप लगाना पूर्णरूप से सही नहीं है कि वियतनाम में नीतिगत बैंक राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करता है। वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण की राशि बाजार आधारित ब्याज दरों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है और उस पर कोई सब्सिडी नहीं ली जाती है और न ही उसे तंग किया जाता है।

88. उत्तर देने वाले किसी भी नियंतिक ने इस कार्यक्रम के बारे में कोई स्पष्टीकरण अथवा विवरण नहीं दिया है। उन्होंने न तो यह उल्लेख किया है कि उन्हें उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और न ही यह कि वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, किसी भी नियंतिक ने अपने द्वारा लिये गये किसी भी ऋण का और इस पर भुगतान किये गये ब्याज की दर का कुल विवरण उपलब्ध कराया है जो यह दर्शा सके कि इनके द्वारा लिये गये ऋणों की अलग अलग श्रेणियों पर कोई अंतर ब्याज नहीं है।

89. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बैंक द्वारा रियायती दरों पर ऋण दिये जा सकते हैं जो सरकार के स्वामित्व वाली अथवा निजी रूप से नियंत्रित हो सके। यद्यपि किसी बैंक को निजी तौर पर नियंत्रित भी किया जाता है तब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यदि प्राइवेट बैंक केंद्रीय बैंक/ सरकार से निदेश कर रियायती दर पर ऋण देते हैं तब प्रतिसंतुलनीयता नहीं होती है।

90. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उक्त कार्यक्रम की जांच यू एस – लेमिनेटिड बोवेन स्टेक द्वारा किया गया है और कुछ पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क वियतनाम के उत्पादकों के मामले में लगाया गया है।
91. तदनुसार, सबिसडी मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नीचे दिये तालिका के अनुसार किया गया है।
- उ. कार्यक्रम सं. 6 : निर्यात संवर्धन कार्यक्रम**
92. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य व्यापार संवर्धन क्रियाकलापों का विस्तार करना, निर्यात बाजारों का विकास करना, व्यापार संवर्धन की सेवा में ठोस नींव बनाने के लिए आरंभिक स्थितियां उत्पन्न करना और जांच के अधीन संबंधित उपक्रमों की व्यापार क्षमता को बढ़ाने में अंशदान करना है। याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि वर्तमान कार्यक्रम निर्यात निष्पादन पर निर्भर करता है।
93. वियतनाम सरकार ने अनुरोध किया कि निर्यात संवर्धन कार्यक्रम उद्योग और व्यापार मंत्रालय (एम ओ आई टी) द्वारा अपने स्थानीय निकाय के माध्यम शासित किया जाता है जो विदेशी बाजारों, सीमावर्ती क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में भी व्यापार का विस्तार करने के लिए व्यापार संवर्धन क्रियाकलापों को शासित करता है। यह कार्यक्रम 2010 में शुरू हुआ और यह राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन नीति के अनुसार हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए पात्रता संबंधी मानदंड यह है कि विशिष्ट उपक्रम के पास व्यापार संवर्धन योजना होनी ही चाहिए जो निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करे और उसमें आयात किये गये उत्पादों की तुलना में स्थानीय उत्पादों का संवर्धन करने की योजना शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा, वियतनाम सरकार ने अनुरोध किया कि उत्तर देने वाले किसी भी निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, वियतनाम सरकार ने इस उत्पाद के उत्पादों/ निर्यातकों जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है और जिन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ मिल सकता है कि सूची उपलब्ध नहीं कराई है।
94. वियतनाम सरकार से इन तर्कों का उत्तर देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उद्योग और व्यापार मंत्री के दिनांक 16/01/2017 के निर्णय संख्या 137/ क्यू डी – बी सी टी के अनुसार 2017 में राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन कार्यक्रम स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इस योजना को उक्त अधिसूचना से प्रतिस्थापित किया गया है और यह योजना अभी भी लागू है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त घटनाक्रम को वियतनाम सरकार द्वारा रिकार्ड पर नहीं लाया गया है और न ही दिनांक 16/01/2017 के निर्णय सं. 137/ क्यू डी – बी सी टी की मौजूदगी से वियतनाम सरकार द्वारा इनकार किया गया है।
95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम को सार्वजनिक निकाय द्वारा विनियमित किया जाता है और इसमें व्यापार संवर्धन क्रियाकलाप का प्रावधान है जिसे प्रतिसंतुलनीय माना गया है।
96. तदनुसार, सबिसडी मार्जिन का निर्धारण नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया गया है।
- च. कार्यक्रम सं. 7 : वियतनाम डेवलपमेंट बैंक निर्यात ऋण**
97. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि वियतनाम डेवलपमेंट बैंक वियतनाम से उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यात दे रहा है। इस कार्यक्रम को वियतनाम सरकार शासित किया जाता है और इसका संचालन वित्त मंत्रालय, राज्य एजेंसिया स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम और अन्य वाणिज्यिक बैंकों राज्य पूँजी निगम (एस सी आई सी) वियतन बैंक (एस ओ ई बैंक) ने वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया जाता है। ये बैंक कम ब्याज लागत ऋण उपलब्ध कराते हैं और जहां ऋण राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये अथवा मंजूर किये जाते हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि वियतनाम में बैंकिंग क्षेत्र पर राज्य के स्वामित्व वाले “स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम” द्वारा नियंत्रण रहता है जो इस उद्देश्य से अधिकतम ब्याज दरों को तय करता है।
98. वियतनाम सरकार ने उल्लेख किया है वियतनाम डेवलपमेंट बैंक राज्य के स्वामित्व वाला एक वाणिज्यिक बैंक है और उसकी स्थापना मई, 2006 को निर्णय 108/ 2006/ क्यूडी-टीटीजी द्वारा किया गया है। ये बैंक तीन प्रमुख प्रकार के लाभों – निर्यातकों को अधिमान्य ऋण देना उनमें से एक है, उपलब्ध कराता है। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है कि वियतनाम में एक नीतिगत बैंक राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करता है और वह कि वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण की राशि

बाजार आधारित व्याज दरों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है और इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है अथवा इसे कम नहीं किया जाता है।

99. वियतनाम सरकार द्वारा और उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा किये गये अनुरोधों के उत्तर में याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम का कोई विस्तृत स्पष्टीकरण और विवरण वियतनाम सरकार अथवा उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है और उन्होंने केवल यह उल्लेख किया है कि उन्हें उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है अथवा वे अपने कथन के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण दिये बिना इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सार्वजनिक निकाय अथवा सार्वजनिक निकाय के निवेश पर दिया गया ऋण यदि रियायती दरों पर दिया जाता है तब यह प्रतिसंतुलन कारणीय सब्सिडी हो सकता है।
101. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं उक्त कार्यक्रम की जांच कोल्ड रॉल्ड स्टील और कॉपर फिटिंग में कनाडा, पोलीस्टर स्टेपल फाइबर में यूरोपीय यूनियन और जमाये हुये गरम जल शिमपंद ने यू एस सहित अन्य जांच अधिकारियों द्वारा किया गया है और उस पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।
102. तदनुसार, सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया गया है।

#### **च. कार्यक्रम सं. 8 : निर्यात सहायता ऋण**

103. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि उक्त कार्यक्रम निर्यातकों को रियायती दरों पर कुछ वस्तुओं के आयात पर सहायता के आधार पर ऋण प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। निर्यात सहायता केवल उन निर्यातकों पर लागू होगी जो निवेशकों के साथ शामिल हैं और जिनकी ऋण चुकाने की क्षमता है, परियोजना को निवेश और निर्माण चरण में अवश्य पूरा किया होना चाहिए और निवेशक का वित्तीय योजनाओं और ऋण पुनर्भुगतान योजनाओं के लिए विकास सहायता निधि के द्वारा अवश्य मूल्यांकन किया गया होना चाहिए।
  104. वियतनाम सरकार ने उल्लेख किया है कि उक्त कार्यक्रम 2001 में आरंभ किया गया था और 2007 में समाप्त कर दिया गया है और उस पर उत्तर देने वाले किसी निर्यातक को उक्त कार्यक्रम से लाभ नहीं मिला है।
  105. वियतनाम सरकार के इस तर्क का उत्तर देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि डिक्री 32/ 2017 का अनुच्छेद 8 और 9 में यह प्रावधान है कि ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 12 वर्ष है दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह कार्यक्रम शेष लाभों को प्रदान करता है। हालांकि, वियतनाम सरकार और उत्तर देने वाले निर्यातकों ने यह सूचना नहीं दी है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई शेष लाभ है।
  106. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को नोट किया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यात राजस्व के साथ निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करने, निर्माण करने अथवा प्रसंस्करण करने की निवेश परियोजनाओं के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत लघु और मध्यम अवधि के निवेश ऋणों के बारे में याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि ये ऋण कुल वार्षिक राजस्व का कम से कम 30 प्रतिशत हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त कार्यक्रम का मूल्यांकन अन्य जांच प्राधिकारियों जैसे कोल्ड रोल्ड, कॉपर फिटिंग में कनाडा; पोलीस्टर स्टेपल फाइबर में यूरोपीय यूनियन, जमे हुए गरम पानी श्रिम्प मामलों में यू एस द्वारा किया गया है और इस पर प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।
  107. प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ निर्यात कार्य निष्पादन पर निर्भर है और इस कारण से उस पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जा सकता है। तदनुसार, सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया गया है।
- ज. कार्यक्रम सं. 9 : निवेशकों के लिए अधिमान्य ऋण देना**
108. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि अधिमान्य दरों पर ऋण निवेशकों को वियतनाम में उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम का संचालन वित्त मंत्रालय, राज्य एजेंसियों, स्टेट बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों,

- राज्य पूंजी निवेश निगम (एस सी आई सी); वियतिन बैंक (एस ओ ई बैंक), वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया जाता है।
109. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि यह कार्यक्रम वियतनाम में राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम ब्याज क्रृष्ण उपलब्ध कराता है क्योंकि वियतनाम में बैंकिंग क्षेत्र, स्टेट बैंक और ऑफ वियतनाम द्वारा नियंत्रित होता है जो अधिकतम ब्याज दरों को तय करता है।
110. वियतनाम सरकार ने उल्लेख किया है वियतनाम डेवलपमेंट बैंक राज्य के स्वामित्व वाला एक वाणिज्यिक बैंक है और उसकी स्थापना मई, 2006 को निर्णय 108/ 2006/ क्यूडी-टीटीजी और डिक्री संख्या डिक्री सं. 75/ 2011/ एनडी-सीपी द्वारा किया गया है। ये बैंक तीन प्रमुख प्रकार के लाभों – नियर्तिकों को अधिमान्य क्रृष्ण देना उनमें से एक है, उपलब्ध कराता है। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है कि वियतनाम में एक नीतिगत बैंक राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करता है और वह कि वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत क्रृष्ण की राशि बाजार आधारित ब्याज दरों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है और इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है अथवा इसे कम नहीं किया जाता है।
111. वियतनाम सरकार के तर्कों का उत्तर देते हुए याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि बाजार प्रथाओं से प्राप्त की जा रही ब्याज दर के संबंध में वियतनाम सरकार का दावा सही नहीं है। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को सब्सिडी वाले ब्याज दर पर वियतनाम सरकार के नियंत्रण वाले बैंक से क्रृष्ण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि हितवद्ध पक्षकारों ने या तो केवल इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपने कथन का समर्थन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिये बिना इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के लिये वे पात्र नहीं हैं।
112. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को नोट करते हैं कि इन उपक्रमों को वियतनाम में रियायती दरों पर क्रृष्ण उपलब्ध कराये जाते हैं जबकि इस तथ्य का उल्लेख करते समय कि दरों को बाजार की प्रथाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है, न तो वियतनाम सरकार और न ही उत्तर देने वाले नियर्तिकों ने उत्तर देने वाले नियर्तिकों द्वारा प्राप्त किये गये विभिन्न क्रृष्ण और उस पर ब्याज का कुल ब्यौरा यह सिद्ध करने के लिए दिया है कि वास्तव में ये क्रृष्ण बाजार कीमतों पर प्राप्त किये गये थे। वियतनाम सरकार ने भी अपने केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों के निर्धारण के संबंध में दस्तावेजों को दर्शाये हुए उपलब्ध कराया है।
113. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त कार्यक्रम की जांच अन्य जांच प्राधिकारियों जैसे कुछ स्टील नेल ने यू एस द्वारा किया गया है और उस पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।
114. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जा सकता है। तदनुसार, सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण नीचे दिये गये तालिका के अनुसार किया गया है।
- झ. कार्यक्रम सं. 10 : निवेश क्रेडिट क्रृष्णों के ब्याज दर**
115. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि वियतनाम सरकार वियतनाम डेवलपमेंट बैंक को एक नीतिगत बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। यह बैंक निर्णय 108/ 2006/ क्यूडी – टीटीजी के अनुसार उपक्रमों जो परियोजनाओं में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित निवेश क्रेडिट के लिए उन सात निवेशकों की सूची में हैं, को दिये जाने के लिए निवेश क्रेडिट क्रृष्ण की अनुमति देता है।
116. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि डिक्री 75 के अनुच्छेद 21 में क्रृष्ण देने के लिए ब्याज दर के प्रावधानों का उल्लेख है और उसके उप नियम (1) के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि नियर्ति क्रृष्ण देने के लिए ब्याज दरों की सूचना बाजार ब्याज दरों के साथ अनुकूलता के सिद्धांत पर प्रकाशन के लिए वित्त मंत्रालय को वियतनाम डेवलपमेंट बैंक मेनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा।” इसके अलावा, यह भी कहा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक वियतनाम सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है।

117. याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया है कि डिक्री सं. 75/ 2011/ एनडी-सीपी एकमात्र अध्यतीत कानूनी पाठ डिक्री 151/ 2006 / एनडी-सीपी का है और इसमें पुराने डिक्री के विभिन्न प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तनों करने का प्रावधान है जिसमें वियतनाम डेवलपमेंट बैंक के निवेश ऋण और निर्यात ऋण कार्यक्रमों दोनों के लिए संगत प्रावधान शामिल है।
118. याचिकाकर्ताओं ने निवेश के लिए क्रेडिट ऋणों पर विनियमों के संबंध में परिपत्र सं. 76/ 2015/ टीटी-वीटीसी का भी संदर्भ लिया जिसमें निवेश क्रेडिट ऋण और निर्यात क्रेडिट ऋण के लिए व्याज दर का उल्लेख है।
119. वियतनाम सरकार ने उल्लेख किया कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो बैंकों को वियतनाम में राज्य अथवा राष्ट्रीय नीति के आधार पर कार्य करने की अनुमति देता हो और यह कि वाणिज्यिक बैंक ऋण प्राप्तकर्ताओं के संबंध में विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद स्वतंत्र रूप से उधार देने का निर्णय कर सके और इन निर्णयों का सरकारी प्राधिकारी से कोई संबंध नहीं है।
120. उत्पादकों/ निर्यातकों ने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा, डिक्री दस्तावेज यह दर्शते हैं कि केवल कुछ सरकार के निवेश जो डिक्री सं. 75/ 2011/ एनडी-सीपी के परिशिष्ट । के अंतर्गत सूचीबद्ध है, लाभ के लिए पात्र है।
121. प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को नोट करते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त कार्यक्रम की जांच अन्य जांच प्राधिकारियों जैसे कुछ स्टील नेल ने यू एस द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।
122. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जा सकता है। तदनुसार, सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण नीचे दिये गये तालिका के अनुसार किया गया है।
- व. **कार्यक्रम सं. 11 : विदेशी निवेशकों जिन्होंने लघु और मध्यम उपक्रमों को स्थापित करने पर निवेश किया है, पर निवेश सहायता पर**
123. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि वियतनाम सरकार ने लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए निवेश परियोजनाओं को आसान बनाने और इसका समर्थन करने के उद्देश्य से लघु और मध्यम उपक्रमों को स्थापित करने के लिए विदेशी निवेशकों को निवेश सहायता उपलब्ध कराई है।
124. वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया है कि लघु और मध्यम आकार के उपक्रमों (एस एम ई) के विकास को आसान बनाने के उद्देश्य से, वियतनाम सरकार ने एस एम ई की सहायता के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु डिक्री सं. 56/ 2009/ एनडी-सीपी जारी किया है जो व्यापार के किसी रूप अथवा प्रकार पर विचार किये बिना पूरे देश भर में एस एम ई पर लागू होता है। योजना और निवेश मंत्रालय (एम पी आई) लघु और मध्यम आकार के उपक्रमों के विकास को सहायता का एकीकृत राज्य प्रबंधन करने में सरकार को सहायता देने और उसके बाद एस एम ई के लिए सहायता के संबंध में सरकार की नीति का कार्यान्वयन के बारे में दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए निकाय के रूप में कार्य करता था। स्थानीय प्राधिकारी केंद्र सरकार के सिद्धांतों और मार्गदर्शनों के आधार पर एस एम ई सहायता कार्यक्रमों को डिजाइन करने और उसका कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है।
125. वियतनाम सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि विनलॉग स्टेनलैस स्टील कं. लिमि. एक एस एम ई के रूप में योग्य कंपनी है। विनलॉग ने आवेदन नहीं किया और इसे इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिला है। किसी भी उत्तर देने वाले निर्यातकों ने इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है।
126. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त कार्यक्रम का मूल्यांकन जांच अन्य जांच प्राधिकारियों जैसे कुछ स्टील नेल ने यू एस द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।
127. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जा सकता है। तदनुसार, सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण नीचे दिये गये तालिका के अनुसार किया गया है।

**ट. कार्यक्रम सं. 13 : वियतिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी**

128. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि वियतिन बैंक जो राज्य के स्वामित्व वाला वाणिज्यिक बैंक है, वियतनाम के घरेलू वस्तुओं के निर्यात पर वित्तीय गारंटी प्रदान करता है और इस उपक्रम से निर्यात कार्य निष्पादन का संवर्धन करता है।
129. वियतनाम सरकार ने इस सबिसडी कार्यक्रम के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और यह उल्लेख किया है कि जांच के अधीन किसी भी कंपनी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, उत्तर देने वाले कुछ उत्पादक/ निर्यातकों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने उक्त लाभ प्राप्त किया है लेकिन यह विचाराधीन उत्पाद के लिए नहीं प्राप्त किया।
130. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह कार्यक्रम ऋण संस्थाओं को अपेक्षित प्रावधान को पूरा करने वाले उपक्रमों को वित्तीय गारंटी प्रदान करने की अनुमति देता है। जिन्होंने इसके लिए निम्नलिखित कानूनी आधार उद्धृत किया है।  
 अनुच्छेद 3, नियम (1) बैंक गारंटी को “एक तरह का क्रेडिट देने जो गारंटी पक्षकार लिखित रूप में गारंटी प्राप्त करने वाले पक्षकार के साथ करता है कि यह गारंटी दिये गये पक्षकार द्वारा वित्तीय दायित्व को नहीं निभाये जाने की स्थिति में गारंटी दिये गये पक्षकार के वित्तीय दायित्व को निभायेगा अथवा अपर्याप्त रूप से गारंटी प्राप्त करने वाले पक्षकार के साथ किये गये वित्तीय दायित्व का निर्वहन करेगा; गारंटी दिये गये पक्षकार को ऋण अपने ऊपर लेना होगा और करार के रूप में गारंटी दिये गये पक्षकार के लिए ऋण चुकाना होगा।” के रूप परिभाषित करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 11 नियम (2) (क) के अनुसार क्रेडिट संस्थाओं जो गारंटी का लाभ दे रहे हैं को स्टेट बैंक द्वारा व्यापार करने और ऐसी सेवा देने के लिए अलग से लाइसेंस दिया जाना चाहिए।
131. वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उन उपक्रमों को निर्यात व्यापार का विस्तार करने के लिए गारंटी प्राप्त करने हेतु अनुमति देता है जिसका भुगतान क्रेडिट संस्था अथवा वाणिज्यिक बैंक अधिमान्य व्याज दर पर बाद में किया जाना है।
132. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जा सकता है। तदनुसार, सबिसडी के मार्जिन का निर्धारण नीचे दिये गये तालिका के अनुसार किया गया है।

**ठ. कार्यक्रम सं. 14 : डिक्री 142 के अंतर्गत प्रोत्साहित उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों में उपक्रमों के लिए भूमि अधिमान्यता**

**ड. कार्यक्रम सं. 15 : समुचित प्रतिफल से कम और भूमि एवं जल के लगानों से छूट अथवा कमी के लिए भूमि का सरकारी प्रावधान**

133. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि वियतनाम की सरकार ने विशेष रूप से कठिन आर्थिक – सामाजिक स्थितियों के क्षेत्रों में निवेश परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उपक्रम को प्रोत्साहित करने के वास्ते भूमि आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया है। निवेश परियोजनाओं में शामिल और विशिष्ट क्षेत्रों, अंचलों में स्थित उपक्रमों और इन उपक्रमों जो प्रोत्साहित उद्योग के रूप में सूचीबद्ध हैं को भूमि के लगान के भुगतान के छूट और कमी से सूचित किया जाता है।
134. वियतनाम की सरकार ने उल्लेख किया है कि भौगोलिक क्षेत्रों और विशेष रूप से कठिन सामाजिक आर्थिक स्थितियों वाले क्षेत्रों में निवेश करने के लिए उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वियतनाम की सरकार इन कंपनियों जिनकी इस प्रकार के क्षेत्रों में निवेश परियोजनाएं हैं के लिए भूमि के लगान में छूट और कमी की नीति का अनुसरण करता है। भूमि के लगान में छूट विशेष मामलों जैसे गरीब कामगारों के लिए रहने के लिए घरों का निर्माण, विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए छात्रावास, पर्वतीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए कृषि भूमि में निवेश परियोजनाओं तथा प्रोत्साहित उद्योगों में निवेश परियोजनाओं पर भी लागू होता है। अपने निवेश प्रमाण पत्र अथवा व्यापार पंजीकरण के आधार पर, संबंधित स्थानीय कर प्राधिकारी भूमि के किरायेदारों द्वारा भुगतान योग्य राशि का

निर्धारण करते हैं। उत्तर देने वाले किसी भी नियांतक ने उक्त लाभ को प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, इस कार्यक्रम के संचालन से संबंधित संगत दस्तावेजों का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, वियतनाम की सरकार ने विचाराधीन उत्पाद के उत्तर देने वाले अथवा उत्तर न देने वाले नियांतकों को लाभ न दिये जाने को दर्शाये हुए कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है।

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं उक्त कार्यक्रम की जांच अन्य जांच अधिकारियों द्वारा विगत में की गई है जिसमें कोल्ड रॉल्ड स्टील और कॉपर फिटिंग में कनाडा, पोलीस्टर स्टेपल फाइबर में यूरोपीय यूनियन द्वारा किया हुआ मूल्यांकन शामिल है और उस पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।
136. प्राधिकारी समुचित प्रतिफल से कम के लिए भूमि के प्रावधान के संबंध में वियतनाम सरकार और नियांतकों के निम्नलिखित तर्कों को नोट करते हैं :
- (i) यदि कोई निवेशक चाहे वह विदेशी अथवा स्वदेशी हो, डेवलपर सहित निजी स्रोत से एल यू आर प्राप्त करता है जिसके लिए एल यू आर पहले ही कारखाना अथवा कंपनी के परिसर को स्थापित करने के लिए मंजूर किया गया था, एल यू आर अंतरण कीमत का निर्धारण इन पक्षकारों के बीच निःशुल्क समझौते के द्वारा किया जायेगा।
  - (ii) इस स्थिति में जहां निवेशक राज्य से भूमि के आवंटन और भूमि के पट्टे के माध्यम भूमि का एक हिस्से का एल यू आर प्राप्त करता है तब भूमि के आवंटन और भूमि के पट्टे की कीमत का निर्धारण मुख्य रूप से नीलामी विजेता की कीमत के आधार पर किया जायेगा। नीलामी के लिए आंभिक कीमत इस कीमत सूची से कम नहीं होगी जो प्रांतीय जन समिति द्वारा घोषित भूमि के भाग के लिए है। कीमत की सूची की औपचारिक घोषणा प्रांतीय जन समिति द्वारा आरंभिक वर्ष के 01 जनवरी को प्रत्येक पांच साल के बाद किया जाता है (अनुच्छेद 114, भूमि कानून 2013)। हंग येन, हनोई, लॉग एन एंड टियान गियान के चार प्रांतों द्वारा घोषित कीमत सूची का नमूना अनुबंध 7.2 में दिया गया है।
  - (iii) यदि कोई नीलामी नहीं होती है तब स्थानीय सरकार सामान्य परिस्थितियों में भूमि के वास्तविक मूल्य के आधार पर ("विशिष्ट भूमि कीमत") के आधार पर भूमि के उस हिस्से की कीमत का निर्धारण करेगा, जिसमें भूमि की कीमत के मूल्यांकन के लिए परिषद् की भागीदारी शामिल है। भूमि की कीमत के मूल्यांकन के लिए परिषद् ने स्थानीय जन समिति (प्रांतीय स्तर) के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में, संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि और वह संगठन जो भूमि की कीमत के निर्धारण के संबंध में परामर्श देता है, के प्रतिनिधि शामिल हैं। (अनुच्छेद 114, भूमि कानून 2013)।
  - (iv) निर्धारित भूमि कीमतों को सुनिश्चित करना बाजार की कीमत के अनुरूप है, वियतनाम की सरकार भूमि की कीमत निर्धारण की पांच पद्धतियों अर्थात् प्रत्यक्ष तुलना पद्धति, घटाव पद्धति, आय आधारित पद्धति, अतिरिक्त आधारित पद्धति और भूमि कीमत गुणक पद्धति का उपयोग करता है। इन पद्धतियों और उनके उपयोगों का ब्यौरा भूमि की कीमतों से संबंधित विनियमों पर डिक्री संख्या 44/ 2014/ एनडी-सीपी के अनुच्छेद 4 और 5 में दिया गया है। इन कीमत निर्धारण पद्धतियों का व्यापक रूप से उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। उन्हें न केवल विशिष्ट भूमि की कीमत का निर्धारण करने में बल्कि प्रांतीय स्तर के प्राधिकारियों द्वारा भूमि की कीमत की सूची तैयार करने में भी लागू किया जाता है।
  - (v) एल यू आर को रद्द करने के संबंध में, राज्य निम्नलिखित मामलों में एल यू आर प्राप्त कर सकता है (खंड 1, अध्याय VI, भूमि कानून 2013) :
    1. राष्ट्रीय सुरक्षा; राष्ट्रीय और जनहित में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए; अथवा
    2. भूमि संबंधी कानून और विनियमों के उल्लंघन के कारण;

3. कानून के अनुसार भूमि के उपयोग का निर्धारण, भूमि की स्वैच्छिक वापसी अथवा मानव जीवन को खतरा उत्पन्न करने के जोखिम के कारण।

इस प्रकार से यदि एल यू आर की वसूली राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय और जनहित में आर्थिक सामाजिक विकास के लिए किया जाता है तब राज्य भूमि के मालिक को एल यू आर की क्षतिपूर्ति और एल यू आर मालिक से भूमि पर बचे हुए निवेश की लागत की क्षतिपूर्ति करेगा।

137. इस प्रकार से वियतनाम सरकार ने यह तर्क दिया कि न तो वियतनाम सरकार ने विचाराधीन उत्पाद (रोल्ड किया हुआ स्टेनलैस पाइप और ट्यूब) उद्योग को अथवा उन क्षेत्रों को जहां विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक स्थित हैं, को कमतर अथवा कोई पट्टा लगान नहीं जैसा विशिष्ट लाभ दिया है और न ही विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है।
138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस भूमि पर वियतनाम सरकार का मालिकाना हक है और भूमि की कीमत का निर्धारण उनके द्वारा किया गया है और यूरोपीय यूनियन, यू एस और कनाडा जैसे कुछ प्राधिकारियों ने इन कार्यक्रमों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया है।
139. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जा सकता है। तदनुसार, सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण नीचे दिये गये तालिका के अनुसार किया गया है।

### अकथित सब्सिडी

“स्थायी संपत्ति सृजित करने के लिए उपकरण और मशीनरी के लिए आयात शुल्क में छूट”

140. वियतनाम की सरकार ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में यह उल्लेख किया कि ‘कच्चे माल के लिए आयात शुल्क में छूट अथवा प्रतिपूर्ति’ के अलावा, अन्य ‘स्थायी संपत्ति सृजित करने के लिए उपकरण और मशीनरी के लिए आयात शुल्क में छूट’ हैं। इस कार्यक्रम का संचालन वित्त मंत्रालय वियतनाम सीमा शुल्क विभाग (जी डी वी सी) द्वारा किया जाता है।
141. स्थायी संपत्ति सृजित करने के लिए उपकरण और मशीनरी के लिए आयात शुल्क में छूट आयात और निर्यात शुल्क 2016 संबंधी कानून के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। आयात और निर्यात शुल्क 2016 संबंधी कानून और डिक्री 134/ 2016/ एनडी-सीपी के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि निवेश अधिमान्यता के अध्यधीन कंपनियों के लिए स्थायी संपत्तियों को सृजित करने हेतु आयात की गई वस्तु को आयात शुल्कों से छूट मिलती है। आयात की गई इन वस्तुओं ने मशीनरी और उपकरण संघटक, कलपुर्जे, मशीनरी और उपकरण की एसेम्बली अथवा प्रचालन के लिए स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और उपकरण के निर्माण के लिए कच्चा माल, संघटक, हिस्सा अथवा मशीनरी और उपकरण का स्पेयर पार्ट्स, निर्माण परियोजना के लिए प्रत्यक्ष रूप में उपयोग किये जाने वाले प्रौद्योगिकीय रूप में विशेष उपयोग वाहन और निर्माण से संबंधित इन सामग्रियों जिनका घेरलू स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, शामिल है।
142. वियतनाम की सरकार ने यह उल्लेख किया कि डाई डुआग ने 2010 में स्थायी परिसंपत्तियों को सृजित करने के लिए केवल उपकरण और मशीनरी का आयात किया है और इस प्रकार से इसे 2010 में अर्थात् जांच की अवधि से काफी पहले के समय में यह लाभ प्राप्त हुआ। चूंकि यह लाभ औसत उपयोगी जीवन के लिए उक्त लाभ के वास्ते पूँजीगत परिसंपत्तियों को दिया जाता है और इस कारण से डाई डुआग ओ एस एस ने इस लाभ को प्राप्त किया है।
143. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जा सकता है। तदनुसार, सब्सिडी के मार्जिन का निर्धारण नीचे दिये गये तालिका के अनुसार किया गया है।

### वियतनाम में सी वी डी योजनाओं के संबंध में निष्कर्ष

144. पूर्व में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए प्राधिकारी यह पाते हैं कि वियतनाम के उत्पादकों को प्रतिकारणीय सब्सिडी से लाभ मिल रहा है। की गई जांचों, रिकार्ड में तथ्यों और विगत में की गई जांचों के आधार पर तथा विचाराधीन

उत्पाद के वियतनाम से कुछ भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों से पूरा सहयोग न मिलने पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने नीचे दी गई तालिका में दर्शये गये अनुसार विभिन्न सब्सिडी योजनाओं और सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया है। प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि सी बी डी मार्जिन की मात्रा मैसर्स सोन्हा एस एस पी वियतनाम सोल मेस्टर कं. लिमि. और मैसर्स स्टील 568 कं. लिमि. को छोड़कर बहुत अधिक और न्यूनतम से ऊपर रहा है।

कार्य सं.	कार्यक्रम का नाम	सोन हा एस एस पी वियतनाम	नाम कुआंग एवं टुआन डाट मेटल कंपनी लि.	डाई डुआंग ओ एस एस कं. लिमि.	गियाआन हुंग येन एवं गिया अन्ह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
कार्य.1	विक्री 24 के अध्याय V के अंतर्गत आयकर अधिमान्यता (उपक्रम आयकर संबंधी कानून का कार्यान्वयन)	NIL			
कार्य.3	उपक्रमों के लिए कोरपोरेट आयकर पर छूट		NIL	0-5%	0-5%
कार्य.2	कच्चे माल के लिए क्षतिपूर्ति पर आयात शुल्क छूट	NIL	NIL	NIL	NIL
कार्य.5	निर्यातकों को अधिमान्य ऋण देना	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
कार्य.6	निर्यात संबद्धन कार्यक्रम	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
कार्य.7	वियतनाम डेवलपमेंट बैंक से निर्यात ऋण	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
कार्य.8	निर्यात सहायता ऋण	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
कार्य.9	निवेशकों के लिए अधिमान्य ऋण देना	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
कार्य.10	निवेश ऋण का ब्याज दर	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
कार्य.11	विदेशी निवेशकों जिन्होंने लघु और मध्यम उपक्रमों को स्थापित करने पर निवेश किया है को निवेश सहायता	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
कार्य.13	वियतन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
कार्य.14	विक्री 142 के अंतर्गत प्रोत्साहित उद्योगों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में उपक्रमों के लिए भूमि अधिमान्यता	0-5%			
कार्य.15	भूमि और जल के लगान से उचित पारिश्रमिक और छूट अथवा कमी की तुलना में कम भूमि का सरकारी प्रावधान		0-5%	0-5%	0-5%
अन्य	स्थाई परिसंपत्ति का सर्जन करने के लिए उपकरण और मशीनरी के लिए आयात शुल्क छूट	NIL	0-5%	0-5%	0-5%

कार्य. सं..	कार्यक्रम का नाम	सोन हा एस एस पी वियतनाम	नाम कुआंग वियतनाम एवं टुआन डाट मेटल कंपनी लि.	डाई डुआंग ओ एस एस कं. लिमि.	गियाआन हुंग येन एवं गिया अन्ह जवाइंट स्टॉक कंपनी
	<b>कुल सब्सिडी मार्जिन %</b>	न्यूनतम	***	***	***
	<b>कुल सब्सिडी मार्जिन (रेंज %)</b>	न्यूनतम	<b>10-20%</b>	<b>10-20%</b>	<b>10-20%</b>
कार्य. सं.	कार्यक्रम का नाम	हा अन्ह स्टेनलैस स्टील कं. लिमि.	विनलॉग स्टेनलैस स्टील (वियतनाम) कं. लिमि.	स्टील 568 कं. लिमि.	शेष
कार्य.1	विक्री 24 के अध्याय V के अंतर्गत आयकर अधिमान्यता (उपक्रम आयकर संबंधी कानून का कार्यान्वयन)				
कार्य.3	उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट आयकर पर छूट	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
कार्य.2	कच्चे माल के लिए क्षतिपूर्ति पर आयात शुल्क छूट	NIL	NIL	NIL	NIL
कार्य.5	निर्यातकों को अधिमान्य ऋण देना	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
कार्य.6	निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
कार्य.7	वियतनाम डेवलपमेंट बैंक से निर्यात ऋण	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
कार्य.8	निर्यात सहायता ऋण	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
कार्य.9	निवेशकों के लिए अधिमान्य ऋण देना	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
कार्य.10	निवेश ऋण का ब्याज दर	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
कार्य.11	विदेशी निवेशकों जिन्होंने लघु और मध्यम उपक्रमों को स्थापित करने पर निवेश किया है को निवेश सहायता	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
कार्य.13	वियतिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
कार्य.14	विक्री 142 के अंतर्गत प्रोत्साहित उद्योगों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में उपक्रमों के लिए भूमि अधिमान्यता				
कार्य.15	भूमि और जल के लगात से उचित पारिश्रमिक और छूट अथवा कमी की तुलना में कम भूमि का सरकारी प्रावधान	0-5%	0-5%	0-5%	0-5%
अन्य	स्थाई परिसंपत्ति का सर्जन करने के लिए उपकरण और मशीनरी के लिए आयात शुल्क छूट			NIL	

कार्य सं..	कार्यक्रम का नाम	सोन हा एस एस पी वियतनाम	नाम कुआंग वियतनाम एवं टुआन डाट मेटल कंपनी लि.	डाई डुआंग ओ एस एस कं. लिमि.	गियाआन हुंग येन एवं गिया अन्ह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
		0-5%	0-5%		0-5%
	<b>कुल सब्सिडी मार्जिन %</b>	***	***	न्यूनतम	***
	<b>कुल सब्सिडी मार्जिन (रेंज %)</b>	<b>10-20%</b>	<b>10-20%</b>	न्यूनतम	<b>10-20%</b>

**ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध****ज. 1. घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन**

145. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :

- क. संबद्ध देशों से काफी अधिक मात्रा में आयात हुआ है जो क्षति की अवधि के दौरान 662 प्रतिशत तक बढ़ा है।
- ख. केवल एक वर्ष की अवधि के भीतर संबद्ध आयातों ने 2016-17 में \*\*\* मी. ट. जांच की अवधि में \*\*\* मी. ट. तक लगभग 3.5 गुणा वृद्धि हुई है।
- ग. संबद्ध देशों से आयातों में 2016-17 से 2017-18 तक घरेलू उत्पादन में 27 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि हुई है।
- घ. आयातों में वृद्धि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि बहुत अधिक है।
- ङ. आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती हो रही है और कम कीमत पर विक्री सकारात्मक और बहुत अधिक है।
- च. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है। हालांकि लघु क्षेत्र के भाग के रूप में अधिकांश घरेलू उत्पादक, तब तक आदेश नहीं लेते हैं जब तक की उन्हें कुछ मार्जिन न मिले। इस कारण से कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास के पहलू इस तरह दृष्टिगत नहीं हो सकते हैं जैसा कि आमतौर पर रासायनिक, पैट्रोकेमिकल अथवा इस्पात उद्योगों में देखा जाता है।
- छ. घरेलू उद्योग द्वारा बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की आशा के साथ अपनी क्षमता में वृद्धि करने के बावजूद, यह समानुपातिक रूप में अपने उत्पादन और विक्री को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाया है।
- ज. घरेलू उद्योग बाजार में बहुत अधिक मांग रहने के बावजूद पूरी अवधि में \*\*\* प्रतिशत से कम क्षमता पर कार्य करता रहा है। घरेलू उद्योग के क्षमता के उपयोग में \*\*\* प्रतिशत तक गिरावट आई है।
- झ. संबद्ध आयातों ने भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से को समाप्त कर दिया है।
- ञ. एम एस एम ई उद्योग का हिस्सा होने के कारण घरेलू उत्पादक माल भंडार को रोक पाने की अनुमति नहीं दे सकता है और इस कारण से तभी उत्पादन करता है जब उनके पास आर्डर हो अथवा आर्डर बुक करने की निश्चितता हो।
- ट. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में इस अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई है।
- ठ. उद्योग का नकद लाभ और निवेश पर आय में भी गिरावट देखी गई है।
- ड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के सभी मानदंडों में गिरावट दर्ज की है और मात्रा के मानदंडों के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि आदर्श स्थिति से कम रही है।

८. आयातकों ने जांच की अवधि के बाद 6 महीने में जांच की अवधि में किये गये आयातों की 1.5 गुणा वृद्धि की है।
९. लघु स्तर पर प्रचालनों और मामूली मार्जिन के कारण अनेक घरेलू उत्पादक आयात करने के लिए बाध्य हुए हैं और कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए निर्यातकों के लिए वास्तव में कमीशन एजेंट के रूप में ही कार्य कर रहे हैं।
१०. जांच की अवधि के बाद आयातों में वृद्धि मैसर्स सोन्हा एस एस पी वियतनाम सोल मेम्बर कं. लिमि. के पत्र से क्रेडिट हुआ है इसमें आयातकों को यह आश्वासन दिया है कि कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए निर्यात किये गये उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जायेगा और यह कि लगाये गये किसी प्रतिकारी शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी।
११. यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रशुल्क कोटा लगाना, यू एस द्वारा प्रशुल्क दरों में वृद्धि और थाईलैंड एवं टर्की द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने का खतरा आगे हुआ है।
१२. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित लघु निवेश के कारण, चीन में कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) के निर्यातों में वृद्धि कर भारत द्वारा पी यू सी के कच्चे मालों पर शुल्क लगाकर प्रतिक्रिया दी है।
१३. चूंकि चीन से वियतनाम तक आयातों पर प्रशुल्क राशि चीन-आशियन करार के अंतर्गत शून्य है। अतः कच्चे मालों का निर्यात वियतनाम में किया जाता है और उसके पश्चात विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में शुल्क के रियायती दर पर किया जाता है।
१४. घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य ज्ञात कारक द्वारा नहीं पहुंचाई गई है।
१५. घरेलू उद्योग को क्षति और सम्बिंदीयुक्त आयातों के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित से स्पष्ट है :
- i. आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इस प्रकार के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके फलस्वरूप भारतीय उद्योग ने बाजार में अपना स्थान खो दिया है और यह क्षमता और मांग में वृद्धि के अनुपात में अपना उत्पादन बढ़ा पाने में सक्षम नहीं रहा है।
  - ii. घरेलू उद्योग की विक्री कीमत में कमी आई है और देखी गई प्रति इकाई के लिए धाटा उठा रहा है।
१६. इस तर्क के उत्तर कि क्षमता के उपयोग में गिरावट बढ़ती हुई मांग के कारण हुई थी। यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उद्योग बढ़ती हुई मांग के अनुरूप अपने उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाया था। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति ऐसी नहीं है कि उत्पादक को उत्पादन क्षमताओं को आदर्शतम स्तर पर लाने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता हो।
१७. क्षमता में वृद्धि बढ़ती हुई मांग के पूर्वानुमान में न्यायोचित था।
१८. किसी कर पूर्व लाभ में भी इस अवधि के दौरान गिरावट आई है अतः इस तर्क में कोई दम नहीं है कि निवेश पर आय में नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण गिरावट आई है।
१९. चूंकि निर्यात इसके कुल विक्री का 5 प्रतिशत से कम है अतः निर्यातों में संभावित कमी के कारण कोई क्षति नहीं हो सकती थी।
२०. रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि के संबंध में इन तर्कों के बारे में यह अनुरोध किया गया था कि प्रति इकाई क्षमता के रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि बढ़ती हुई क्षमता और उत्पादन के अनुरूप है। यह भी अनुरोध किया गया था कि प्रतिदिन उत्पादकता प्रतिदिन क्षमता की तुलना में बहुत कम थी।
२१. इन तर्कों के संबंध में की स्टेनलैस स्टील का भारतीय उत्पादन 2016 से 17 तक \*\*\* प्रतिशत तक बढ़ा और यह कि पाइप और ठ्यूब के उत्पादन में 2016 से 2018 तक वृद्धि हुई। यह अनुरोध किया जाता है कि कोई भी आंकड़ा विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं है। किसी भी मामले में आयातों में वृद्धि उल्लिखित उत्पादन में वृद्धि से बहुत अधिक है।

- ल. इस तर्क के संबंध में की स्टेनलैस स्टील की कीमतों में वृद्धि हुई है, यह अनुरोध किया गया था कि कुल मिलाकर स्टेनलैस स्टील के उत्पादों की कीमतों में वृद्धि भारत में संबद्ध वस्तु की कीमत में प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है क्योंकि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े आयातों की पहुंच कीमत में \*\*\* प्रतिशत तक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- व. जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री के राजस्व में वृद्धि हुई है, इसकी बिक्री कीमत में कमी आई है जिसके फलस्वरूप इसके लाभ में गिरावट हुई है।
- श. इस तर्क के संबंध में कि वियतनाम से आयातों की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, यह दर्शाया गया था कि वियतनाम से आयात संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का \*\*\* प्रतिशत और भारत में बाजार का दसवां हिस्सा है जो मामूली नहीं है।
- ष. यह तथ्य कि संबद्ध वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता भारत में अपनी वस्तुओं का \*\*\* प्रतिशत का निर्यात करता है, यह दर्शाता है कि भारत उनके प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक है।

## ज. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन

146. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :
- क. एम एम ई उत्पादकों की पहचान करने में कठिनाईयों का दावा करने के बावजूद, आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं के बाजार हिस्से, मांग और खपत का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे उत्पादकों के कार्य निष्पादन की मात्रा निर्धारित की है जो अपने आप में सही नहीं है।
- ख. उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद, क्षमता उपयोग कम रहा है जिसके फलस्वरूप उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। आवेदकों को संयोजना रिपोर्ट और अशाह क्षमता उपयोग के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।
- ग. किसी आवेदक का उत्पादन और बिक्री स्थिर रही है, यह स्पष्ट है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री कर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।
- घ. उत्पादकता में अनुपातिक वृद्धि के बिना कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय भार आया है।
- झ. क्षमता के उपयोग में गिरावट आ रही है क्योंकि याचिकाकर्ता क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- च. क्षति क्षमताओं के अनुचित/अन्यायोचित वृद्धि के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई है क्योंकि यह अपनी क्षमताओं को स्थिर रख लेने में सक्षम नहीं है जिसके फलस्वरूप नियोजित अपेक्षाकृत अधिक पूँजी, नियोजित पूँजी पर नकारात्मक आय और भारी घाटा हुआ है।
- छ. जबकि घरेलू बिक्री में \*\*\* प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, निर्यात बिक्री \*\*\* प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है जिससे क्षति हुई है।
- ज. बिक्री और उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में माल भंडार में गिरावट आई है।
- झ. बिक्री की लागत में गिरावट के साथ बिक्री की कीमत में कमी आई है।
- ञ. वियतनाम से वस्तु उसी कीमत पर आ रही है जिस कीमत पर वस्तुओं का निर्यात अन्य संबद्ध देशों से किया जाता है जबकि चीन जन. गण. से वस्तु बहुत कम कीमतों पर आ रही है।
- ट. वियतनाम से कीमत में कटौती नकारात्मक है इसका मतलब यह है कि वियतनाम से संबद्ध वस्तु क्षति रहित कीमत से अधिक कीमत पर है।

- ठ. चीन का \*\*\* प्रतिशत का हिस्सा है, वियतनाम के पास केवल \*\*\* प्रतिशत का हिस्सा है। कम कीमत पर चीन के आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और वियतनाम से आयातों तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- ड. नियोजित पूँजी पर आय क्षति की अवधि के दौरान सकारात्मक है।
- ढ. कर्मचारियों की संख्या में तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- ण. घरेलू उद्योग के समग्र कार्य निष्पादन में सुधार हो रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध से आयातों के कारण नहीं हो सकती है।
- त. संबद्ध वस्तुओं के आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति जो चीन से कम कीमत की वस्तुओं के कारण हो रही है, के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- थ. अन्य आयातों से क्षतिकारक प्रभावों को अन्य कारकों से अलग किया जाना चाहिए।
- द. भारतीय उद्योग को जांच की अवधि के दौरान वियतनाम से आयातों से वास्तविक क्षति नहीं उठानी पड़ी।
- ध. भारत में स्टेनलैस स्टील का घरेलू उत्पादन 2016 से 17 तक \*\*\* प्रतिशत की दर \*\*\* मिलियन टन से \*\*\* मिलियन टन तक वृद्धि हुई। पाइप और ट्यूब का उत्पादन 2016 से 2018 तक \*\*\* मिलियन मी. ट. से बढ़कर \*\*\* मिलियन मी. ट. तक हो गया।
- न. सभी रूपों के स्टेनलैस स्टील उत्पादों की विक्री कीमत 2016 से 2017 तक निकल, आयरन और स्क्रेप की कीमत में वृद्धि के कारण बढ़ती गई है।
- प. वियतनाम से संबद्ध वस्तुओं की औसत कीमत 2016 से 2017 तक 10 प्रतिशत तक बढ़ी।
- फ. भारत में दो सबसे बड़े उत्पादकों रतनामणि मेटल्स और ट्यूब और अपेक्ष स्टूब्स प्रा. लिमि. ने राजस्व में सतत वृद्धि दर्शायी है।
- ब. घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से हो सकती है।
- भ. भारतीय कंपनियों का निर्यात विक्री कर संयुक्त राज्य और यूरोपीय यूनियन जैसे अन्य देशों द्वारा आरंभ की गई व्यापार जांचों के प्रभाव द्वारा असर कर सकता है।
- म. वियतनाम से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जिससे कि भारतीय उद्योग के हित को तत्काल नुकसान पहुँचे।

### **ज. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

147. हितवद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किये गये विभिन्न निवेदनों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण वास्तव में याचिकाकर्ताओं और विरोधी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये निवेदनों पर विचार करता है।
148. निम्नलिखित कंपनियों द्वारा जांच आरंभन के पश्चात प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप तथा तरीके से क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की गई थी :
- क. मावन स्टेनलैस प्राइवेट लिमिटेड  
ख. नवभारत ट्यूब्स लिमिटेड  
ग. जिंदल क्वालिटी ट्यूबलर लिमिटेड  
घ. एस एन पी स्टील्स  
ड. जे एन बी स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड  
च. रेमी इंडस्ट्रीजल ट्यूबुलर्स लिमिटेड  
छ. बंगल पाइप मैन्यूफैक्चरिंग कं.
- ज. रवि स्टेनलैस स्टील्स  
झ. क्वालिटी स्टेनलैस

- ट. एएसबी ट्यूब्स
149. निम्नलिखित कंपनियों के आंकड़ों पर वर्तमान जांचों के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में क्षति निश्चारण के प्रयोजन से सामूहिक रूप से विचार किए गए हैं :-
- क. हिसार स्टील्स प्रा. लिमिटेड  
 ख. पी.एस. राज स्टील्स प्रा. लिमिटेड  
 ग. विकास स्टेनलैस प्रा. लिमिटेड  
 घ. रैमसंस स्टेनलैस  
 ङ. सांझी मेटल्स प्रा. लिमिटेड  
 च. शिव गंगा स्टेनलैस  
 छ. पारस भवानी स्टील्स प्रा. लिमिटेड  
 ज. जे एस एस स्टीलिटालिया लिमिटेड  
 झ. राजरत्ना वेन्टर्स लिमिटेड  
 ट. सुमन स्टील इंडस्ट्रीज  
 ठ. तिरुपति ट्यूब्स लिमिटेड  
 ड. मावेन स्टेनलैस प्रा.लि.  
 ढ. नवभारत ट्यूब्स लिमिटेड  
 ण. जिंदल क्वालिटी ट्युबलर लिमिटेड  
 त. एस एन पी स्टील्स  
 थ. जेएनबी स्टील इंडस्ट्रीज प्रा.लि.  
 द. रेमी एडेलस्टथल ट्युबलर्स लिमिटेड  
 ध. बंगाल पाइप मैन्युफैक्चरिंग कं.
- न. रवि स्टेनलैस स्टील्स  
 क. मांग का आकलन

150. भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्री और सभी अन्य देशों से आयातों के योग के रूप में किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
संबद्ध आयात	मी. ट.	9,391	17,254	20,594	71,593
अन्य आयात	मी. ट.	1,317	1,855	3,141	6,798
घरेलू उद्योग की विक्री	मी. ट.	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों की विक्री	मी. ट.	***	***	***	***
<b>मांग/ खपत</b>	<b>मी. ट.</b>	<b>191,137</b>	<b>201,197</b>	<b>223,553</b>	<b>248,392</b>

151. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

#### I. आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

152. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
चीन जन. गण.	मी. ट.	4,411	3,630	6,702	43,059
वियतनाम	मी. ट.	4,980	13,624	13,892	28,535

संबद्ध आयात	मी. ट.	9,391	17,254	20,594	71,593
अन्य आयात	मी. ट.	1,317	1,855	3,141	6,798
<b>कुल आयात</b>	<b>मी. ट.</b>	<b>10,708</b>	<b>19,109</b>	<b>23,735</b>	<b>78,392</b>
<b>निम्नलिखित की तुलना में आयात</b>					
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***
खपत	%	5%	9%	9%	29%
<b>कुल आयात</b>	<b>%</b>	<b>88%</b>	<b>90%</b>	<b>87%</b>	<b>91%</b>

153. यह देखा गया है कि :

- क. संबद्ध देशों से आयातों की संपूर्ण मात्रा में 662 प्रतिशत तक बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- ख. आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में \*\*\* प्रतिशत से \*\*\* प्रतिशत तक तेजी से वृद्धि हुई है।
- ग. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में तेजी से वृद्धि हुई है और ये आयात मांग का 29 प्रतिशत है।
- घ. ये आयात बहुत रूप से संबद्ध देशों से हुये हैं जो आयातों में हिस्से का 91 प्रतिशत है।

## II. आयात का कीमत संबंधी प्रभाव

154. कीमतों पर आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत से तुलना किये जाने पर आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक कीमतों में कमी होगी अथवा कीमत में वृद्धि रूप जायेगी, जो काफी हद तक अन्य प्रकार से हुआ होता।

### क. कीमत में कटौती

155. कीमत में कटौती जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल विक्री प्राप्ति से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करने पर निर्धारित किया गया है। कीमत में कटौती का निर्धारण प्रत्येक पी सी एन के लिए पृथक रूप से किया गया है और इसके पश्चात विचाराधीन उत्पाद के लिए संपूर्ण रूप में किया गया है।

विवरण	इकाई	200 सीरिज	300 सीरिज	भारित औसत
<b>चीन जन. गण.</b>				
आयात की मात्रा	मी. ट.	33,438	9,094	42,532
पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	101,245	151,589	112,010
निवल विक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज %	10-20%	20-30%	10-20%
<b>वियतनाम</b>				
आयात की मात्रा	मी. ट.	2,611	25,923	28,535
पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	111,606	159,348	154,979
निवल विक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***

विवरण	इकाई	200 सीरिज	300 सीरिज	भारित औसत
कीमत में कटौती	रेंज %	0-10%	10-20%	10-20%

156. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अलावा, कीमत में कटौती वियतनाम से 200 सीरिज के पी यू सी के आयात को छोड़कर अधिक है। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि चीन का 78 प्रतिशत आयात 200 सीरिज का था, वियतनाम का 91 प्रतिशत आयात 300 सीरिज का था। घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमतों के आधार पर, यह देखा गया है कि 200 सीरिज और 300 सीरिज के पाइपों के बीच कीमत में अंतर 75 प्रतिशत तक है।

#### क. कम कीमत पर बिक्री

157. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमतों का निर्धारण किया है और उसकी तुलना आयात किये गये वस्तुओं के पहुंच मूल्य से की है ताकि कम कीमत पर बिक्री की सीमा तय की जा सके। कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण प्रत्येक पी सी एन के लिए पृथक रूप से और उसके पश्चात विचाराधीन उत्पाद के लिए संपूर्ण रूप में किया गया है।

विवरण	इकाई	200 सीरिज	300 सीरिज	भारित औसत
<b>चीन जन. गण.</b>				
आयात की मात्रा	मी. ट.	33,438	9,094	42,532
पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	101,245	151,589	112,010
क्षति रहित कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. ट.	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	10-20%	10-20%	10-20%
<b>वियतनाम</b>				
आयात की मात्रा	मी. ट.	2,611	25,923	28,534
पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	111,606	159,348	154,979
क्षति रहित कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. ट.	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	0-10%	10-20%	10-20%
विवरण	इकाई	200 सीरिज	300 सीरिज	भारित औसत

158. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है और यह दर्शाती है कि बाजार में आयात क्षति कारक कीमतों पर हुई है।

#### ख. कीमत न्यूनीकरण और ह्रास

159. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की आयातों के प्रभाव से कीमतों ने बहुत अधिक हद तक कमी आयेगी और कीमत में वृद्धि रूप जायेगी जो अन्य प्रकार से हुई होती। प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयातों की पहुंच कीमत और लागत एवं कीमतों में परिवर्तन की जांच की है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	88	96

बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	88	95
पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	143,488	138,290	129,110	129,136
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	90	90

160. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग कीमत और बिक्री की लागत दोनों में कमी आई है। आगे यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में 10 प्रतिशत तक गिरावट आई और यह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों और संबद्ध वस्तुओं की लागत से बहुत कम है। यह दर्शाता है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं और कीमत में वृद्धि रुक रही है जो अन्य प्रकार से हुई होती।

### III. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

161. इस नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर इन आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; वे कारक जो घरेलू कीमतें, नकदी के प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच क्षति के अवधि के दौरान की गई है।

#### क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग एवं बिक्री

162. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग एवं बिक्री के संबंध में क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
क्षमता	मी. ट.	1,10,385	1,18,835	1,29,735	1,39,005
उत्पादन	मी. ट.	58,743	65,172	66,873	73,927
क्षमता का उपयोग	%	53%	55%	52%	53%
घरेलू बिक्री	मी. ट.	56,198	63,095	66,091	72,471

163. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि इस उत्पाद की मांग में \*\*\* मी. ट. तक वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग क्षमताओं में केवल \*\*\* मी. ट. तक वृद्धि हुई। हालांकि, घरेलू उद्योग में क्षमता के उपयोग को बढ़ाने में सक्षम नहीं था और लगभग आधी क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। हालांकि, उत्पादन में वृद्धि मांग अथवा क्षमता में वृद्धि के अनुपात में नहीं थी। जबकि क्षमता में \*\*\* मी. ट. वृद्धि हुई, उत्पादन में केवल \*\*\* मी. ट. तक वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग का क्षमता का उपयोग बहुत कम रहा।
- ग. घरेलू उद्योग की बिक्री में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, यह नोट किया गया है कि जबकि भारतीय उद्योग की बिक्री पूर्व में इसकी क्षमताओं की तुलना में कम थी और इसका कारण मांग का न होना था, घरेलू उद्योग को मांग में बहुत अधिक वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि में कम बिक्री की मात्रा के कारण घाटा उठाना पड़ा।

### ख. बाजार हिस्सा

164. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादक का बाजार हिस्सा नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
संबद्ध आयात	%	5%	9%	9%	29%
अन्य आयात	%	1%	1%	1%	3%
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
संपूर्ण रूप में घरेलू उत्पादक	%	94%	91%	89%	68%

165. यह नोट किया जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2015-16 में वृद्धि हुई और उसके पश्चात् इसमें गिरावट आती रही है, संपूर्ण रूप में घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है और संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में विशेष रूप से जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इन आयातों में भारत में क्षमताओं के मौजूद होने के बावजूद भारतीय उत्पादकों के बहुत बड़े बाजार हिस्से को ले लिया गया है।

### ग. माल भंडार

166. संबद्ध वस्तुओं के माल भंडारों के संबंध में आंकड़े नीचे दिये गये अनुसार हैं :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आरंभिक माल भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
अंतिम माल भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
औसत माल भंडार	मी. ट.	***	***	***	***

167. यह नोट किया जाता है कि औसत माल भंडार में 2015-16 में वृद्धि हुई और इसके बाद उसने गिरावट दर्शायी है।

### घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय

168. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता की स्थिति नीचे दिये गये अनुसार थी :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लाभ/ हानि	रु./ मी. ट.	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-610	-305	-241
कर पूर्व लाभ	रु. लाख	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-685	-359	-311
प्रति इकाई नकद लाभ	रु./ मी. ट.	***	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-44	43	91
नकद लाभ	रु. लाख	***	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-49	51	117
नियोजित पूँजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	36	44	62

169. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

- क. घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान वित्तीय हानि होती रही है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा उठाये गये घाटे में बिक्री में वृद्धि के बावजूद क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई।
- ग. घरेलू उद्योग के नकद घाटे और नियोजित पूँजी पर आय की भी वही प्रवृत्ति रही है।
- घ. जांच की अवधि के दौरान आय 2014-15 में आय की तुलना में बहुत कम है और यह उचित स्तर से बहुत कम है।

#### **ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

170. क्षति की अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मजदूरी	लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	131	209
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रति दिन उत्पादकता	मी. ट./ दिन	***	***	***	***

171. यह देखा गया है कि मजदूरी और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि के साथ कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

#### **च. वृद्धि**

172. घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभ के मानदंडों की प्रवृत्ति ने नीचे दिये गये अनुसार दर्शाया है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
उत्पादन	%	-	11%	3%	11%
घरेलू बिक्री	%	-	12%	5%	10%
प्रति इकाई लाभ	%	-	-510%	50%	21%
प्रति इकाई नकद लाभ	%	-	-149%	204%	130%
नियोजित पूँजी पर आय	%	-	-64%	22%	41%

173. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों ने वृद्धि को दर्शाया है। हालांकि, कीमत मानदंडों में गिरावट रही है। लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय में भी क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट दर्शायी है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2015-16 में तेजी से गिरावट आई और उसके पश्चात पूर्ण रूप से इसमें सुधार नहीं हुआ है।

#### **छ. पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता**

174. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने पूँजी निवेश करते हुए इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता में वृद्धि की है। हालांकि, मांग में वृद्धि के बावजूद, ये क्षमताएं पर्याप्त रूप से कम उपयोग किये हुए रही हैं। जबकि विगत में कम क्षमता उपयोग मांग में कमी के कारण हुई थी, वर्तमान में निम्न क्षमता उपयोग आयातों में वृद्धि के कारण हुई है।

**ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

175. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती रही है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति के अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में कमी आई है। यह दर्शाता है कि आयात कम कीमतों पर बाजार में पहुंच रहे हैं।

**IV. वास्तविक क्षति से संबंधित मानदंडों का सारांश**

176. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। कम कीमत पर विक्री भी सकारात्मक है। जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम है। यद्यपि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन विक्री और क्षमता के मामले में सुधार आया है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को कम उपयोग की गई क्षमताओं से हानि हो रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को हानि हुई है और निवेश पर इसकी आय कम है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

**V. कारणात्मक संबंध**

177. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को नीचे दिये गये अनुसार क्षति हो सकती थी :

**क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत**

178. चूंकि अन्य देशों से आयात बहुत अधिक नहीं हैं अतः जिसके इसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती थी।

**ख. मांग का संकुचन और खपत के प्रकरण में परिवर्तन**

179. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके विपरीत, संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग में क्षति की अवधि के दौरान सुधार देखा गया है। इसके अलावा, खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

**ग. विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापक प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा**

180. कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

**घ. प्रौद्योगिकी में विकास**

181. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी में किसी परिवर्तन को दर्शनी के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

**इ. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन**

182. क्षति से संबंधित सूचना पर घरेलू और निर्यात के लिए उस सीमा तक पृथक रूप से विचार किया गया है जिस सीमा तक उसे अलग किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कुल विक्री के अनुपात में बहुत अधिक नहीं है। वास्तव में यह देखा गया है कि उत्पादन का लगभग 98 प्रतिशत घरेलू बाजार में बेचा गया है। निर्यात की मात्रा अथवा लाभ में संभावित गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती थी।

**च. अन्य उत्पादों जिनका घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और जिन्हें बेचा जा रहा है का कार्य निष्पादन**

183. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की तुलना में ही इन आंकड़ों पर विचार किया है। इस कारण से अन्य उत्पादों जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जा रहा है और जिन्हें बेचा जा रहा है, का कार्य निष्पादन संगत नहीं है।

## **VI. कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष**

184. जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों में क्षति नहीं पहुंचाई है, निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति समिड़ीयुक्त आयातों से होती है।
- क. ये आयात संबद्ध वस्तुओं को समिड़ी दिये जाने के कारण उन कीमतों पर घरेलू बाजार में हो रहा है जो घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में बहुत कम है।
  - ख. इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत में गिरावट आई है क्योंकि इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई और कीमत वृद्धि रूक गई जो अन्य प्रकार से हुई होती।
  - ग. सकारात्मक कीमत में कटौती के फलस्वरूप विदेशी उत्पादकों से बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
  - घ. जबकि घरेलू उद्योग का उत्पादन, विक्री और क्षमता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है फिर भी यह वृद्धि संबद्ध वस्तुओं के लिये मांग में वृद्धि के समानुपातिक नहीं है। घरेलू उद्योग को उत्पादन क्षमताओं के कम उपयोग का सामना करना पड़ा।
  - ड. घरेलू उद्योग को हानि हुई है और निवेश पर इसकी आय कम और अपर्याप्त रहती है।

185. तदनुसार, प्राथिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग द्वारा समिड़ीयुक्त आयातों और उनको हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

### **क्षति मार्जिन का आकार**

186. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत, जिसका निर्धारण प्राथिकारी द्वारा किया गया है, की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से नियातों की पहुंच कीमत से देखी गई है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन नीचे दिए गए अनुसार है:-

### **चीन**

विवरण	इकाई	जियूली	शेष
क्षति रहित कीमत	रु./मी.ट.	***	***
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	1,51,589	1,00,040
क्षति मार्जिन	रु./मी.ट.	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***
क्षति मार्जिन	रेज	15-25	20-30

### **वियतनाम**

विवरण	इकाई	सानहा एस एस पी वियनतना म	नामचुओंग वियतनाम और तुआन डाट मेटल कंपनी लि.	डाई डुओंग ओएसएस कं. लि.	गिया अन्ह हुंग येन और गिया अन्ह संयुक्त उद्यम कंपनी
क्षति रहित कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	1,54,578	1,57,938	1,53,889	1,48,009
क्षति मार्जिन	रु./मी.ट.	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेज	15-25	10-20	15-25	15-25
विवरण	इकाई	हा अन्ह	विलोंग स्टेनलैस	स्टील 568	शेष

विवरण	इकाई	सानहा एस एस पी वियनतना म	नामचुओंग वियतनाम और तुबान डाट मेटल कंपनी लि.	डाइ डुओंग ओएसएस कं. लि.	गिया अन्ह हुंग येन और गिया अन्ह संयुक्त उद्यम कंपनी
		स्टेनलैस स्टील कंपनी लि.	स्टील (वियतनाम) कंपनी लि.	कंपनी लि.	
क्षति रहित कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	1,48,785	1,62,304	1,31,740	1,31,740
क्षति मार्जिन	रु./मी.ट.	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेज	20-30	10-20	15-25	30-40

#### ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

187. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जिन मुद्दों को उठाया गया है उनमें से अधिकांश मुद्दों को पहले भी उठाया गया है और उसका समाधान उपयुक्त रूप से कर भी दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विशेषण नीचे दिए गए अनुसार दिया गया है :

##### ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

188. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र, उन उत्पादकों जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है का समावेशीकरण, निर्यातिकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता, निर्यातिकों द्वारा तथ्यों को छुपाना और क्षति के संबंध में अपने अनुरोधों को फिर से दोहराया है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने नीचे दिए गए अनुसार अनुरोध किया :

- क. घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना, दस्तावेजों और अनुरोधों को समुचित रूप से प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई थी। घरेलू उद्योग के अनुरोधों के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुरोध, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों, प्रत्युत्तर के रूप में अनुरोध और हितबद्ध पक्षकारों को जारी की गई सत्यापन रिपोर्ट को घरेलू उद्योग को प्रकट नहीं किया गया है।
- ख. अत्यधिक गोपनीयता के कारण, याचिकाकर्ता अपने हितों का बचाव करने में सक्षम नहीं है।
- ग. वियतनाम के मामले में, कच्चे माल में सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई है।
- घ. संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पत्ति नियमावली का दुरुपयोग करने के कारण दक्षिण कोरिया और ताइवान से सामग्री का उपयोग करते हुए वियतनाम स्टील के आयातों पर 456 प्रतिशत तक प्रशुल्क अब तय किए हैं।
- ड. वियतनाम के उत्पादकों को उनके पास उपलब्ध सब्सिडी मुक्त इस्पात का लाभ मिला है और इस पहलू की जांच नहीं की गई है।
- च. वियतनाम के उत्पादकों ने अन्य देशों से इस्पात की खरीद की है और आम तौर पर केवल 15 प्रतिशत होने के कारण निहित प्रक्रिया के लिए मूल्यवर्धन के बावजूद 55 प्रतिशत मूल्यवर्धन का दावा किया है।
- झ. दो उत्पादकों ने चीन में अपनी संबंधित कंपनी से कच्चे माल की खरीद की है।
- ज. वियतनाम सरकार का प्रश्नावली का उत्तर केवल उत्तर देने वाले उत्पादों/निर्यातिकों तक ही सीमित है और न कि संपूर्ण देश पर और इस कारण से यह भाग न लेने वाले निर्यातिकों से संबंधित नहीं है।
- झ. जब जेन्नियांग ज्यूली ने अपने द्वारा प्राप्त सभी सब्सिडी का खुलासा नहीं किया था तब इसके उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- ट. संबंधित पक्षकारों द्वारा उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में, स्टील 568, सोनहा, ज्यूली, ओ एस एस डाई डुओंग और हा अन्ह द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- ठ. यह आवश्यक है कि ये संबंधित पक्षकार जो अपने आप में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक हैं, मूल कंपनियां, इनपुट आपूर्तिकर्ता और कोई अन्य संबंधित पक्षकार जिन्होंने निर्यातिक को समिस्डी अंतरित की है, को अवश्य भाग लेना चाहिए जिसके न होने पर निर्यातिक को सहयोगी के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह अन्य न्याय क्षेत्रों जैसे यू एस, ब्राजील, यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया और मिश्र में स्थापित रीतियों के अनुरूप है।
- ड. संबद्ध वस्तुओं के लिए वियतनाम में निर्माण करने की क्षमता में बहुत हद तक वृद्धि हुई है और इसका कारण चीन से सविसडी युक्त इनपुट की उपलब्धता रही है।
- ढ. ज्ञेजियांग ज्यूली ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है बल्कि सीमलैस स्टेनलैस स्टील पाइप और ट्यूब का निर्यात किया है।
- ण. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त शुल्क लगाए जाने का प्रावधान है। हालांकि निर्धारण की गई क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी।
- त. क्षतिरहित कीमत का निर्धारण उत्पादन की वास्तविक लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- थ. वहन की गई कच्चे माल की लागत और वास्तविक क्षमता उपयोग को ध्यान में रखकर क्षतिरहित कीमत का फिर से निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

## ट.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

189. अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराने के अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने नीचे दिए गए अनुसार अनुरोध किया :
- क. यह तर्क कि सूची में अधिकांश आयातकों जिन्हें प्रश्नावली का उत्तर भेजा गया था, ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, वह यह है कि वे स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पादों नामतः एच एस कोड 7219 और 7220 के अंतर्गत आने वाले क्वायल और शीट का आयात करते रहे हैं जबकि जांच के अधीन उत्पाद के लिए एच एस कोडी 7306 है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद के लिए वी आई एस अनुकूल होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उनमें उपयुक्त इनपुट के लिए वी आई एस अनुकूल होने की आवश्यकता है। यदि विचाराधीन उत्पाद के लिए वी आई एस अपेक्षित था तब अधिकांश कंपनियों जिनका नाम इस याचिका में है, उस उत्पाद के लिए वी आई एस के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं। लाम खांग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, भाग न लेने वाले एक उत्पादक/निर्यातिक एआईएफीए के सदस्य पी टी, इंडोनेशिया गुआंग चिंग निकेल और स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्री इंडोनेशिया जो वी आई एस अनुकूल है, से कच्चे माल की खरीद करता है।
- ग. टूलिंग में मामूली परिवर्तन करने मात्र से सभी आकारों के वेल्ड किए हुए ट्यूब और पाइप का निर्माण करना संभव नहीं है क्योंकि एक खास सीमा के व्यास और मोटाई वाले पृथक श्रेणी की मशीनों से यह अपेक्षित होगा कि वह अपेक्षित सहनशीलता के साथ अपेक्षित आकार के उत्पाद करे।
- घ. उद्योग के आकार और उत्पादन के बारे में निर्णय एकमात्र कच्चे माल के उत्पादक और अपूर्तिकर्ता की क्षमता और विक्री के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आंकड़ों का न होना इस तथ्य को दर्शाता है कि घरेलू उद्योग संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानक नियमावली और विनियमों का पालन नहीं कर रहा है और उससे सरकार का उस उद्योग से राजस्व की हानि हो रही है।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन, बिक्री, राजस्व/ रोजगार का सृजन, बाजार का हिस्सा, क्षति का स्तर इत्यादि के संबंध में सहयोगी आंकड़े के उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट है कि इस जांच का एकमात्र लाभार्थी एकल कॉर्पोरेट कंपनी है।
- च. उत्पादक ट्यूब की वेलिंग, पालिशिंग और गोलाई/चौड़ाई के मामले में अच्छी गुणवत्ता बनाए रख रहे हैं और वे उचित कीमत पर उसकी बिक्री करने में ही सक्षम हो पाए हैं। यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि घरेलू उद्योग के पास गुणवत्ता संबंधी मानदंडों का अभाव है और इस कारण से ये आयात आवश्यकताओं के कारण किए जाते हैं।

- छ. प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि कुछ भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने सत्यापन के दौरान उनसे मांगे गए आवश्यक ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि विनलोंग के परिसरों में कोई सत्यापन नहीं किया गया था। अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे गए थे और अनुरोध के बावजूद कोई समय विस्तार नहीं दिया गया था।
- ज. इसके अलावा, विनलोंग द्वारा पूर्ण सहयोग न किए जाने के कारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विभिन्न सभिसडी योजनाओं और मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए यह निष्कर्ष वास्तविक रूप में सही नहीं है। विनलोंग ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर प्रस्तुत किया है और इसका सत्यापन किया जा सकता था। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान किसी खामियों का उल्लेख नहीं किया गया था।
- झ. वियतनाम के कथित सभिसडी के लिए योजनावार टिप्पणियां नीचे दिए गए अनुसार हैं :-
- i. कथित सभिसडी योजनाओं के कार्यक्रम 1 और कार्यक्रम 3 के लिए, प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया है कि कुछ उत्पादकों को यह लाभ प्राप्त हुआ है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उन उत्पादकों का नाम उपलब्ध कराएं जिन्होंने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है। .
  - ii. कार्यक्रम-2 के लिए, कच्चे माल का आयात करते समय आयात प्रशुल्क चीन-आशियान मुक्त व्यापार करार (ए सी एफ टी ए) और आशियान - भारत मुक्त व्यापार करार (ए आई एफ टी ए) के अनुसार शून्य प्रतिशत है। अतः कोई भी शुल्क भुगतान के योग्य नहीं है और कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। जिनलोंग एक निर्यात प्रसंसकरण उपक्रम है और यह कानून के अनुसार आयात की गई अथवा निर्यात की गई किसी सामग्री या वस्तुओं पर कोई आयात/निर्यात शुल्क अथवा मूल्यवर्धित कर के अध्यधीन नहीं है। .
  - iii. कार्यक्रम-5 के लिए, प्राधिकारी ने यू एस – लेमिनेटिड वूवेन स्टैप्स जो विभिन्न तथ्यों और जांच की विभिन्न अवधियों के साथ प्राधिकारी द्वारा अलग जांच किए जाने वाले एक अलग उत्पाद के लिए है, के जांच परिणाम के आधार पर अपने जांच परिणाम का निष्कर्ष निकाला है। इसके अलावा, वियतनाम की सरकार द्वारा बैंकों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई निदेश नहीं दिया गया है। यदि ऐसा कोई निदेश भी है, तो केवल इसे सरकार अथवा किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान के रूप में नहीं माना जा सकता है। .
  - iv. कार्यक्रम-6 के लिए इस्पात उद्योग इस योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं है और जांच के अधीन किसी भी कंपनी को उस योजना से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।
  - v. कार्यक्रम-7 के लिए किसी भी कंपनियों को वियतनाम डेवलपमेंट बैंक से निर्यात ऋण के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा निर्यात ऋण को राज्य के निवेश ऋण और निर्यात ऋण पर डिक्री 75/2011/एनडी-सीपी जो 14 मई, 2017 तक लागू था, द्वारा विनियमित किया गया था। राज्य के निवेश ऋण पर डिक्री 32/2017/ एनडी-सीपी 15 मई, 2017 को लागू हुआ और यह डिक्री 75 के स्थान पर लाया गया है।
  - vi. कार्यक्रम-8 के लिए, इस कार्यक्रम को डिक्री 151/2006/एनडी- सी पी के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार 16 जनवरी, 2007 को समाप्त कर दिया गया था।
  - vii. कार्यक्रम-9 के लिए निर्यातकों ने, प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया है और यह प्राधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वह सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों का मौके पर सत्यापन करें और उनकी लेखा बुक से अपेक्षित सूचना प्राप्त करें और उसका सत्यापन करें। आगे मांगी गई सूचना भी, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम की हाल में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी जो देश में मौजूद अल्प अवधि और दीर्घ अवधि की ब्याज दरों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

- viii. कार्यक्रम-10 के लिए संबद्ध वस्तुओं का कोई भी उत्पादक/निर्यातक इन उप शीर्षों में से किसी भी उपशीर्ष के अंतर्गत नहीं आता है और इस कारण से यह किसी लाभ के लिए पात्र नहीं है।
- ix. कार्यक्रम-11 के लिए, कोई भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक एक उत्पादक नामतः विनलोंग स्टेनलैस स्टील (वियतनाम) कं. लि. जिसने निर्यातक की प्रश्नावली के अपने उत्तर के भाग के रूप में सभी सूचना उपलब्ध कराई थी और इस योजना के अंतर्गत किसी लाभ के लिए आवेदन नहीं किया था अथवा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था, को छोड़कर लघु और मध्यम आकार के उपक्रमों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- x. कार्यक्रम-13 के लिए, इन उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध वस्तुओं/विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, इसके प्रभाव को इस जांच में नहीं लिया जा सकता है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है।
- xi. कार्यक्रम- 14 और कार्यक्रम 15 के लिए वियतनाम की बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को 70 से अधिक देशों और 2009 में भारत के द्वारा भी दिया गया है और इस कारण से यह भी स्वीकार किया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंकिंग सेवाओं तथा भूमि के उपयोग के अधिकार की कीमत बाजार के सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य करती है।
- xii. स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए उपकरण और मशीनरी के वास्ते आयात शुल्क से छूट जिसका आरोप नहीं लगाया गया है, के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत लाभ की किसी राशि की गणना करने के लिए, इस लाभ में परिसंपत्तियों के जीवनकाल के दौरान लाभ आवंटित करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, वह उत्पाद कंपनी के मामले में, इस प्रकार की राशि को एक संबद्ध वस्तु में आवंटित करना सर्वथा अन्यायोचित होगा।
- xiii. कथित सभी सबिसडी योजनाओं के संबंध में, याचिकाकर्ता किसी सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता के होने के बारे में सिद्ध नहीं कर सके।
- ट विनलोंग भारत में विचाराधीन उत्पाद की बहुत कम मात्राओं और वह भी बहुत अधिक महंगी कीमत पर भेजता रहा है। विनलोंग से किए गए आयातों का हिस्सा वियतनाम से किए गए कुल आयातों में मुश्किल से 5 प्रतिशत है।
- ठ. विनलोंग के पास स्लाटेड वेल्डेड ठ्यूब, सेनेटरी वेल्डेड ठ्यूब, बड़े व्यास वाले वेल्ड किए हुए पाइप, बड़ी और मोटी संरचनात्मक वेल्ड की हुई ठ्यूब जैसे अलग-अलग उत्पाद प्रकार हैं और इनकी बिक्री भी उसी एच एस कोड के अंतर्गत की जाती है। भारतीय मिल विनलोंग द्वारा निर्मित सभी उत्पादों का उत्पादन नहीं कर सकती है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इन उत्पादों में अंतर को स्पष्ट करें और उन उत्पादों, जिनका निर्माण भारतीय मिल द्वारा नहीं किया गया है, पर शुल्क लगाने की सिफारिश न करें।
- ड. गिया अन्ह हुंग येन कंपनी लिमिटेड, हा अन्ह, टुआन डाट, नाम चुओंग, ओ एस एस डाई डुओंग और गिया अन्ह जे एस सी ने यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा प्राधिकारी को पूर्ण रूप से सहयोग दिए जाने के बावजूद प्राधिकारी को उनके मामले में उपलब्ध तथ्यों के उपयोग लागू नहीं करना चाहिए। यह सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 और सबिसडी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के करारे के अनुरूप नहीं होगा।
- ढ. गिया अन्ह हुंग येन कंपनी लिमिटेड, हा अन्ह, टुआन डाट, नाम चुओंग, ओ एस एस डाई डुओंग और गिया अन्ह जे एस सी ने यह अनुरोध किया है कि चूंकि उन्हें जांच की अवधि के दौरान कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, उनके लिए लिए सबिसडी मार्जिन की गणना उनसे संबंधित वास्तविक तथ्यों के अनुरूप पूर्ण रूप से नहीं है।
- ण. डीएसबी नियमावली यह दर्शाती है कि इस प्रकार के कथन और दावे में निम्नलिखित सहित अन्य के साथ-साथ इस मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं :

- i. सामान्य दावे जिनकी पुष्टि संबंधित साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है, पर्याप्त नहीं हैं।
- ii. सब्सिडी कार्यक्रम के बिना किसी प्रत्यक्ष संबंध के सरकारी नीति के बारे में सामान्य सूचना विशिष्टता का “पर्याप्त साक्ष्य” नहीं है।
- iii. यह तथ्य कि कोई कंपनी इस कार्यक्रम की प्रयोक्ता है, इसका साक्ष्य नहीं है कि यह इस कार्यक्रम के सीमित प्रयोक्ताओं में से एक है अथवा एकमात्र प्रयोक्ता है जो विशिष्टता को दर्शाता हो।
- iv. प्रस्तावित जांच अवधि में सब्सिडी के लाभ के आवंटन के संबंध में सूचना न दिए जाने की स्थिति में इस संबंध में कोई भी साक्ष्य को बहुत कम मात्रा में समावेश करना, प्रत्याशित जांच अवधि में लाभ के होने को दर्शनी की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।
- त. दिनांक 27 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 13/2018 के अनुसार, सहयोगी समर्थन देने वाली कंपनियां/प्रतिष्ठान से यह अपेक्षित है कि वे जांच अपरंभ के पूर्ण के चरण में अनुबंध-1 और अनुबंध-2 में निर्धारित प्रपत्र में आंकड़े/सूचना प्रस्तुत करें। सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण किए जाने पर, कोई भी समर्थकारी पत्र उपलब्ध नहीं थे। यह तथ्य कि इन हितबद्ध पक्षकारों को घेरलू उद्योग के रूप में 19 याचिकाकर्ता कंपनियों के आंकड़ों पर टिप्पणी करने का अवसर नहीं दिया गया है और समर्थन करने वाले 86 कंपनियों ने तैसरिंग न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है।
- थ. एतद द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि वियतनाम की सरकार को और सब भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातिकों को सत्यापित की गई कोई पर्याप्त सूचना नहीं दी गई थी। वियतनाम की सरकार के लिए मौके पर सत्यापन हेतु तैयारी करने के लिए 10 दिन का नोटिस और सत्यापन हेतु तैयारी करने के लिए उत्पादकों/निर्यातिकों को 3 कार्य दिवस का समय दिया जाना पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। इस कारण से सत्यापन के संबंधित ब्यौरे डी जी टी आर द्वारा जारी की गई प्रचालन तथा मैनुअल के अनुबंध-VI पैरा-5 और पैरा 8.8.5 (v) तथा एस सी एम करार के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया था।
- द. उन 9 कंपनियों, जिन्होंने निर्यातिक की प्रश्नावली का पूरा उत्तर प्रस्तुत किया, में से 6 कंपनियों को सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान सत्यापन नहीं किया गया था। सत्यापन न किए गए उत्पादकों और निर्यातिकों से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी तथा प्रभावी रूप से केवल एक कार्य दिवस सत्यापन न किए गए निर्यातिकों को व्यापक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। विनलोंग स्टेनलैस स्टील (वियतनाम) कं. लि. द्वारा समय विस्तार दिए जाने का अनुरोध किया गया था परंतु उसे नहीं दिया गया था।
- ध. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम- 7 के पैरा (8) के अनुसार, जांच प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं यदि कोई हितबद्ध पक्षकार:

  - i. सूचना देने से इंकार करता है; अथवा
  - ii. उचित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है; अथवा
  - iii. इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा उत्पन्न करता है।

- न. उत्पादकों/निर्यातिकों ने सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई है और वे अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। महानिदेशक को स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करना चाहिए कि कौन सी सूचना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं कराई गई थी और केवल इस बात का उल्लेख करना कि सूचना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं कराई गई थी, पर्याप्त नहीं है।
- प. यह निष्कर्ष विभिन्न उत्पाद और विभिन्न अवधि के लिए अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा विगत में की गई जांचों के आधार पर निकाली गई है।

- फ. प्राधिकारी को प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में “उपलब्ध तथ्यों” का उपयोग करते समय हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए सभी सिद्ध किए गए तथ्यों पर अवश्य विचार करना चाहिए, यदि वे तथ्य उस पक्षकार द्वारा पूर्ण सूचना के संबंध में अनुरोध किए गए अनुसार स्थापित न भी करता हो। इसके अलावा, प्राधिकारी को “उपलब्ध तथ्यों” सामान्य तौर पर उन्हीं तक सीमित है जो उचित रूप से उस सूचना को प्रतिस्थापित कर सकता है जो कि हितबद्ध पक्षकार उपलब्ध कराने में असफल रहे।
- ब. अनुच्छेद 12.7 के प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि यदि हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तब इस जांच में बाधा नहीं उत्पन्न की जानी चाहिए। इस प्रकार से, यह प्रावधान सूचना को जहां मौजूद नहीं है, को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के उपयोग की अनुमति देता है जिससे कि सही-सही सब्सिडी अथवा क्षति के निर्धारण को तय किया जा सके।
- भ. वियतनाम के सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उन्हीं तथ्यों और भागीदारी की गई थी और प्राधिकारी द्वारा वहीं सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई थी फिर भी उनमें सब्सिडी मार्जिन दो कंपनियों के लिए रही है और शेष 7 कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को अस्वीकार कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि प्राधिकारी द्वारा सतत दृष्टिकोण को अपनाया नहीं गया है।
- म. प्राधिकारी को क्षति मार्जिन के लिए गणना/कार्यपद्धति को प्रकट करते हुए एक शुद्धि पत्र प्रकटन विवरण अवश्य जारी करना चाहिए।
- य. प्राधिकारी ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय के विस्तार हेतु जेझियान ज्युली हाई टैक मैटल्स द्वारा किए गए अनुरोध को नहीं माना है। हालांकि, प्राधिकारी ने जानबूझकर निर्धारित समय के बाद और विलंबित चरण में घरेलू उत्पादकों को अपने आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। 22 उत्पादकों का समेकित आंकड़ा मौखिक सुनवाई के चरण में प्रस्तुत किया गया था। इस कारण से इन आंकड़ों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- र. समेकित सूचना/आंकड़ों को कथित उत्पादकों द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत किया गया और यह उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की तिथि को रिकॉर्ड करें जिसमें 19 पात्र उत्पादकों की समेकित सूचना प्रस्तुत की गई थी और यह सूचना ज्यूली को उपलब्ध कराएं ताकि इस संबंध में समुचित टिप्पणियां अंतिम जांच परिणामों के पूर्व प्रस्तुत की जा सके।
- ल. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे एल टी ए आर के लिए सब्सिडी की दर के निर्धारण के संबंध में ज्यूली द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करें और एल टी ए आर सब्सिडी दर के निर्धारण के लिए इन आंकड़ों पर विचार करें।
- व. यह अनुरोध किया जाता है कि कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान स्वतः रूप में प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी के रूप में नहीं होता है और इस कारण से अन्य उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान वर्तमान जांच के लिए प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी के रूप में पात्र नहीं है।
- श. सी वी डी नियम 2 (ख) “घरेलू उद्योग” के कार्यक्षेत्र के भीतर आयातकों को शामिल किए जाने की अनुमति नहीं देता है। आयातकों को जांच आरंभन के चरण में ही “घरेलू उद्योग” के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए था। इस कारण से, वर्तमान जांच गलत और भ्रामक तथ्यों/आंकड़ों के आधार पर होने के कारण सही नहीं है।
- ष. जांच आरंभन के चरण के बाद घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए समर्थन संबंधी पत्रों को अस्वीकार किया जाना चाहिए। घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया समर्थन पत्र डी जी टी आर द्वारा जारी किए गए व्यापार सूचना 13/2018 में निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।
- ह. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे जिंदल स्टेनलैस कॉपोरेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. द्वारा यथाअनुमानित कुल उत्पादन के संबंध में सूचना को अस्वीकार करें और इस पर उस तरीके से विचार करें जिस तरीके से घरेलू उत्पादन के अनुमान तय किए गए हैं क्योंकि वह न्यायोचित नहीं है।

- अ. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आर्थिक मानदंडों जिन्हें अंतिम जांच परिणामों में गोपनीय के रूप में दावा नहीं किया गया है (उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, घरेलू विक्री, नियीत विक्री, माल भंडार, आदि सहित) को प्रकट करें।
- ब्र. आर्थिक मानदंडों से संबंधित आंकड़े जिन्हें प्रकटन विवरण में दर्शाया गया है, घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।
- ज. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे हितबद्ध पक्षकारों की सूची को डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- कक. सीवीडी नियमावली के संबंध में शुल्क तब नहीं लगाया जाना चाहिए जब आयातों के कारण क्षति नहीं हुई हो। इस कारण से उसे कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे वर्तमान जांच में शुल्क का संदर्भ कीमत/बैंच मार्क की सिफारिश करें।
- खख. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि घरेलू उत्पादक स्वयं संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और अन्य भारतीय उत्पादकों को क्षति पहुंचा रहे हैं।
- गग. प्राधिकारी को क्षति के विश्लेषण को निर्धारित करने के लिए सभी 86 समर्थन करने वाले उत्पादकों के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए था क्योंकि यह प्राधिकारी को घरेलू उत्पादकों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए सक्षम बनाया होता।
- घघ. निर्दिष्ट प्राधिकारी को “कमतर शुल्क नियमावली” को अपनाना चाहिए और यदि क्षति का कोई निर्धारण किया गया हो, तब सब्सिडी के मार्जिन की तुलना में कम दर पर शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए (अर्थात् क्षति के मार्जिन की सीमा तक क्योंकि वह क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है)।
- ड.ड. प्राधिकारी ने इनपुट सामग्री के घरेलू प्रतिष्ठानों/आपूर्तिकर्ताओं की प्रकृति के बारे में ज्यूली से ब्यौरा मांगा है। ज्यूली द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि इनपुट सामग्री की आपूर्ति निजी प्रतिष्ठान तथा ऐसे ओं ई से की गई थी। और यह पुष्टि करता है कि चीन की सरकार इनपुट सामग्री का एक एकाधिकारवादी आपूर्तिकर्ता नहीं है।
- चच. प्राधिकारी ने चीन में भूमि की कीमत की तुलना करने के लिए उपयोग की गई थाइलैंड में क्षेत्र/स्थान को प्रकट नहीं किया है। यदि 2010 का बैंचमार्क कीमत को सूचीबद्ध किया जाता है तब यह दर्शाएगा कि सब्सिडी की दर नगण्य (0.10 प्रतिशत) है और इस कारण से भूमि कार्यक्रम के लिए सब्सिडी की किसी भी दर का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सी बी डी नियमावली सब्सिडी की दर का निर्धारण करने के लिए भूमि पर लाभ के योग की अनुमति नहीं देता है। तदनुसार, ज्यूली इस तथ्य को दोहराता है कि प्राधिकारी को भूमि के उपयोग के अधिकारों पर प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी के रूप में विचार नहीं करना चाहिए।
- छछ. कार्यक्रम-51 – स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यवर्धित कर में कटौती केन्द्रीय क्षेत्र में स्थिति प्रतिष्ठानों पर लागू है। ज्यूली केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित नहीं है और इस कारण से यह योजना लागू नहीं है।
- जज. परिवर्तनीय बॉड को जारी किए जाने के द्वारा प्राप्त किया गया वित्त चीन की सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण के कार्यक्षेत्र से बाहर है और उसे प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।
- झझ. चीन के लिए कार्यक्रम सं. 32 के अंतर्गत लाभ ज्यूली द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है क्योंकि इसे प्रश्नावली के उत्तर में पूर्व में भी प्रस्तुत किया गया है।
- टट. चीन के लिए कथित कार्यक्रम सं. 39 विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं है और इस कारण से यह प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी नहीं है।
- ठठ. अपीलीय निकाय रिपोर्ट, संयुक्त राज्य – निश्चयात्मक पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, जो चीन के कुछ उत्पादों पर, डब्ल्यू टी/ डी ऐस 379/एवी/आर पर लगाया गया है, जहां विश्व व्यापार संगठन ने यह माना है कि राज्य का स्वामित्व “सार्वजनिक निकाय” के निर्धारण के लिए एकमात्र निर्णायक मानदंड नहीं है, से यह देखा जा

सकता है। इस कारण से राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों (एस ओ सी बी) से प्राप्त किया गया ऋण सब्सिडी के प्राधिकार से बाहर आता है।

- डड. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट कुछ अंतरनिहित कारणों से हुई है। घरेलू उद्योग की कम उत्पादकता के कारण उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए बाध्य हुए हैं। इस कारण से प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे जांच की अवधि के पूर्व की अवधि के दौरान कम क्षमता के उपयोग के कारणों और व्यापक तौर पर नीचे स्तर तक “घरेलू उत्पादकों” के कार्यनिष्पादन पर इसके प्रभाव की जांच करें।

### ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

190. जहां तक इस अनुरोध का प्रश्न है कि वियतनाम की सरकार और भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों को कोई पर्याप्त सूचना सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वियतनाम की सरकार और उसके साथ ही संबंधित निर्यातिक, जो सत्यापन के लिए सहमत हुए थे, का मौके पर सत्यापन के लिए पर्याप्त सूचना दी है। प्राधिकारी ने उसके बाद ही सत्यापन की आगे की कार्रवाई की है। वियतनाम की सरकार द्वारा दिनांक 04.06.2019 को प्राधिकारी को भेजे गए पत्र के अनुसार यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि वियतनाम की सरकार को दिनांक 17 जून, 2019 से किए जाने वाले सत्यापन के बारे में बहुत पहले ही इसकी पूर्ण जानकारी थी। भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को भी सत्यापन की तैयारी करने के लिए उन्हें 7-10 दिनों का समय देते हुए बहुत पहले ही सूचित किया गया था। लिखित पत्र के अलावा, मौखिक सूचना प्राथमिक सत्यापन के बहुत पहले कानूनी प्रतिनिधियों को दी गई थी। वास्तव में, वियतनाम की सरकार के प्रतिनिधि और निर्यातिक को प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले सत्यापन के बारे में लाया गया था।
191. इस अनुरोध के संबंध में विनलोंग स्टेनलैस स्टील को पर्याप्त समय नहीं दिया गया था और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी द्वारा कोई समय विस्तार नहीं दिया गया था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातिक ने इस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए 4 अतिरिक्त दिवस दिए जाने का अनुरोध किया था और इस अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा नहीं माना गया था। परंतु, निर्यातिक 4 अतिरिक्त दिवस के समाप्त होने के बाद भी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं कर पाए।
192. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै. सोन हा एस एस पी और मै. स्टील 568 का सत्यापन किया गया था क्योंकि इन कंपनियों का भारत में बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता था। इन उत्पादकों/निर्यातिकों ने जांच के प्रत्येक चरण में प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सभी सूचना प्रस्तुत की। हालांकि, कुल 9 निर्यातिकों में से शेष 7 निर्यातिकों ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई और तदनुसार, प्राधिकारी इन 7 निर्यातिकों के मामले में जहां कहीं भी लागू हुआ, उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है।
193. मै. डाई डुओंग के मामले में, यह यह नोट किया जा सकता है कि इसके उत्तर को प्राधिकारी को अस्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी जहां कहीं भी संबंधित निर्यातिक ने जांच के किसी चरण में प्राधिकारी द्वारा यथापेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है।
194. बीआईएस अनुकूल होने का मुद्दा संबद्ध वस्तुओं को सब्सिडी दिए जाने और घरेलू उद्योग को क्षति होने के मुद्दे से संबंधित नहीं है।
195. कुछ हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि टूलिंग में केवल मामूली परिवर्तन के द्वारा सभी आकारों के बेल्ड किया हुए ट्यूब और पाइपों का निर्माण करना संभव नहीं है और विशेष सीमा के व्यास और मोटाई वाली मशीनों की अलग रेंज अपेक्षित सहनशीलता के साथ अपेक्षित आकार का उत्पादन करने के लिए आवश्यक होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि कुछ उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

196. यह देखा जाता है कि आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक सीमा तक वृद्धि हुई है और घरेलू उत्पादकों के संपूर्ण बाजार हिस्से में बहुत अधिक गिरावट आई है। याचिकार्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस उत्पाद का अधिकांश उत्पादन एम एम ई श्रेणी में होता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि इस उत्पाद का आयात गुणवत्ता की दृष्टि से किया गया है। इस आशय का कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
197. प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से किसी पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अपेक्षित सूचना के लिए सत्यापन एक प्रतिस्थानापन नहीं है। वास्तव में सत्यापन प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए ही है। प्राधिकारी सत्यापन के समय सूचना संग्रह करने के बजाए सूचना मंगाकर पूर्ण रूप से सही कार्य किया है। सत्यापन निर्धारण के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने हेतु हितबद्ध पक्षकार के पास एक अवसर नहीं है।
198. इस तर्क के संबंध में कि भारतीय उद्योग विनलोंग द्वारा निर्मित सभी उत्पादों का उत्पादन नहीं कर सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस प्रकार के किसी दावे को कंपनी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। वास्तव में इस प्रकार का कोई दावा जांच आरंभन के चरण में नहीं किया गया था और न ही किसी प्रकार के नियाति को दर्शाते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है जिसके लिए समान वस्तु की आपूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की जाती है। किसी विशिष्ट दावे अथवा साक्ष्य के उपलब्ध न होने की स्थिति में, कुछ उत्पादों को बाहर किए जाने के संबंध में विलंब से किए गए दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में बाहर किए जाने हेतु अनुरोध बहुत सामान्य है और इस संबंध में कोई विशिष्ट दावा नहीं किया गया है।
199. इस नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध घरेलू उद्योग के अलग-अलग उत्पादकों के आंकड़े उपलब्ध कराएं। इस नियमावली में हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर दिया जाना अपेक्षित है कि वे संपूर्ण रूप में घरेलू उद्योग से संबंधित सूचना के बारे में टिप्पणी प्रस्तुत कर सकें। प्राधिकारी की यह सतत प्रथा रही है कि वे संपूर्ण रूप में घरेलू उद्योग के संबंध में और न कि घरेलू उद्योग के अलग-अलग संघटक के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं।
200. वियतनाम की सरकार और भाग लेने वाले उत्पादक/नियातिक को सत्यापन के लिए तैयारी करने के वास्ते समुचित समय और अवसर दिए गए हैं। लिखित सूचना के अलावा, मौखिक सूचना वास्तविक सत्यापन के बहुत पहले कानूनी प्रतिनिधियों को दिया गया था। इसके अलावा, दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवश्यकता का विशेष उल्लेख करते हुए लिखित सूचना के अलावा जिन पक्षकारों के कानूनी प्रतिनिधियों को इन आवश्यकताओं के बारे में अनेक बार मौखिक रूप से सूचित किया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि इन पक्षकारों के लिए यह आवश्यक था कि वे आरंभिक प्रश्नावली के उत्तर के समय ही प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराएं। यह नोट किया जाता है कि प्रश्नावली के आरंभिक उत्तर बहुत अधिक संक्षिप्त थे और इसमें सभी संगत सूचना निहित नहीं थी। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रश्नावली में ही बहुत स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया था कि प्रश्नावली के उत्तर के साथ-साथ सभी संगत सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
201. इस तर्क के संबंध में कि 10 अतिरिक्त उत्पादकों के आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि इस मुद्रे की पहले ही जांच कर ली गई है।
202. ज्यूली के मामले में सब्सिडी के मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण की अपनी टिप्पणियों में यह अनुरोध किया है कि मैं, ज्यूली ने भारत में केवल सीमलैस ट्यूब्स एंड पाइप्स (एनपीयूसी) और न कि वेल्ड किया हुआ सीमलैस ट्यूब और पाइप (विचाराधीन उत्पाद) का नियाति किया है। इस टिप्पणी को प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने दी गई पद्धति से भी आयात से संबंधित आंकड़े मंगाए हैं और यह पाया है कि जांच की अवधि के दौरान मैं, ज्यूली द्वारा सूचित की गई भारत में विचाराधीन उत्पाद के नियाति के लिए नियाति संबंधी सभी लेन देन उनमें प्रतीत नहीं होते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संपूर्ण रूप में इन नियाति लेन देन के लिए मैं, ज्यूली द्वारा सूचित दर चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद की औसत नियाति कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण को देखते हुए, मैं, ज्यूली की नियाति कीमत को क्षति के मार्जिन के निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने मैं, ज्यूली के क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए

उपलब्ध तथ्यों का उपयोग किया है। हालांकि प्राधिकारी ने मै. ज्यूली के लिए सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से अपने ई क्यू आर में मै. ज्यूली द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार अधिकांश सूचना को स्वीकार किया है।

203. उन कंपनियों, जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया था, को बाहर किए जाने के संबंध में भाग लेने वाली कुछ कंपनियों द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की स्थिति के उद्देश्य से इस प्रकार के प्रतिष्ठानों को बाहर रखा है। हालांकि, इस प्रकार के प्रतिष्ठानों को बाहर रखे जाने के बाद ही घरेलू उद्योग की स्थिति संबंधी आवश्यकता जांच आरंभन के चरण में भी पूरी की गई है।
204. इस तर्क के संबंध में कि, जिंदल स्टेनलैस कॉम्पोरेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. द्वारा सूचित सकल घरेलू उत्पादन को स्वीकार नहीं किया जाए, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सकल घरेलू उत्पादन के संबंध में कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। वर्तमान मामले में, **12** कंपनियों ने जांच आरंभन के चरण में क्षति से संबंधित अपनी सूचना उपलब्ध कराई जबकि अतिरिक्त **86** कंपनियों ने इस याचिका का समर्थन किया। जांच आरंभन के बाद, **10** कंपनियों ने क्षति से संबंधित अपनी सूचना उपलब्ध कराई। यह नोट किया जाता है कि यदि उत्पादकों द्वारा आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद को बाहर भी रख दिया जाता है, तब घरेलू उद्योग के भाग के रूप में कंपनियां इस नियमावली के आशय से एक बहुत बड़े हिस्से का आयात कर सकते हैं।
205. वैबसाइट पर हितबद्ध पक्षकारों की सूची डाले जाने के संबंध में, प्राधिकारी ने पहले ही सभी निर्यातकों और आयातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया है, के नामों की सूची दे दी है। इसके अलावा, सभी संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में रखी गई थीं और जांच की प्रक्रिया के दौरान इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उन्हें प्राप्त किया गया था।
206. जहां तक शुल्क के बैंचमार्क रूप की सिफारिश किए जाने का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि इस मामले के वास्तविक मैट्रिक्स के आधार पर प्राधिकारी द्वारा शुल्क का उपयुक्त रूप की सिफारिश की जाती है।
207. भूमि के उपयोग के अधिकार में सब्सिडी के संबंध में यह नोट किया जाता है कि भूमि के उपयोग पर लाभ का निर्धारण सी वी डी नियमावी के अनुबंध-IV के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, इन दावों के संबंध में कि 2010 की कीमतों की बैंचमार्किंग मामूली सब्सिडी को दर्शाएंगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातिक ने किसी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अपने दावे की पुष्टि नहीं की है। इस प्रकार के किसी साक्ष्य के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लाभ का निर्धारण किया है।
208. इस तर्क के संबंध में कि अन्य जांच में की गई सब्सिडी निर्धारण वर्तमान जांच में लागू नहीं किया जा सकता है, यह नोट किया जा सकता है कि प्राधिकारी ने केवल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की है जहां अपेक्षित सूचना निर्यातिक/उत्पादक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।
209. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट कुछ अन्य कारणों से हुई है। हालांकि, इस प्रकार के किसी कारक की पहचान नहीं की गई है और न ही यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपब्रह्म कराया गया है कि क्षमता के उपयोग में गिरावट कुछ अंतरनिहित कारकों और न कि सब्सिडीयुक्त आयात के कारण हुई है।
210. वियतनाम की सब्सिडी योजनाओं के संबंध में किए गए तर्कों के बारे में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे और व्यक्त की गई चिंताओं का निवारण यहां नीचे दिए गए अनुसार किया गया है।
- इस तर्क के संबंध में कि कार्यक्रम 1 और कार्यक्रम 3 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले उत्पादकों के नाम की पहचान की जानी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि सब्सिडी मार्जिन संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों पर लगाया गया है, जैसाकि संबंधित तालिका में उल्लेख किया गया है।
  - कार्यक्रम-5 में उठाए गए तर्कों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रियायती दरों पर ऋण ऐसे बैंक द्वारा दिया जा सकता है जो सरकार के स्वामित्व वाला अथवा निजी नियंत्रण वाला हो सकता है और यह कि यदि

कोई बैंक निजी कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है तब भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यदि केन्द्रीय बैंक/सरकार के निवेश पर निजी बैंक रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, तब प्रतिसंतुलनकारणीयता का अभाव है।

- iii. कार्यक्रम-6 में दिए गए तर्कों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम उत्पाद/क्षेत्र विशिष्ट नहीं है, जैसा कि दावा किया गया है।
- iv. कार्यक्रम 7, 8 और 10 के संबंध में दिए गए तर्कों के बारे में कि इस्पात क्षेत्र को राज्य के निवेश ऋण और निर्यात ऋण के संबंध में डिक्री 75/2011/एनडी-सीपी जो 14 मई, 2017 तक लागू था, के अंतर्गत लाभ को बाहर रखा गया है। यह नोट किया जाता है कि 75/2011/एनडी-सीपी 15 मई, 2017 से राज्य की निवेश ऋण से संबंधित डिक्री 32/2017/एनडी-सीपी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो इस लाभ से उत्पाद क्षेत्र को बाहर रखना जारी रखता है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि यह लाभ इस्पात उद्योग को एक अलग योजना अर्थात् “इस्पात उद्योग विकास मास्टर प्लान” के अंतर्गत दिया जाता है।
- v. कार्यक्रम सं. 11 के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वियतनाम की सरकार को अपना उत्तर केवल उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभ एस एम ई को भी उपलब्ध कराया जाता है। न तो वियतनाम सरकार और न ही निर्यातक ने इस तर्क के संबंध में उपयुक्त कारण उपलब्ध कराए हैं कि क्यों इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए एस एम ई के पात्र होने के बावजूद विनलैंग स्टेनलैस स्टील कंपनी लि. ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है अथवा लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- vi. कार्यक्रम-13 के संबंध में दिए गए तर्कों के बारे में यह नोट किया जाता है कि न तो वियतनाम की सरकार ने और न ही निर्यातकों ने इस कार्यक्रम के मौजूद होने का विरोध किया है और इस कारण से यह वियतनाम आधारित उत्पादक/निर्यातक की श्रेष्ठ श्रेणी के लिए प्रतिसंतुलनकारणीय है।
- vii. समुचित धनराशि से कम पर भूमि उपलब्ध कराने/भूमि के उपयोग का अधिकार देने से संबंधित कार्यक्रम 14 और कार्यक्रम 15 के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि वियतनाम को भारत की सरकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है और तदनुसार, इस प्रकार का कोई लाभ विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातक को नहीं दिया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक देश को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना अथवा अन्यथा का कोई संबंध समुचित धनराशि से कम पर ऐसे कार्यक्रमों को चलाने से नहीं है।
- viii. थाई परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए उपकरण और मशीनरी के वास्ते आयात शुल्क में छूट की योजना के बारे में यह नोट किया जाता है कि वियतनाम की सरकार ने इस कार्यक्रम के मौजूद होने को स्वीकार किया है और यह उल्लेख किया है कि मै. डाई डुओंग ने इस योजना का लाभ उठाया है। हालांकि मै. डाई डुओंग ने इस लाभ की सूचना नहीं दी है और तदनुसार प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की है।
- ix. वियतनाम से निर्यातकों को उनके संबंधित पक्षकारों के संबंध में सूचना/आंकड़े/व्यौरा प्रस्तुत न करने के कारण असहयोगी के रूप में घोषित करने के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर पाया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए इनपुट की आपूर्ति इस प्रकार के किसी संबंधित पक्षकारों से की गई है और तदनुसार, प्राधिकारी इसे उचित नहीं मानते हैं कि वियतनाम के उत्पादक को किस आधार पर असहयोगी के रूप में घोषित किया जाए।
- x. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद के वियतनाम के उत्पादक/निर्यातक आयात किए गए इनपुट्स पर प्राप्त मूल्यवर्धन की गलत घोषणा करते हुए उत्पत्ति के नियम के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मुद्दे की जांच वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

#### **ठ. निष्कर्ष**

211. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में यथा दर्ज किए गए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि :
- विचाराधीन उत्पाद का निर्यात् भारत में संबद्ध देशों से सब्सिडीयुक्त मूल्य पर किया गया है और इस प्रकार से इस उत्पाद को सब्सिडी दी गई है।
  - घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद को सब्सिडी दिए जाने के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।
  - वास्तविक क्षति संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण हुई है।

### **भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे**

212. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य आम तौर पर सब्सिडी दिए जाने की अनुचित व्यापार प्रथाओं के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए है जिससे भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थित पुनः स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिवंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
213. यह मान लिया गया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने का प्रतिकूल प्रभाव संबद्ध वस्तुओं की लागत पर पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को लगाए जाने, विशेष रूप से यदि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने से सब्सिडीयुक्त संबद्ध वस्तुओं के आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो, कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को लगाए जाने से सब्सिडी के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को समाप्त किया जाएगा और समान अवसर सृजित होंगे।

### **सिफारिशें**

214. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह जांच आरंभ की गई थी और इसकी सूचना चीन जन.गण की सरकार और वियतनाम की सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी और इसके पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध सब्सिडी दिए जाने, क्षति और कारणात्मक संबंधों के पहलुओं पर सूचना/साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था। निर्धारित नियमावली के संबंध में सब्सिडी दिए जाने, क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच आरंभ किए जाने और पूरा किए जाने तथा इस प्रकार के सब्सिडीयुक्त आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति तथा सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन का सिद्ध किए जाने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना इस कारण से अपेक्षित है कि सब्सिडी दिए जाने और क्षति के प्रभाव से बचा जा सके। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि नीचे दिए गए रूप और तरीके से चीन जन.गण और वियतनाम से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाए।
215. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कमतर शुल्क नियमावली के संबंध में, प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से सब्सिडी के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से जो भी कमतर हो, उसके बराबर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, निम्नलिखित तालिका के कॉलम 7 में यथाउल्लिखित निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को चीन जन.गण. और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

### **शुल्क तालिका**

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्भव का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	---------	--------

						मूल्य के % के अनुरूप शुल्क राशि
1	73064000, 73066100, 73066900, 73061100, 73062100	वेल्ड किया हुआ स्टेनलैस स्टील पाइप और छूब	चीन जन.गण	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांग ज्यूली हाइ टैक मेटल्स कं., लि.	21.74
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन. गण. सहित कोई देश	उपर्युक्त 1 को छोड़कर कोई उत्पादक	29.88
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. और वियतनाम को छोड़कर कोई अन्य देश	चीन जन गण	कोई	29.88
4	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	सोनहा एसएसपी वियतनाम सोल मेंबर कंपनी लिमिटेड	शुन्य
5	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	नाम कुओंग मेटल कंपनी लिमिटेड	11.04
6	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	ओ एस एस डाई डुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	11.10
7	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	विनलोंग स्टेनलैस स्टील (वियतनाम )कं., लि.	10.33
8	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	स्टील 568 कं., लि.	शुन्य

9	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	हा अन्ह स्टेनलैस स्टील कंपनी लिमिटेड	11.96
10	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	जिया अन्ह हुंग येन कं., लि.	11.96
11	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	उपर्युक्त 4 से 10 को छोड़कर कोई उत्पादक	11.96
12	-वही-	-वही-	वियतनाम और चीन जन गण को छोड़कर कोई अन्य देश	वियतनाम	कोई	11.96

216. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथा निर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और इसमें सीमा प्रशुल्क अधिनियम, की धारा 3, 3क, 8 ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।
217. इस जांच परिणाम के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31<sup>st</sup> July, 2019

**FINAL FINDINGS**

**Subject:** Final Findings in anti-subsidy investigation concerning imports of Welded Stainless Steel Pipes and Tubes originating in or exported from China PR and Vietnam.

**F.No. 6/22/2018-DGAD:** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the “Countervailing Duty Rules” or the “Rules”) thereof:

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. Whereas, M/s Stainless Steel Pipe And Tubes Manufacturer Association, New Delhi, M/s Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association, Ahmedabad, M/s South India Stainless Steel Pipe And Tubes Manufacturer Association and M/s Haryana Stainless Steel Pipe And Tube Manufacturer Association (hereinafter also referred to as the “petitioners”) have jointly filed a petition, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and Countervailing Duty Rules for imposition of countervailing duty on imports of Welded Stainless Steel Pipes and Tubes (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration”) from China PR and Vietnam (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Petitioners, issued a public notice vide Notification No. 6/22/2018 - DGAD dated 9<sup>th</sup> August, 2018, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/ countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
  - a. The Authority informed the Embassies of People’s Republic of China and Vietnam in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation.
  - b. The Authority invited the Governments of the subject countries for consultations with the aim of clarifying the factual situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). The Authority held consultations with the representatives of the Government of China PR (hereinafter also referred to as “GOC”) on 27<sup>th</sup> June, 2018 and the representatives of the Government of Vietnam (hereinafter also referred to as “GOV”) on 6<sup>th</sup> July, 2018 at New Delhi. The consultations were attended by representatives of the two countries. The facts clarified and documents/information filed, if any, by the governments of the subject countries were taken on record.
  - c. The Authority issued a public notice dated 9<sup>th</sup> August, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating countervailing duty/anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods.
  - d. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 9<sup>th</sup> August, 2018 to the embassy of the subject countries, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Petitioners and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
  - e. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.
  - f. The embassy of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

- g. The Authority sent questionnaire to the government of the subject countries in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit were alleged to have been conferred by the governments/public bodies.
- h. The Authority sent questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject countries, in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
- i. Shen Zen 1-Touch Business Service Limited, China PR
  - ii. Wuxi Joyray International Corp, China PR
  - iii. Lianzhong Stainless Steel Corporation, China PR
  - iv. Foshang Liteng Economy & Trade Co., Ltd, China PR
  - v. Foshan Gangtuo Import & Export Co., Ltd., China PR
  - vi. Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd., China PR
  - vii. Ningbo Tierslia Imp. & Exp. Co., Ltd., China PR
  - viii. Shenzhen Zhaoheng Specialty Steel Co., Ltd., China PR
  - ix. Sichuan Dayang Trading Co., Ltd., China PR
  - x. Shenzhen Zhongchuang Yu Steel Industry Co., Ltd., China PR
  - xi. Minmetals Steel Co., Ltd., China PR
  - xii. Jieyang City Baowei Stainless Steel Co., Ltd, China PR
  - xiii. Foshan Sun Ming Trading Co.,Ltd, China PR
  - xiv. Pohang (Zhangjiagang) Stainless Steel Processing Co., Ltd., China
  - xv. Xiamen Great Corporation, China PR
  - xvi. Guangdong Foreign Trade Imp & Exp. Co., China PR
  - xvii. Ningbo Chinaworld Grand Import And Export Co., Ltd., China PR
  - xviii. Shandong Huaye Stainless Steel Products Co., China PR
  - xix. Export Co., Ltd., China PR
  - xx. Beijing Jingnanfang Decoration Engineering Co., Ltd., China PR
  - xxi. Xiamen Golden Huanan Imp. & Exp. Co., Ltd., China PR
  - xxii. Yu Gang Import And Export Trading Co Ltd., China PR
  - xxiii. Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, China PR
  - xxiv. Mianzhu Honda Trading Co., Ltd, China PR
  - xxv. Xiamen Tancheng Import And Export Co., Ltd, China PR
  - xxvi. Foshan Vigor Dragon Imp & Exp Co., Ltd, China PR
  - xxvii. Foshan International Trade Co. Ltd, China PR
  - xxviii. Shanghai Hyss International Trading Co., Ltd, China PR
  - xxix. T Singshan Holding Group Shanghai Internatiqnal Trading Co., Ltd, China PR
  - xxx. Export Co., Ltd., Nanjing Robinson, China PR
  - xxxi. Sokal Steel Co., Ltd., China PR
  - xxxii. Gaoming District Of Foshan City Octopus Stainless Steel Co , Ltd, China PR
  - xxxiii. Foshan Guang Yu Stainless Steel Co., Ltd, China PR
  - xxxiv. Zhejiang, One Of Qualcomm Enterprise Services Ltd, China PR
  - xxxv. Kinforo Henan Construction Machinery Co., Ltd, China PR
  - xxxvi. China Western Power Industrial Co., Ltd., China PR
  - xxxvii. Nanhai Shun Tang Imp. & Exp.Co., Ltd of Foshan, China PR
  - xxxviii. Taikoo (Xiamen) Aircraft Engineering Co., Ltd, China PR
  - xxxix. TAP International, JSC, Vietnam
  - xl. Inox Hoa Binh JSC, Vietnam
  - xli. Sonha International Corporation, Vietnam
  - xlii. OSS Dai Duong International Joint Stock Company, Vietnam
  - xliii. Vinainox, Vietnam
  - xliv. Ming Huu Lien JSC, Vietnam
- i. In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:
- i. Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd., China PR
  - ii. Sonha SSP Vietnam Sole Member Co., Ltd., Vietnam
  - iii. Nam Cuong Metal Company Limited, Vietnam
  - iv. OSS Dai Duong International Joint Stock Company, Vietnam
  - v. Tuan Dat Metal Company Limited, Vietnam
  - vi. Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co., Ltd., Vietnam
  - vii. Steel 568 Co., Ltd., Vietnam
  - viii. Gia Anh Joint Stock Company, Vietnam
  - ix. Ha Anh Stainless Steel Company Limited, Vietnam

- x. Gia Anh Hung Yen Company Limited, Vietnam
- j. Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject countries, GOV also filed the questionnaire response. GOC has however not filed any questionnaire response in the present investigation.
- k. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
  - i. Maruichi Kuma Steel Tube Private Ltd
  - ii. Magppie International Ltd.
  - iii. Posco-India Delhi Steel Processing Centre Pvt. Ltd
  - iv. U-Like Exports
  - v. Posco-India Pune Steel Processing Centre Pvt. Ltd
  - vi. Aadinath Metal
  - vii. Sharda Motor Inds Ltd
  - viii. JKB International
  - ix. Minox Metal Pvt.Ltd
  - x. Anant Inox
  - xi. Navnidhi Steel Engineering Co. Pvt. Ltd.
  - xii. Shiva Utensils Industries Pvt. Ltd.
  - xiii. Automotive Steel Pipe India Private Limited
  - xiv. Rajputana Stainless Ltd
  - xv. Stainox Alloys Pvt Ltd
  - xvi. Radha Raman Stainless Steel Pvt. Ltd.
  - xvii. Posco India Chennai Steel Processing Centre Pvt.
  - xviii. Janki Metal Strips Private Limited
  - xix. Tenneco Automotive India Private Limited
  - xx. M M Metal International
  - xxi. Reliance Fabrications Pvt. Ltd.
  - xxii. Mukesh Steel Trading
  - xxiii. IDMC Limited
  - xxiv. Sunrise Stainless Pvt. Ltd.
  - xxv. Navnidhi Steel Engineering Co. Pvt. Ltd.
  - xxvi. Kone Elevator India Pvt Ltd
  - xxvii. Paharpur Cooling Towers Limited
  - xxviii. Larsen & Toubro Limited
  - xxix. Inox India Ltd
  - xxx. Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited
  - xxxi. Renaissance Biochemicals Pvt. Ltd.
  - xxxi. Sulzer India Ltd.
  - xxxiii. Isgec Heavy Engineering Ltd
  - xxxiv. Manak Overseas Ltd.
  - xxxv. Suncity Strips & Tubes Private Limited
  - xxxvi. Shah Foils Limited

- xxxvii. Repute Exim
- xxxviii. Bharat Heavy Electricals Limited
- xxxix. Divya Kitchenware Pvt Ltd.
- xl. Apex Tubes Private Limited
- xli. Punjab Stainless Steel Industries
- xlii. Honest Enterprise Ltd

- l. None of the importers has filed response to the questionnaire. However, M/s Paxal Corporation has filed submissions during the hearing.
- m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented / submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- n. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for the present purposes.
- o. The Non-Injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry has been worked out so as to ascertain whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- p. On-the-spot verification of the information/ data provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present final findings.
- q. Verification of the information provided by the producers/exporters and Government of Vietnam, to the extent deemed necessary and to the extent these parties have provided information and evidence, was carried out by the Authority and has been relied upon for the purpose of present final findings.
- r. The period of investigation for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from April 2017–March 2018 (12 months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the period of investigation.
- s. In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 15<sup>th</sup> February, 2019. All the parties who attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were advised to offer their rebuttals.
- t. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings to the extent considered relevant and necessary for the present purposes.
- u. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.
- v. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to appropriateness of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- w. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of the facts available.
- x. A Disclosure Statement was issued to interested parties on 19<sup>th</sup> July, 2019 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 27<sup>th</sup> July, 2019 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately in the present final findings.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 =₹- 65.33.

### C. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as “*Welded Stainless Steel Pipes and tubes*”.

#### C.1. **Submissions by domestic industry**

5. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

- a. The product under consideration is “*Welded Stainless Steel Pipes and Tubes*”. The product under consideration is largely made either from 200 series or 300 series steel (though there are some market for 400 series pipes as well), and the price of pipes made from different series of steel varies significantly.
- b. The goods produced by the domestic industry and those imported are like article.
- c. The use of PCN-wise data is important as there is significant difference in the cost and price of subject goods of different grades.
- d. With regard to the other interested parties’ allegation that PCN-methodology suggested by petitioners was erroneous, it is submitted that raw material cost vary significantly depending upon the series of steel used and conversion costs account for only 10-12% of the total cost. Further, the responding exporters have not demonstrated that there are no differences in cost and price structures due to difference in steel used.
- e. Subject goods of 200 series are primarily used for ornamental purposes, those of 300 series are mainly used for industrial and structural purposes, while those of 400 series is used for exhaust pipes. However, the price difference between the tubes and pipes is not on account of the usage, but on account of the grade of steel used.
- f. Responding to arguments regarding sub-types of industrial types, it is submitted that there are actually no significant price and cost differences between the pipes meant for different usages.
- g. Regarding the argument that only M/s Ratnamani Metals & Tubes Ltd. is engaged in production of industrial pipes, it is submitted that other producers, such as Hissar Steels Pvt. Ltd., Suman Steel Industries, Paras Bhavani Steel Pvt. Ltd, P.S. Raj Steels Pvt Ltd., etc. also produce this product.
- h. Regarding the importer’s argument that quality of subject goods from Vietnam is better than that produced domestically, it is submitted that Indian producers use inputs of BIS standards, whereas the Vietnamese producers procure inputs from China. Also, the Vietnamese producers are selling the subject goods under tags of “Made in India”, which itself demonstrates that their product is not superior to that of the Indian manufacturers.
- i. Responding to argument that range of products manufactured in Vietnam is not available in India, it is submitted that the Indian manufacturers have produced the subject goods of different size or thickness, and using different grade of stainless steel. In any case, pipes and tubes of different sizes can be made on the same machines, with minor retooling.

#### C.2. **Submissions by other interested parties**

6. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:

- a. The product under consideration produced in Vietnam is of far superior quality in terms of metallurgy and finishing.
- b. The range of products manufactured by Vietnamese industry is not available in India. Pipes and tubes of certain sizes and dimensions are not manufactured by domestic producers and even if the same are manufactured, the costs are prohibitive.
- c. Goods produced in India have a lot of gauge variation which ultimately impair usage.
- d. Since the Authority called for information to be submitted with regard to subject goods, and not on PCN basis, the data furnished by domestic industry on PCN basis holds no relevance.
- e. The methodology adopted for sub-categorization under 200 series and 300 series is erroneous as it does not capture difference in product sub-categories on account of cost and price differences.
- f. In India and world-wide, stainless steel pipes are broadly classified into three categories, that is, (a) ornamental & structural tubes, (b) exhaust tubes, and (c) tube & pipe for industrial applications.

- g. The market for industrial tube & pipe can be further broken down into (a) instrumentation & hydraulic tubes, (b) heat exchanger tubes, (c) hygienic tubes, (d) mechanical tubes, (e) process pipe, and (f) tubes and pipes used as a component of furnace, heater, air cooler, condenser and other industrial applications.
- h. PCN may be devised after giving due opportunity to all interested parties and on the basis of three broad categories namely (a) ornamental & structural tubes, (b) exhaust tubes, and (c) tube & pipe for industrial applications.
- i. The scope of domestic industry has been incorrectly determined considering four associations who are not themselves engaged in production of subject goods. Only the producers can be treated as domestic industry, and not associations.

### C.3. Examination by the Authority

- 7. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry.
- 8. The product under consideration in the present investigation, as defined in the initiation notification, is “Welded Stainless Steel Pipes and tubes”. The input material for welded pipes and tubes is stainless steel sheet/skelp/coil/plates which are formed into required shape and welded through suitable welding process. Pipes and tubes are generally made with similar production process. Further, the sheet/skelp/coil/plates can be of different types, depending upon the requirement.
- 9. The subject goods can be used for ornamental purposes, industrial and structural purposes and in exhaust pipes. The product under consideration is classified under Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975, and further classified under customs sub-heading 73064000, 73066100, 73066900 73061100 and 7306210. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.
- 10. The Authority proposed a PCN and invited comments from all interested parties with regard to the PCN methodology, vide letter dated 6<sup>th</sup> March, 2019. After receiving and evaluating comments from interested parties, the Designated Authority communicated PCN decided by the authority vide letter dated 14<sup>th</sup> March, 2019. The PCN methodology adopted is based on the grade of steel used, for the reason that the cost and price of the subject goods are largely impacted by the cost of raw material used. Accordingly, the PCN methodology followed is as under:
  - a. Pipes and tubes of 200 series stainless steel
  - b. Pipes and tubes of 300 series stainless steel
  - c. Pipes and tubes of 400 series stainless steel
- 11. The Authority finds that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The consumers importing the product under consideration have also purchased the same from the domestic industry.
- 12. As regards the contentions in respect of quality of the subject goods and the like articles produced by the domestic industry, it is noted while the importers alleged differences in the domestic and imported product, the foreign producers have not raised any such concern. The importers, while alleging quality differences, have not provided any verifiable information and evidence to demonstrate differences in the quality of the imported and domestically produced goods. The importer has not even filed response to prescribed questionnaire. The domestic industry has contended that it uses steel of BIS standards. The Authority further notes that in order to have fair and appropriate comparison between subject goods and goods produced by the domestic industry, the PCN methodology has been adopted. Accordingly, the Authority holds that no quality differences have been demonstrated between the imported product and goods produced by the domestic industry.
- 13. As regards the argument that the domestic industry does not produce all types, kinds, size and thickness of subject goods included in the product scope; the Authority notes that the interested parties have not specified any product type that is not produced by the domestic industry, nor adduced any evidence to show that the domestic industry has failed to provide any type or kind or size of the product. Therefore, the Designated Authority does not find any merit in the argument that all types, sizes and kinds of subject goods are not produced by the domestic industry.
- 14. In view of the above, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **D.1. Submissions by the domestic industry**

15. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:
- a. The petition was filed by four associations. Twelve producers provided injury and costing information at the stage of application. Post initiation and in response to initiation, ten more producers have provided their costing information.
  - b. The data of the producers that participated post initiation should be considered. Even in the past, the Designated Authority has added producers that provided relevant information post initiation as part of the domestic industry.
  - c. Since the petition has been filed by the four associations and all the producers of the product under consideration are a member of one or the other association, it should be considered that the application has been made "on behalf of domestic industry" and is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than fifty percent of the total production.
  - d. The production of the participating domestic producers constitutes a major proportion of the total domestic production.
  - e. Since there is no publicly available information with regard to total production and the industry belongs largely to the MSME sector, production in the period of investigation has been considered on the basis of the supply of raw material in the market.
  - f. The petitioners had sought information from the Ministry of Statistics & Programme Implementation under RTI. However, the Ministry has stated absence of relevant information.
  - g. As M/s Jindal Stainless is the major producer and biggest supplier of the raw materials of the subject goods in the Indian market. This company carries out detailed research on the market size and production by various producers in the country and tracks consumption of raw materials in India as its marketing requirement and the same can be used to establish Indian production.
  - h. Following the judgment of the Apex Court in Commissioner of Customs, Bangalore Vs. G. M. Exports, Rule 2(b) of the Countervailing Duty Rules must be read harmoniously with the definition of domestic industry under Article 16.1 of ASCM. Therefore, the word "shall" used in Rule 2(b) should be interpreted to mean "may", in line with the provisions of ASCM. Accordingly, the Designated Authority has discretion to consider the producers, who have imported the subject goods, as domestic industry for the present purpose. There should be no automatic exclusion of such producers. Some of the domestic producers, being small-sized companies, were not in a position to continue production operations at loss-making prices and were forced to import due to significant price difference between the domestic and imported product. Significant price difference between the domestic and imported product led to these producers to keep their production facilities idle and instead import the product, which itself is an evidence of injury being caused by the imports.
  - i. Even if the domestic producers that have imported the subject goods are treated ineligible domestic industry, the remaining participating producers would nevertheless constitute a major proportion in the domestic production.
  - j. Participating domestic producers constitute major proportion whether importing producers are considered eligible or ineligible domestic industry.
  - k. In response to the argument that domestic industry has not given declaration regarding imports, it was clarified that none of the producers that had provided data in the petition, have imported the subject goods.
  - l. Even for the other producers, the share of participating domestic producers increases if producers, that have imported, are excluded and there was nothing to be gained by the petitioners by not reporting the fact of imports. The petitioners, however, believe that these producers need to be included as the imports were made out of necessity.
  - m. In response to the argument that the list of members of association was not provided, it was highlighted that there was no requirement to provide the same. However, the list of members was furnished on being pointed out.
  - n. In response to the contention that details of 22 companies remain confidential, it is submitted that the non-confidential version of the letters filing the costing data formed part of the public file open for inspection and thus, the details of companies were known to all parties.

- o. Responding to the argument that associations are not domestic producers, it is submitted that associations are only petitioners, and not domestic industry. Under Rule 6(1), the application can be made by or on behalf of the domestic industry.
- p. Contrary to the arguments of the opposing parties, the petitioners had not excluded any producer for reason of imports and the standing was determined on the basis of gross Indian production.
- q. While the exporter and other interested parties have questioned the estimates of total domestic production provided in the application, none of these parties have been able to refute these estimates with such cogent evidence and a claim of domestic production.
- r. There is no merit in the argument that when the domestic industry is determined based on major proportion of total domestic production, the production of subject goods by importers cannot be excluded. Nor does the Rule in any way provide that if producers engaged in importation are excluded, then all remaining domestic producers must be considered, as has been argued by the exporters.
- s. Contrary to the arguments of the interested parties, M/s Maven Stainless had filed its data within the stipulated time i.e. 23rd October, 2018.

#### **D.2. Submission by other interested parties**

- 16. The submissions made by interested parties with regard to the scope and standing of the domestic industry are as follows:
  - a. Despite admitting that the applicants have no information on importers of subject goods, they have excluded a large number of producers on the pretext of importation.
  - b. Jindal Services Corporate Management Services Pvt. Ltd. merely acts as an internal advisor to the Jindal Stainless Group Companies and does not maintain information with regard to Indian production of subject goods.
  - c. Since a large number of producers belong to the MSME sector, the relevant information with regard to production is not available. As a result, the evaluation of 25% criteria is devoid of merits.
  - d. The onus of providing information regarding domestic production in India lies with the applicants and a solitary report by a Company, which is not even engaged in business of collecting such information, should not be relied upon unless an opportunity to review and rebut the same is provided to all parties.
  - e. The Panel Report in the case of China – Anti-dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from the United States and Manual of SOP of DGTR highlight the importance of establishing domestic production. In cases where a large number of producers are from MSME sector, the verification of total domestic production of product under consideration becomes even more important.
  - f. Of all applicants, only M/s Ratnamani Metals & Tubes Ltd., which is also an importer, is engaged in production of industrial pipes. Since none of the other applicants are engaged in production of industrial pipes, the same should be removed from the scope of product under consideration.
  - g. There are three methodologies for determining domestic industry, (a) domestic producers as a whole, (b) major proportion of domestic production, and (c) domestic producers excluding importers of subject goods. When the domestic industry has been defined as per major proportion of total domestic production, the production of subject goods by importers cannot be excluded. Under third methodology, no producer can be excluded unless they have imported the subject goods.
  - h. Since M/s Ratnamani Metals & Tubes Ltd. has admitted as having imported the subject goods, the applicants should be treated as non-cooperative.
  - i. The Authority has taken on record the data filed by M/s Maven Stainless at a belated stage, in contravention of the deadline of 23rd October, 2018.
  - j. Since a number of producers have turned out to be importers, the applicants would seek to modify the constituents of domestic industry or seek to substitute the importing producers with other additional producers. The Authority should not allow the applicants to file information as per their convenience.
  - k. Petition shows that a large number of producers of the subject goods in India are also importing.
  - l. Ratnamani is included as a domestic producer and also in the list of importers.
  - m. The use of the word “shall” in Rule 2(b) implies that the Authority has no discretion regarding exclusion of a producer who has imported subject goods.
  - n. Domestic industry has not given a declaration about the imports by them or their affiliate parties from subject countries.

- o. The petitioners have not provided information such as capacity, production for the other Indian producers. In the absence of the same, their claim of being domestic industry cannot be verified.

### **D.3. Examination by the Authority**

17. Rule 2(b) of the Countervailing Duty Rules defines domestic industry as follows:

*"domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry".*

18. The Petition has been filed on behalf of the domestic industry by following associations of domestic producers of the product under consideration in India
- i. Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association, New Delhi,
  - ii. Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association, Ahmedabad,
  - iii. South India Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association,
  - iv. Haryana Stainless Steel Pipe and Tube manufacturer Association.
19. At the stage of petition, twelve (12) domestic producers, being members of the aforesaid associations, filed relevant injury data and required costing information. Post initiation of the investigation, ten (10) more producers of the subject goods in India responded and provided relevant injury data along with costing information. The information filed by the producers was made available to all interested parties.
20. In the absence of any publicly available information, the petitioners have estimated gross domestic production on the basis of information provided by the major supplier of raw material in India. The opposing parties have disputed use of such an approach/ methodology for determining the domestic production. The Authority notes that the present industry belongs to MSME sector. Further, the unit of measurement used for commercial transaction in the PUC is not standard one and it could either be in terms of length or numbers or weights etc. The applicants submitted that, for these reasons, it was not possible to quantify eligible Indian production by collating production of each and every producer.
21. Since no concrete information with regard to Indian production is compiled or available either with the associations, or with any agency, which would be accessible to the associations as public information; considering various facts and circumstances of the present case, the Authority considers that resort to best information available is reasonable and appropriate. Difficulties arising in quantifying gross domestic production in case of fragmented industry has been well recognised. While the interested parties have objected to the use of information provided by Jindal Stainless, it is noted that these interested parties have not provided any evidence to demonstrate that the domestic production determined is understated. The Authority holds that in facts and circumstances like the present case, domestic production can be quantified and determined on the basis, such as consumption of raw material in the country. Since M/s Jindal Stainless is the largest supplier of raw material in the country, and has direct interest in ascertaining the Indian production, its information with regard to Indian production constitutes a reliable estimate of Indian production of the subject goods. On the basis of the said steel consumption, the domestic production has been estimated as between 1,60,000 MT to 1,70,000 MT. The Designated Authority has considered the average of the two i.e. 1,65,000 MT as total domestic production.
22. It is clarified that the information provided by the raw material producer is not limited to its own sales. The said information is based on gross Indian production. Merely because the information has been provided by a domestic supplier of raw material does not imply that the same pertains to production and sales of that party alone. It is further clarified that the information with regard to injury to the domestic industry is based on production, sales and other injury data of participating companies.
23. The interested parties have opposed the consideration of additional ten producers, who have filed injury data post initiation. The Authority considers that it would be appropriate to include these companies within the scope of domestic industry for the purpose of the determination for the following reasons:
- a. On one hand, the interested parties contend that the size of the domestic industry is small whereas on the other the interested parties have contended that information of more producers should not be added after initiation. This is inherently contradictory. Greater participation in the investigation on the contrary will result in more representative data and ensure improvement in quality of investigation.
  - b. In a situation where information with regard to domestic producers as a whole is not available, the Rules require the Authority to consider those producers whose collective output constitutes a major proportion of the total domestic production.

- c. The Appellate Body in European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China [WT/DS397/AB/R] observed that the domestic industry should be defined in such a manner so as to reduce the risk of distortion in the injury analysis. It follows thus that the higher the proportion of participating producers, lesser the likelihood of distortion in the injury determination.
- d. The inclusion of these additional domestic producers only ensures that the scope of domestic industry is representative of the domestic producers as a whole.
- e. Contrary to the claim of other interested parties, non-confidential version of the consolidated injury information was shared with the interested parties before the oral hearing. In fact, oral hearing scheduled was postponed only to allow the interested parties to defend themselves appropriately and adequately. Therefore, the interested parties received due opportunity to comment upon the information and defend their interest.
- f. The domestic producers consented for verification of information provided by them and provided non confidential version of their information, which was kept in the public file. Accordingly, the information has been accepted after due verification of the information filed.

In view of the foregoing, the Designated Authority has considered the data filed by the 10 producers after initiation of investigation .

- 24. The interested parties have argued that some of the domestic producers participating in the investigation have imported the subject goods into India. It has also been contended that a number of producers are importers of the product under consideration. The petitioners have also admitted that some imports might have been made by some domestic producers through some affiliate, rather than importing in their own name. The issue has been examined at length. The import data received from the DGCI&S has also been analysed. The Authority has only checked names of the petitioners in the DGCI&S to ascertain whether any of them have imported the product. It is seen that three of the domestic producers, namely, M/s Ratnamani Metals & Tubes Limited, M/s Quality Stainless Private Limited and M/s ASB Tubes have imported the subject goods into India.
- 25. The domestic industry has argued that the Authority should consider the domestic producer importing the product as eligible domestic industry. The Designated Authority however holds that considering the language of CVD Rules, it would not be appropriate to treat a domestic producer as eligible domestic industry if such producer is itself an importer or related to importer or exporter of subject goods. In view of above, the Authority holds that M/s Ratnamani Metals & Tubes Limited, M/s Quality Stainless Private Limited and M/s ASB Tubes cannot be treated as part of eligible domestic industry.
- 26. The interested parties have contended that the petitioners have excluded domestic producers on the basis that they are importers of the subject goods. In response, the petitioners have clarified that no producer has been excluded from domestic production while establishing standing. Production of 1,65,000 MT has been considered as gross domestic production for the reason stated above and the same has been considered for establishing standing in the present case. The Authority further notes that production of producers, which have been found to have imported the subject goods, has now been excluded from the total eligible domestic production and eligible production of petitioners for determination of standing, as required under the Rules.
- 27. The authority notes that as of now, the 19 eligible petitioners companies account for 49.44% of the domestic production. It is further noted that subsequently i.e after initiation of the investigation 86 more firms/ companies producing the subject goods have expressed support in favour of the petition. There is no opposition to this petition by any domestic producer. Hence, the requirement of domestic industry standing in terms of CVD Rules is met. It is further noted that even with 12 petitioner companies at the time of initiation, the requirement of standing is met.
- 28. From the above, it is noted that the participating eligible domestic producers account for a major proportion of the total domestic production and constitute domestic industry within the meaning of the Countervailing Duty Rules.

#### **E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY**

##### **E.1. Submissions by the domestic industry**

- 29. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
  - a. The participating exporters have violated the provisions of Rule 8, the practice and the trade notice on confidentiality.
  - b. The non-confidential version of the response does not permit a reasonable understanding of the confidential information and the exporters have not provided any reasons for not providing a non-confidential summary.
  - c. The exporters have completely omitted certain exhibits from the non-confidential version of the responses.
  - d. The exporters have claimed information which is easily available in the public domain as confidential.

- e. In response to allegation that domestic industry has claimed excessive confidentiality, it was submitted that most of the data for the domestic industry on an actual basis and its confidentiality claims are consistent with the Trade Notice No. 10/2018.
- f. The petitioners have provided actual number or trends of all injury parameters which is sufficient for the opposing interested parties to argue on merits of the case and have disclosed much more information as compared to the producers and exporters of the subject countries.
- g. Annual reports and costing formats of the participating producers contain business sensitive information in relation to production, sales, selling price, cost of sales, profit and return on investment of such producers and cannot be disclosed.
- h. Even the updated petition, post initiation, was filed before the issuance of Trade Notice No. 10/2018, that is, on 23rd August, 2018.

#### **E.2. Submissions by other interested parties**

30. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
- a. The petitioners cannot keep assessment of subsidy as confidential from the exporters.
  - b. In contravention of Trade Notice 10/2018, the petitioners have failed to provide (a) Relationship of petitioners with foreign producers / exporters / importers / domestic producers; (b) Name and addresses of all other Indian Producers; (c) Volume and value of production by all other producers except the domestic industry. The domestic industry has not provided above information in actual figures.
  - c. Right of defence of interested parties cannot be fully exercised since significant data has not been properly indexed in non-confidential version in the petition.
  - d. In Section VI, reference has been made to Annexure 6 or annual report, which has been claimed confidential on the ground of being business sensitive information.

#### **E.3. Examination by the Authority**

31. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of the Countervailing Duty Rules provides as follows:
- “Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.*
- (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.”*
32. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.
33. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

34. The petitioners have adequately disclosed their assessment of subsidy in the petition. No specific instance has been pointed out where the petitioners have not disclosed an information publicly available. It is seen that the petitioners have provided relevant information prescribed under Trade Notice 10/2018. No specific instance has been pointed out where the petitioners have not disclosed an information publicly disclosed by them, but claimed confidential in the present petition. The Authority considers that the costing information by nature is confidential and is not susceptible to summarisation. The Authority has been consistently permitting all interested parties to claim confidentiality on costing information, as disclosure of this information can cause significant prejudice to the legitimate rights of these parties.

#### **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

##### **F.1. Submissions by other interested parties**

35. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:
- The imports from Vietnam are necessitated because of (a) superior quality of goods, (b) stable pricing, and (c) stable delivery schedule. On the other hand, goods manufactured by domestic producers are not up to the mark, the prices are unstable and delivery is erratic.
  - The basis on which the investigation has been initiated has no merits since manufacturers in Vietnam are not known to subsidized the subject goods.
  - Supplier of the goods exports only 15-20% of their total production to India and that too after repeated persuasion in view of high demand for quality pipes.
  - Imposition of countervailing duty may jeopardize healthy relationship that Vietnam and India have enjoyed over the last five decades.
  - The non-confidential version of the verification report of M/s Ratnamani Metals & Tubes Pvt. Ltd. and other domestic producers should be placed in the public file, in accordance with Article 12 of the ASCM and WTO Panel Report in EU – PET (Pakistan).

##### **F.2. Submissions by the domestic industry**

36. In response to the submissions of the interested parties, the domestic industry submitted as under:
- Since a number of producers belong to the MSME sector and the margins involved are nominal, some of the producers have been forced to turn to importation.
  - Considering the massive increase in imports in a relatively short period, and that the injury caused to the domestic industry would be difficult to repair, there is a need for retrospective imposition of duty.
  - As regards the argument that the countervailing investigation would damage friendly relations with Vietnam, it is submitted that as signatories to ASCM, both GOI and GOV have agreed to not grant countervailable subsidies, as would cause injury to the industry of another country, and accepted the prerogative of the importing country to take necessary action to protect its industry against such subsidization.
  - It must be examined if the exports from Vietnam are passing the test of value addition required for claiming concessional customs duty. The raw material is imported into Vietnam and the value addition to make the subject goods is below 20%, whereas the Rules of Origin under AIFTA require a value addition of 35%. However, the subject goods are exported to India as originating in Vietnam.
  - The exporters are flouting value addition conditions, leading to a loss of Rs.125-150 crores to the Government of India.
  - With regard to the argument that levy of duty is against the public interest, it is submitted that it is not for GOV to comment upon public interest in India. The foreign producers have caused material injury to the Indian domestic industry and the same must be answered by the GOV. The duty will ensure level playing field for both Indian and foreign suppliers and the same will not restrict availability of the subject goods.
  - With regard to the argument that the imports from Vietnam are necessary, it is submitted that the subject goods manufactured in India are produced using stainless steel of BIS standard and therefore the question of inferior quality due to gauge variation or any other reason does not arise. Further, the pricing of the subject goods is dependent upon the spot prices of chrome, iron, nickel, copper, etc., and therefore, subject to change. With regard to delivery schedule, it was submitted that transit time from Vietnam to India is much more than the time taken by domestic producer to process the order.

##### **F.3. Examination by the Authority**

37. The Authority notes that countervailing duty, if imposed , shall not prevent imports from Vietnam, but shall only remove the distortion caused by the allegedly subsidised imports from the subject countries..

38. Considering the significant volume of imports from Vietnam, it cannot be concluded that the exporters in Vietnam supply only an insignificant share of their production in India.
39. As regards the effect of imposition of duty on relations between the countries, the Authority notes that imposition of trade remedial measures is only done after a thorough investigation by the importing WTO member country. The investigation is regulated by the ASCM and the domestic anti-subsidy laws, and therefore is fair in nature. Thus, any trade remedial measure imposed for providing level playing field is in accordance with the ASCM and in keeping with spirit of WTO rules for global trade.
40. Regarding the request for non-confidential version of the verification report, the Authority does not, as a practice, keep the verification report of any interested party in the public file. Moreover, a Verification Report is only to confirm, corroborate and authenticate the data and information that has already been submitted by the interested party. The purpose of the verification report is to notify the party submitting the information regarding the information that has been verified and that which could not be verified.
41. As regards the argument of the domestic industry that the goods supplied from Vietnam do not satisfy the criteria of value addition as prescribed under the Rules of Origin, it is noted that the same is for the Customs Authorities to examine at the time of importation and is not within the scope of the present investigation.

#### **G. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN**

42. The petition was filed by the domestic industry which provided *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies in the subject countries. The domestic industry filed a submission showing how each of the scheme identified in the petition was properly included in the petition and was required to be investigated.
  - a. **SUBSIDIES INVESTIGATIONS IN RESPECT OF CHINA**
43. Government of China (GOC) was invited for consultation, which was held on 27<sup>th</sup> June, 2018 in New Delhi.
44. After consultation and examination of the schemes as provided in the petition, the Authority identified following three programs wherein investigation was not necessary. No investigation was therefore initiated in respect of these programs:
  - i. Program No. 1: The State Key Technology Renovation Projects Fund
  - ii. Program No.13: Ad hoc subsidies
  - iii. Program no 17: Pension Fund Grants
45. The Authority initiated investigations for the following CVD programs wherein the producers of the product under consideration may have potentially received countervailable benefits

#### **I. Programs in the form of grants**

1. Program No. 2: Famous Brands Program
2. Program No. 3: Direct Government Grants given by Jiangsu Province
3. Program No. 4: Grants for Antidumping Investigations
4. Program No. 5: Superstar Enterprise Grant
5. Program No. 6: Research & Development (R&D) Assistance Grant
6. Program No. 7: Export Assistance Grant
7. Program No. 8: Grants to Baoshan Steel
8. Program No. 9: Grants for Listing Shares
9. Program No. 10: Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province.
10. Program No. 11: Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation.
11. Program No. 12: Various grants provided to Shandong Province
  - a. Program No. 12 (a): Shandong Province's Special Fund for the Establishment of Key Enterprise Technology Centers
  - b. Program No. 12 (b): Shandong Province's Award Fund for Industrialization of Key Energy-Saving Technology
  - c. Program No. 12 (c): Shandong Province's Environmental Protection Industry Research and Development Funds
  - d. Program No. 12 (d): Shandong Province's Construction Fund for Promotion of Key Industries
12. Program No. 14: Grants provided by Hebei Province
  - a. Grants under the Science and Technology program of Hebei Province
  - b. Government of Shijiazhuang City Export Award

13. Program No. 15: Various grants provided to Fuyang City
  - a. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes
  - b. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
  - c. Grants under Excellent New Products/Technology Award
  - d. Investment grants from Fuyang City Government for key industries
  - e. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
  - f. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees
  - g. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
14. Program No. 16: Grant - Special Funds for Fostering Stable Growth of Foreign Trade
15. Program No. 18: Provincial Government - Equipment Grant
16. Program No. 19: Treasury Bonds Loans or Grants
17. Program No. 20: Interim Measures of Fund Management of Allowance for Zhongsham Enterprises to Attend Domestic and Overseas Fair
18. Program No. 21: International Market Fund for Export Companies
19. Program No. 22: Special Fund for Energy Saving Technology Reform
20. Program No. 23: Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
21. Program No. 24: Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
22. Program No. 25: State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies.

**II. Programs in the form of export financing and export credit**

23. Program No. 26: Export Seller's Credit
24. Program No. 27: Export Buyer's Credit
25. Program No. 28: Other Export Financing from State-Owned Banks

**III. Programs in the form of tax and VAT incentives**

26. Program No. 29: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors
27. Program No. 30: Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to operate for a Period not Less than 10 Years
28. Program No. 31: Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs
29. Program No. 32: Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises and Certain Domestically- Owned Companies Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipment's
30. Program No. 33: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
31. Program No. 34: Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs
32. Program No. 35: Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies
33. Program No. 36: VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically-Produced Equipment
34. Program No. 37: Tax concessions for Central and Western Regions
35. Program No. 38: Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials')
36. Program No. 39: Tax credit concerning the purchase of special equipment
37. Program No. 40: Enterprise Income Tax Rate Reduction in the Tianjin Port Free Trade Zone
38. Program No. 41: Income Tax exemption for investment in domestic technological renovation
39. Program No. 42: Income Tax Reductions under Article 28 of the Enterprise Income Tax Law
40. Program No. 43: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones- & Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones

41. Program No. 44: Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region
42. Program No. 45: Tariff and VAT Exemptions for Imported Equipment
43. Program No. 46: Tax Offsets for Research and Development at FIEs
44. Program No. 47: Tax Preference Available to Companies that Operate at a Small Profit
45. Program No. 48: Tax Reductions for Export-Oriented FIEs
46. Program No. 49: Tax Reductions for Technology or Knowledge-Intensive FIEs
47. Program No. 50: Various local tax discounts (Shandong Province, Chongqing City, Guangxi Region Zhuang, Tax privileges to develop central and western regions)
48. Program No. 51: VAT deduction on fixed assets in the Central region
49. Program No. 52: Shanghai Municipal Tax Refund for High-tech Achievement Commercialization Projects
50. Program No. 53: Local income tax and reduction program for the productive FIEs
51. Program No. 54: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
52. Program No. 55: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs in Guangdong and Hainan Island
53. Program: No. 56: Industrial Parks promoting growth of Steel Industry
54. Program No. 57: Other tax privileges of Ma'anshan

#### **IV. Programs in the form of provision of goods and services**

55. Program No. 58: Provision of Electricity for Less than Adequate & Fair Market Value Remuneration
56. Program No. 59: Provision of Water for less than Adequate Remuneration
57. Program No. 60: Land Use Rights for SOEs
58. Program No. 61: Government Provision for Steel Scrap for Less than Adequate Remuneration
59. Program No. 62: Provision for Coking Coal for Less than Adequate Remuneration
60. Program No. 63: Hot rolled Steel (HRS) Provided by Government at Less than Fair Market Value
61. Program No. 64: Provision of Cold-Rolled for Less Than Adequate Remuneration
62. Program No. 65: Raw Materials Provided by the Government at Less than Fair Market Value
63. Program No. 66: Reduction in Land Use Fees, Land Rental Rates and Land Purchase Prices
64. Program No. 67: Exemptions from Administrative Charges for Companies in Industrial Zones and the Provision of Land-Use Rights for LTAR – Land Use Rights in Certain Industrial and SEZs
65. Program No. 68: Export Restrictions on Coke
66. Program No. 69: Shanghai Municipal Subsidy to Coal-Fired Power Plants for Emissions Reduction
67. Program No. 70: Purchase of Goods by the Government for higher than adequate Remuneration

#### **V. Programs in the form of preferential loans and lending**

68. Program No. 71: Allowance to Pay Loan Interest
69. Program No. 72: Policy Loans
70. Program No. 73: Preferential Loans for SOEs (State Owned Enterprise)
71. Program No. 74: Credit Loan Guarantee by GOC
72. Program No. 75: Preferential export financing from the Export-Import Bank of China.

#### **VI. Programs in the form of equity infusion**

73. Program No. 76: Debt for equity swaps
74. Program No. 77: Debt Forgiveness
75. Program No. 78: Deed Tax

- 76. Program No. 79: Dividend exemption between qualified resident enterprises
  - 77. Program No. 80: Unpaid dividends
  - 78. Program No. 81: Equity infusions
46. Post initiation, the GOC and producers/exporters of the product under consideration were advised to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed and were given adequate time and opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.
47. Government of China did not file questionnaire response. M/s Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals Co. Ltd. [“Jiuli Hi Tech”] is the only producer/ exporter from China which has filed questionnaire response.

#### **Submissions by the domestic industry**

48. The following submissions have been made by the domestic industry in the petition and during the course of the present investigations.
- i. The Governments of subject countries are providing prohibited or actionable subsidies to its producers/exporters of the product under consideration. The domestic industry has provided *prima facie* evidence of existence of such subsidy schemes, including documents relating to legislation and policy.
  - ii. Petitioner has provided documents such as relevant laws & regulations, WTO reports, media reports, government reports, independent reports & studies, countervailing duty investigations determination of other investigating authorities. The petitioner has provided elaborate information regarding various subsidy programs.
  - iii. The identified programs constitute a countervailable subsidy for following reasons:
    - a. There is a financial contribution by government or a public body, where the government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits), government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;
    - b. Benefit is conferred on the Chinese producers/ exporters of the PUC; and
    - c. The program is specific within the meaning of Indian Rules and ASCM.
  - iv. Relevant laws and regulations, WTO reports, various Government reports, media reports and independent studies and analysis, findings of other investigating agencies in their anti-subsidy investigations clearly constitute sufficient evidence of the existence of countervailable subsidy programs in subject countries. These evidences were made available to all interested parties, including the Governments and the known producers and exporters in subject countries.
  - v. The term "Government of People's Republic of China" should cover all levels of government, i.e. Federal, Central, Provincial, Regional or Local Govt. such as Municipal or City or Township Govts. Village or Local legislative, administrative or judicial agencies/bodies; and State-owned enterprises, operating under the direct or indirect control or influence of the GOC which operate as ‘public bodies’ within the meaning of the term as defined in the ASCM.
  - vi. The responding exporter has barely mentioned any details on the benefits received out of the alleged schemes. Therefore, in the absence of a response by the Government of China, the countervailability of the schemes should be presumed.
  - vii. The questionnaire responses filed by the responding exporters are not consistent with the questionnaire format prescribed by the Directorate. The responding exporters have suppressed vital facts and have filed incomplete questionnaire responses.
  - viii. The investigation has been initiated by the Authority only after scrutiny of the evidence provided by the petitioners with regard to the existence and nature of the subsidy program.
  - ix. The petition contains the evidence in the form of legal basis, nature of the scheme, financial contribution and specificity, enterprises that are eligible and that might have availed the benefits under particular scheme, decision of other investigating authorities demonstrating that the schemes actually exist and determined as countervailable with subsidy margins worked out and any other web research.
  - x. As regards information concerning availment of benefits by producers/ exporters of the product under consideration, various schemes identified by the petitioners can be categorized into – (a) country wide programs, (b) sector specific programs, (c) region specific program.

- xii. The petitioners have given sufficient evidences in order to link the program either with the product under consideration or the enterprise or the region where the enterprises producing the product under consideration are located. The petitioners are not bound to relate the program with the producer/exporters of the subject goods.
- xiii. With respect of GOC schemes, the petitioners have further submitted as follows
  - (a) the producers/exporters of the subject goods have received countervailable subsidies under the following categories of various levels of Govts., classified under six broad categories. Various programs classified under these categories are listed below:
    - I. Grants
    - II. Export Financing and export credit
    - III. Tax and VAT incentives
    - IV. Provision for goods and services at LTAR
    - V. Preferential loans and lending
    - VI. Equity infusion
  - (b) Since the Government of China has not filed questionnaire response nor provided any meaningful information regarding alleged subsidy programs, the countervailability and actionability of the schemes cannot be questioned. The Authority must draw adverse inference and proceed on the basis of facts available with regard to the existence of schemes and their countervailability.
  - (c) The Authority has already established the actionability of the subsidy schemes and quantified the margins on the raw material of the subject goods in China. The exporter should provide complete details of their raw material and other inputs procurement and establish that there is no subsidy in the same.
  - (d) Jiuli has not disclosed all subsidies received by it and has suppressed and misrepresented facts with an intent to mislead the Designated Authority and obtain a lower subsidy margin.
  - (e) The nature of the program is the deciding factor to define the program and the benefit. Nomenclature of the programs is of little importance so long as a scheme exists and provides a benefit. Authority should consider the nature of the scheme, and the legal basis behind the same to define the program.
  - (f) The investigation is not restricted to the scheme alleged in the petition and would also include any information with regard to any benefit not alleged by the petitioners during the course of investigation.

#### **Submissions by other interested parties**

49. The following submissions have been made by other interested parties:

- a. Out of the 78 subsidy programs initiated by the Authority, the responding exporter, M/s Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals Co. Ltd. has accepted availing the benefit out of the following schemes:
  - a. Program No. 7: Export Assistance Grant
  - b. Program No. 33: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
  - c. Program No. 35: Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies
  - d. Program No. 39: Tax credit concerning the purchase of special equipment
  - e. Program no 42: Income Tax Reductions under Article 28 of the Enterprise Income Tax Law
- b. The Authority initiated investigation into programs for which the petitioners have not even made proper allegation. The petitioners did not establish the existence of the three elements comprising a countervailable subsidy, namely, (a) financial contribution, (b) benefit and (c) specificity.
- c. The authority should justify (a) whether it has assessed the adequacy and accuracy of the evidence concerning subsidization; and (b) the basis on which it considers that the petition contains adequate and accurate information for each subsidy alleged.
- d. None of the programs identified by the petitioners is substantiated with facts and figures that are benefitting the producer/exporter listed in the petition. In fact, the petitioners have themselves admitted in the petition that they do not have evidence to establish that the subsidies have been received by each producer of the product.

- e. Anti-subsidy duty may be imposed only if there is subsidization at the time of imposition of duty.
- f. When the petitioners are unable to assess the effects of subsidy, the Authority could not have determined, at the time of initiation, that the subsidy margin is above de – minimis.
- g. The petitioners cannot keep assessment of subsidy as confidential from the exporter.
- h. No additional information has been sought by the Authority from Jiuli, evidencing that the response filed by Jiuli is complete.
- i. Non-cooperation by Government of China does not lead to rejection of response filed by Jiuli. The exporter should be accorded benefit of individual margin.
- j. Loans obtained by Jiuli from State-Owned Commercial Banks fall outside the purview of subsidy as the interest rate is determined by market forces.
- k. Export Assistance Grant is granted by the Huzhou Commerce Bureau to the exporter for participating in overseas exhibitions. Such grant is not an export subsidy in terms of Article 3 of the ASCM, as it is not contingent on export performance.
- l. Rule 11 specifically excludes subsidy programs conferred on persons engaged in manufacturing, producing or exporting the article for research activities. Tax deduction for R&D expenses is excluded from scope of countervailable subsidy.
- m. Income Tax Reductions under Article 28 of the Enterprise Income Tax Law were introduced to promote new and advanced technology and is available to all enterprises who fulfil the eligibility criteria. Therefore, it is not specific.
- n. Tax credit concerning the purchase of special equipment was introduced to promote upgradation to environment-friendly equipment, which is excluded from scope of countervailable subsidies under Rule 11(1)(c)(iii).
- o. ASCM/Rules do not provide any methodology for including new program identified during the course of the investigation. Most of the programs listed in the Annual Report of Jiuli do not relate to the subject goods. If the Authority is satisfied that there exists a degree of specificity and benefit for such programs, it may issue a supplementary questionnaire to Jiuli and Jiuli would provide any information required.

#### **Examination by the Authority**

50. Government of China has not filed the questionnaire response. The sole responding producer/ exporter, M/s Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals Co. Ltd. has filed questionnaire response and has accepted availment of benefit under following schemes/programs:
- a. Program No. 7: Export Assistance Grant
  - b. Program No. 33: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
  - c. Program No. 35: Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies
  - d. Program No. 39: Tax credit concerning the purchase of special equipment
  - e. Program no 42: Income Tax Reductions under Article 28 of the Enterprise Income Tax Law
51. The above acceptance in the questionnaire response of the producer shows existence of the above-mentioned schemes/programs. However, while GOC has not filed questionnaire response, the questionnaire responses filed by the said producer was verified, including an onsite verification in China.

#### **Grants**

52. In the questionnaire response the exporter M/s Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals Co. Ltd. has itself admitted availment of benefit under Program No. 7: Export Assistance Grant.
53. Analysis of the annual report of the sole responding producer/exporter M/s Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals Co. Ltd. shows that the company has received subsidies from the Government Authorities in China and these have been reported in the annual report under the head of “Government Subsidies” for grants related to Asset, Income and Finance.
54. Accordingly, the Authority holds that these Govt. subsidies in the form of Grants constitute financial contribution by a public body conferring a benefit to the company concerned and are specific in nature. Accordingly, the subsidy margin under the head of ‘Grants’ reported in the annual report has been considered for quantifying CVD margin. For the purpose, total amount reported in the annual report under the head “Govt. subsidies” has been considered as the benefit conferred. The amount of CVD margin thus determined is \*\*\* %.

### **Tax and VAT incentives**

55. The GOC and its agencies administer a number of tax programs, which provide tax exemption/reduction/remission to certain categories of enterprises based on their location or nature of the enterprises or technological innovation.
56. The exporter M/s Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals Co. Ltd. in the questionnaire response has admitted availing benefit under Program No. 33: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses. The exporter has contended that it is a permitted subsidy, as it concerns R&D. The Authority however holds that it is actionable subsidy. The subsidy margin on this account comes to \*\*\*%.
57. The exporter M/s Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals Co. Ltd. in the questionnaire response has admitted availing benefit under Program No. 35: Preferential tax policies/income tax reductions for companies that are recognized as high and new technology companies. The Authority has determined the margin as \*\*\* %
58. The exporter M/s Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals Co. Ltd. in the questionnaire response has admitted availing benefit under Program No. 39: Tax credit concerning the purchase of special equipment. The Authority has quantified the subsidy margin on the basis of tax rebate received under the program. The subsidy margin so quantified is \*\*\*%
59. The DI has provided the quantification of Program No 51: VAT rebate received by the company on fixed assets for Central region. The Authority has quantified the subsidy margin by taking increase in fixed assets from the year 2016 to 2017 by the responding exporter and the VAT rebate received on the same taking sales turnover as denominator. The CVD margin so quantified is \*\*\*%.

### **Provision of goods and services for less than adequate remuneration (LTAR)**

#### **a. Land-use rights**

60. The authority notes the absence of questionnaire response from GOC, which acquires relevance in respect of availability of land use rights to Chinese producers. The authority in earlier investigations had examined the existence of countervailable subsidies in the form of land use rights and had noted that Government of China is providing land use rights to certain enterprises at less than adequate remuneration, which amounts to countervailable subsidies on account of financial contribution, resultant benefit and specificity by virtue of being limited to certain type of enterprises. Therefore, the Authority earlier noted that the provision of land use rights by the GOC is a countervailable subsidy program.
61. Authority initiated investigations in the present investigation for the following programs
  - a. Program No. 60: Land Use Rights in Industrial and Other Special Economic Zone,
  - b. Program No. 61: Land Use rights for SOEs
  - c. Program No. 62: Land Use rights for FIE.

Since the authority has examined countervailability of land use rights in the past and further GOC has not filed questionnaire response, in the absence of sufficient cooperation from the Government of China (GOC), the authority has considered land use right as countervailable subsidies equivalent to subsidy margin given in the table below.

#### **b. Utilities (electricity)**

62. The notice of initiation refers to subsidy Program No. 58 regarding provision of electricity for less than adequate remuneration. In earlier CVD investigations, it has been noted that public bodies in China provide electricity to industrial enterprises at less than adequate remuneration and have accordingly been countervailed. In view of absence of questionnaire response from the Govt. of China, the Authority holds program no. 58 countervailable. The subsidy margin determined is \*\*\*%.

#### **c. Raw materials**

63. It is noted in the domestic industry claim that the authority has earlier determined subsidies in raw material (viz. Certain Hot Rolled and Cold Rolled flat products of stainless steel) used to manufacture the PUC in the year 2017 as 18.95%. Further, the only responding exporter from China was asked to provide details of raw material purchases including the source of the same. The information provided by the said exporter showed that the company has sourced substantial quantities of raw material from both within Chinese market as also through imports. It was found by the Authority from the analysis of the data so submitted that the price difference between the domestic and imported purchase prices was \*\*\*%. The responding exporter has not reported any difference between the domestically purchased and imported raw material. Therefore, the subsidy margin in the raw material has been determined to be \*\*\*%

### **Preferential Loans and Lending**

64. The authority initiated investigations in respect of Program No. 71, 72, 73, 74, and 75. While GOC did not file questionnaire response, the sole responding exporter contended that the loans are provided by commercial banks.

Since GOC has not filed questionnaire response, the authority has not been able to investigate whether the commercial loans given by the banks are without any direction or control by a public body.

65. The Authority has earlier determined that GOC provides loans at discounted rates. The Authority noted that preferential lending has resulted in financial contribution in the form of direct transfer of funds and determined countervailing duty against such preferential lending by comparing the interest rate charged by the state-owned bank from the exporter receiving loan with the commercial benchmark interest rate. This benefit is specific because it is limited to certain type of enterprises in China.
66. The Authority notes that the loans to the Chinese enterprises (which includes producers of the PUC as well) provides a benefit to these enterprises. Since the authority has examined countervailability of these programs in the past and further since GOC has not filed questionnaire response in the form and manner prescribed, the authority considered that the Chinese producers of the PUC have been benefited from loans at less than benchmark rates. As per facts available on record, the Authority considers that a benefit of \*\*\*% is conferred on the Chinese producers of the PUC.

#### **Conclusion on CVD Schemes in China**

67. In view of the foregoing, the Authority finds that the Chinese producers have benefited from countervailable subsidies. On the basis of the investigations conducted, facts on record available and considering absence of questionnaire response from the GOC, Authority has quantified margin of subsidies in various subsidy schemes as shown in table below.

SN	Name of Scheme	Subsidy Margins M/s Jiuli	Subsidy Margins Residual
I	<b>Grant Program</b>	0-5%	0-5%
II	<b>Tax and VAT Incentives (a+b+c+d as below)</b>	0-5%	0-5%
IIa	• Tax rebate for high and new technology enterprises	0-5%	0-5%
IIb	• VAT rebate	0-5%	0-5%
IIc	• Tax credit on Capital assets	0-5%	0-5%
IId	• Tax rebate on R&D	0-5%	0-5%
III	<b>Provision for goods and services at LTAR (a+b+c as below)</b>	25-30%	25-30%
IIIa	• Raw material	20-25%	20-25%
IIIb	• Land use right	0-5%	5-10%
IIIc	• Electricity LTAR	0-5%	0-5%
IV	<b>Preferential loans and lending</b>	0-5%	0-5%
	<b>Total Subsidy Margin (Range)</b>	<b>25-35%</b>	<b>30-40%</b>

#### **b. SUBSIDIES INVESTIGATION IN RESPECT OF VIETNAM**

68. Government of Vietnam was invited for consultation, which was held on 6<sup>th</sup> July, 2018 in New Delhi.
69. After the consultation and examination of the schemes as provided in the petition, the Authority identified two programs wherein investigation was not necessary. No investigation was therefore initiated in respect of these programs:
  - i. Program No 4: Preferential Import Tariff
  - ii. Program No 12: Vietin Bank for Export financing/Activity

70. The Authority initiated investigations for the following CVD programs

#### **I. Schemes identified as tax incentives and exemptions**

1. Program No 1: Income Tax Preferences under Chapter V of Decree 24 (Implementation of the Law on Enterprise Income Tax)
2. Program No 2: Import duty exemption or reimbursement for raw material

3. Program No. 3: Exemption on corporate income tax for enterprises

**II. Schemes identified as export financing and export credit**

4. Program No 5: Preferential lending to exporters

5. Program No 6: Export Promotion Program

6. Program No 7: Export credits from the Vietnam Development Bank

7. Program No. 8: Export Support Credit

**III. Schemes identified as investment incentives**

8. Program No. 9: Preferential Lending for investors

9. Program No. 10: Interest rate of the investment credit loans

10. Program No. 11: On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises.

**IV. Schemes Identified as benefits from banks**

11. Program No. 13: Financial Guarantees by Vietin Bank

**V. Schemes Identified for being located in specific zones**

12. Program No 14: Land Preferences for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones under Decree 142

**VI. Schemes Identified for incentives on use of utilities**

13. Program No. 15: Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents.

71. Post initiation, the GOV and producers/exporters of the product were advised to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed and were given adequate time and opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.

72. The Government of Vietnam has filed questionnaire response and provided some information with regard to some of the schemes/programs. Further, the following producers/ exporters of the subject goods from Vietnam filed questionnaire response:

i. Sonha SSP Vietnam Sole Member Co. Limited.

ii. Nam Cuong Metal Company Limited

iii. OSS Dai Duong International Joint Stock Company

iv. Tuan Dat Metal Company Limited

v. Gia Anh Joint Stock Company

vi. Ha Anh Stainless Steel Company Limited

vii. Gia Anh Hung Yen Company Limited

viii. Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co. Ltd.

ix. Steel 568 Co. Ltd.

73. The responses filed by the abovesaid producers/exporters and GOV were examined and verified.

**G.1. Submissions by the domestic industry**

74. With respect to Vietnam schemes, the petitioners have further submitted as follows:

(a) the producer/exporter of the subject goods have received countervailable subsidies under the following categories of various levels of Govts.

(i) Tax Incentives and Exemptions

(ii) Export financing and Export Credit

(iii) Investment Incentives

(iv) Benefits from banks

- (v) Benefits in specific Zones
  - (vi) Incentives on use of utilities
  - (vii) Free trade agreements, including ASEAN, Indo-ASEAN, China-ASEAN agreement
- (b) Vietnamese producers are sourcing steel, the primary raw material, from China at less than adequate remuneration. Since this procurement is under Govt. program (China-ASEAN trade agreement), the Authority should investigate and consider that the subsidies in steel procured from China cannot be ignored for the present purposes.
- (c) Since the exporters in Vietnam have imported hot rolled steel from China and processed it to produce the subject goods in Vietnam, the value addition cannot be more than limits prescribed under Indo-ASEAN agreement, unless the Vietnamese producers include Chinese manufacturing as part of their production. The Vietnamese producers have exported the subject goods, claiming the same to be of Vietnamese origin, in order to take benefit of concessional rate of duty under the ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) only on the strength of Chinese production. The A-I form issued by the competent authority in Vietnam clearly shows that the Vietnamese producers claimed and such competent authority in Vietnam and India accepted a value addition on the basis of manufacturing carried out in two countries – Vietnam and China.
- (d) The production process undertaken by the Vietnamese, as declared to customs authorities and as declared to Designated Authority cannot be different. If a different process has been claimed, the Designated Authority in any case should reject the questionnaire response holding that the Vietnamese producers have made contradictory claims between two authorities in India. If the Vietnamese producers have claimed production process employed in China and Vietnam as the process carried out by them for fulfilling the value addition condition, the Designated Authority should consider the same for the present purposes. If the input disclosed to the Authority is steel, showing a value addition of about 10%, it is a clear case of misrepresentation of facts and making contradictory claims before two authorities in India.
- (e) Unless scrap is used, the value addition in producing the subject goods shall remain much less than that prescribed under the ASEAN-India FTA for claiming preferential tariff treatment. However, the government authorities in Vietnam have issued certificates showing the country of origin as Vietnam and value addition beyond the minimum limits prescribed under the agreement. Either GOV should agree that it has allowed Vietnamese producers to export the subject goods to India based on fraudulent certificates of origin, or, the GOV should agree that the value addition has been claimed based on production carried out in two countries – China and Vietnam.
- (f) Since production process from scrap to steel has been reported by the producers of the product as their production process, the Vietnamese producers have benefited by the Chinese subsidised steel upto the stage of hot and cold rolling. The quantum of such subsidization has been determined by the Authority in previous CVD investigation as 18.95%.
- (g) Since A-I form value addition is based on production process in China, the Vietnamese producers deemed to have carried out that production process while producing and selling the product. There can be no different explanation for the claims made by the Vietnamese producers in the A-I form.
- (h) The Vietnamese producers should provide complete purchase details of steel, transaction wise, and showing country of supplier. Unless this information is provided, the Authority cannot determine whether the Vietnamese producers were benefited by the production process deemed to have been carried out by them in China.
- (i) GOV has conferred countervailable subsidies to its exporters, which have allowed them to export to the Indian market at injurious prices.
- (j) GOV must have been fully aware of the production process claimed by the Vietnamese producers, while permitting issuance of the certificates. Further, the GOV must have carried out verifications, as mandated under the trade agreement, periodically, to ensure that the declarations given by the Vietnamese producers are correct. The GOV therefore now cannot plead ignorance.
- (k) The Questionnaire response filed by the responding exporters from Vietnam such as OSS Dai Dong and Vinlong Stainless Steel clearly show purchase of raw material from China or a related entity/parent company is in China.
- (l) There was no production facility either in Vietnam or within ASEAN from the stage of steel melting. The production facility available either in Vietnam or within ASEAN and value addition from that

stage upto the product under consideration under no circumstances can lead to the value additions as are being reported under A-I form (which shows value addition of \*\*\*%).

- (m) GOV is trying to mislead the authority on the legal position with respect to non-actionable subsidies under the WTO, as the provisions expired at the end of 1999. Rule 11 of the Countervailing Duty Rules should be read in consonance with the Articles of the ASCM.
- (n) The petitioners have quantified the subsidy margin for both the producers/exporters from Vietnam based on the information available in the public domain, in addition to the subsidy margin determined by Authority in the raw material vide notification No 14/18/2015-DGAD dated 04th July, 2017.
- (o) There is no provision that requires that countervailing duty can be imposed only when there is subsidy at the time of imposition. If the existence and availment of subsidy during period of investigation is established, countervailing duty can be imposed, whether such subsidy is in existence or availed at the time of imposition of countervailing duty. Subsidies for fixed assets can be considered over the entire AUL.
- (p) If the governments and the producers/exporters of the subject countries are non-cooperative, the Authority must apply adverse facts and determine the countervailability of the schemes based on evidences already available on record and proceed further in determining the subsidy margins.

#### **G.2. Submissions by other interested parties**

75. With respect to Vietnam schemes, the other interested parties have submitted as follows:

- a. Since India and Vietnam are rapidly developing friendly relations, solution for problems arising from bilateral trade must be arrived through consultation. Countervailing investigation would damage interests of Indian invested enterprises in Vietnam.
- b. There is no evidence of existence of a benefit for exporting producers from Vietnam in respect of all direct tax programs mentioned in the petition.
- c. Decree 24/2007 /ND-CP was replaced by Law No. 14/2008/QH12, and was therefore, not applicable during the period of investigation.
- d. Countervailing duty should not be imposed because Vietnamese exporters did not receive any countervailable subsidies from the Government of Vietnam.
- e. Exporters did not receive any loan from the Government of Vietnam or Vietnam Development Bank, and all outstanding loans were provided by commercial banks at market rates of interest and without any exemption.
- f. While five of the exporters did not receive any income tax or import duty preferences, the benefits received by the sixth exporter were based on its location in a disadvantaged region. Therefore, it does not constitute a countervailable subsidy as the benefit was based on location in a disadvantaged region and hence, is non-actionable.
- g. All five exporters did not receive any exemption or reduction with regards to land rent, electricity and water fee.
- h. Government of India also provides tax incentives to units situated in SEZ, less developed areas, incentives for special industries, North east and Himalayan states etc. as well as to exporters such as drawback, EOU, EPCG, etc.

#### **G.3. Examination by the Authority**

76. The Authority notes that few of the participating producers/ exporters have not provided the requisite details asked from them during the verification. Accordingly, the subsidy margin in these cases have been determined on the basis of facts available with the Authority as per the Rules.

#### **I. Programs identified as Tax Incentives:-**

- A. **Program No 1: Income Tax Preferences under Chapter V of Decree 24 (Implementation of the Law on Enterprise Income Tax)**  
and
- B. **Program No. 3: Exemption on corporate income tax for enterprises**
- 77. The petitioners contended that these programs are governed by GOV and administered by Ministry of Finance and Ministry of Commerce. GOV submitted that the Enterprise Income tax 2003- Law no. 09/2003/QHI has ceased and new law has taken its effect on January 2008, and therefore the said benefit is not applicable during POI, and none of the responding exporters are benefited. Petitioners however pointed out towards Article 19(3) & 4 of

No.14/2008/QH12 clearly deals with enterprises which enjoy enterprise income tax incentives under Enterprise Income Tax Law and submitted that enterprises continue enjoying these incentives for the remaining duration (i.e. residual benefits) under Enterprise Income Tax Law No. 09/2003/QH11. Petitioners further submitted that in case enterprise income tax incentives (including tax rate incentives and tax exemptions & reductions duration) are lower than the tax incentives specified in this Law, the tax incentives under this Law apply for the remaining duration. Petitioners have also submitted that Article 20.2 of the Decree No. 218/2013/NĐ-CP clearly demonstrates that enterprises having investment projects and by the end of tax period of 2013 still are entitled to the incentives of corporate income tax. In other words, the petitioners submitted that even when the law is repealed, residual benefit remains available to the enterprises who were earlier eligible for the same. The program no. 1 has been replaced by program no. 3. Some of the responding exporters have even admitted having received benefit under program no.3.

78. Responding exporters from Vietnam, Nam Cuong Metal Company Vietnam, Dai Duong OSS Co. Ltd, Tuan Dat Metal Company Ltd, Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co. Ltd, Steel 568 Co. Ltd, Gia Anh Joint Stock Company, Ha Anh Stainless Steel Co. Ltd, Gia Anh Hung Yen submitted that they have not applied or received any benefit during POI, because the said Decree is terminated in 2009. These companies have however not stated anything with regard to residuary benefits available under the earlier program.
79. Sonha SSP Vietnam Sole Member Co. Ltd stated that the law has been terminated in 2009 but same has amended and supplemented by Law No. 32/2013 I QH13 dated 19/06/2013 of the National Assembly, which amended and supplemented some of articles of the Law on Enterprise Income Tax, effective from January 1,2014. It has further stated that Law No. 71/2014 I QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly was amended and added some of articles of the tax law, effective from 01/01/2015. The company has also stated that Decree No.218/2013/NĐ-CP dated 26/12/2013, detailing and guiding Law on corporate income tax, Effective 15/02/2014. Since the company does not fall under the said criteria, the company has not benefited.
80. The authority notes that these programs are countervailable. Some producer/ exporter(s) have availed the benefit under these programs whereas some of producer/ exporters have not. Accordingly, the subsidy margins determined by the Authority have been given in the table below.

#### **C. Program no. 2: Import duty exemption or reimbursement for raw material**

81. The petitioners contended that these programs are governed by GOV and administered by Ministry of Finance and Ministry of Commerce, which provides exemption on payment of import duty for the importation of raw materials into Vietnam for further production which is contingent on export performance.
82. GOV submitted that import duty is exempted for imported raw material used in production of the exported goods. The amount of the exemption is equal to the amount of the duty corresponding to the value of imported materials actually used in the production of the finished goods that are exported. The program is monitored by the General Department of Vietnam Customs (GDVC) under the Ministry of Finance. To monitor implementation of this policy, the GDVC under the Ministry of Finance is in charge of development of a system to track (1) the amount of imported material actually consumed for the production of export products, including scrap and discarded products that are lost in the production process (this is called the "consumption norm"); and (2) whether the exported products are actually exported.
83. Responding exporters Sonha SSP Vietnam sole Member Co., Steel 568 Co, HA ANH Stainless Steel Company Limited, Tuan Dat Metal Company Limited, OSS Dai Doung International Joint Stock, Gia ANH Hung Yen Company Limited, NamCoug Metal Company Limited have claimed to have not received any benefit under import duty exemption or reimbursement for imported raw material because tariff schedule has been scheduled at 0% duty rates. Vinlong Stainless Vietnam Com Ltd stated that they have not benefited from the said program as they are Export processing enterprises and not subject to any import/export duties & VAT exemptions.
84. With regard to submissions made by the GOV and the responding exporters Steel 568 Co, HA ANH Stainless Steel Company Limited, Tuan Dat Metal Company Limited, OSS Dai Doung International Joint Stock, Gia ANH Hung Yen Company Limited, Nam Coung Metal Company Ltd. stated that as per the AESAN -India Free Trade Agreement (AIFTA) the import tariff in effect at the time of importation for the raw materials was 0% and hence no duty was payable and no benefit could have been received.
85. The authority notes that the said program provides financial contribution and benefit is conferred for import duty exemptions on raw materials for exported goods, the exemptions cannot exceed the amount of duty levied; otherwise, the excess amounts exempted confer a countervailable benefit.

#### **D. Program No. 5: Preferential lending to exporters**

86. The petitioners have submitted that the program no. 5 relating to preferential lending to exporters is governed by GOV and administered by Ministry of Finance, State Agencies, State Bank of Vietnam and Other Commercial banks, State capital investment corporation (SCIC); Vietin Bank (SOE Bank), Vietnam Development bank which provides low interest loans and where 50% of loans which are provided and granted by state owned commercial

banks in Vietnam as the banking sector in Vietnam is controlled by State-owned State bank of Vietnam, which sets maximum interest rates. Petitioners further submitted that the interest rate cannot be accepted as the producers of the subject goods have acquired loan at subsidized rate. The producers in Vietnam have benefitted in the form of reduced rate of interest.

87. The GOV stated that there is no such policy that directs the banks to operate as per state or national policy in Vietnam and that commercial banks make lending decisions independently after considering various factors with respect to the borrowers and these decisions have no correlation to the government authority. Vietnam Development bank is a state-owned commercial bank and was established by Decision 108/2006/QD-TTg on May 2006. Under Decree No. 32/2017/NĐ-CP, state investment credit is provided. The bank provides three key types of benefits, preferential lending to exporters is one of them. However, it is completely inaccurate on the part of the petitioners to allege that a policy bank in Vietnam operates as per the directives of the State or the National government. The loan amount under the present program is provided under market-based interest rates and is not subsidized or reduced.
88. None of the responding exporters have given any explanation or description about the program. They have either stated that they have not received any benefit under the said program or that they are not eligible for benefit under this program. However, none of the exporters have provided complete details of each of the loans taken by them and the rate of interest paid thereon to demonstrate that there is no differential interest on different categories of loans taken by them.
89. The Authority notes that loans can be provided at concessional rates by a bank which may be Govt. owned or privately controlled. Even if a bank is privately controlled, it cannot be said that there is absence of countervailability if the private bank offers loan at the concessional rate at the direction of the central bank/ government.
90. The Authority also notes that the said program has been examined by US-Laminated Woven Sacks and countervailed in respect of Vietnamese producers.
91. Accordingly, the subsidy margin has been determined by the Authority as per the table given below.

#### **E. Program No 6: Export Promotion Program**

92. Petitioners claimed that this program aims at enhancing trade promotion activities, developing export markets, creating initial conditions for building material foundations in service of trade promotion and contributing to raising the business capacity of the relevant enterprises under investigation. Petitioners have stated that the present program is contingent on export performance.
93. GOV submitted that export promotion program, is governed by Ministry of Industry and Trade (MOIT) through their local body who governs trade promotion activities for expanding trade to foreign markets, bordering areas and even mountainous regions. The program emerged in 2010 and has been in accordance with the National Trade Promotion Policy. The eligibility criteria for the program is that the specific enterprise must have a trade promotion plan which must meet the laid down objectives and should include plan for promotion of local products over imported ones. GOV further submitted that none of the responding exporters have benefited during the POI. However, GOV has not provided list of producers/exporters of the product who have not responded and who may have benefited under the program.
94. Responding to the contentions of the GOV, petitioners submitted that as per Decision No. 137 / QĐ-BCT dated 16/01/2017 of the Minister of Industry and Trade, National Trade Promotion Program in 2017 clearly indicates that scheme is replaced with the said notification and scheme is still in existence. The authority notes that the said development has not been brought on record by the GOV, nor existence of Decision No. 137 / QĐ-BCT dated 16/01/2017 denied by the GOV.
95. The authority notes that the program is regulated by a public body and provides for trade promotion activities which is held countervailable.
96. Accordingly, the subsidy margin has been determined as per the table given below.

#### **F. Program No. 7: Export credits from the Vietnam Development Bank**

97. Petitioners have submitted that Vietnam Development Bank is granting export credits to the Vietnamese producers/exporters. The program is governed by GOV and administered by Ministry of Finance, State Agencies, State Bank of Vietnam and Other Commercial banks, State capital investment corporation (SCIC), Vietin Bank (SOE Bank), Vietnam Development Bank. These banks provide low interest cost loans and where loans are provided and granted by state owned commercial banks. Petitioners have further submitted that the banking sector in Vietnam is controlled by State owned “State Bank of Vietnam”, who sets maximum interest rates for the purpose.
98. The GOV has stated that Vietnam Development Bank is a state-owned commercial bank and was established by Decision 108/2006/QD-TTg on May 2006. The bank provides three key types of benefits – preferential lending to the exporters being one of them. They have further stated that it is completely inaccurate of the petitioners to allege

- that a policy bank in Vietnam operates as per the directives of the State or the National government and that the loan amount under the present program is provided under market-based interest rates and is not subsidized or reduced.
99. Responding to the submissions made by GOV and responding exporters, petitioners have submitted that no detailed explanation and description of the program has been provided by GOV or responding exporters; and they have simply stated that they have not received any benefit under the said program or they are not eligible for benefit under this program without giving any explanation to support their statement.
  100. The Authority notes that loans provided by public body or at the direction of public body, if provided at concessional rates, may constitute countervailable subsidies.
  101. The Authority also notes that the said program has been examined by other investigating authorities, including Canada in cold rolled steel & copper fitting, EU in polyester staple fiber, US in frozen warmwater shrimp and have been countervailed.
  102. Accordingly, the subsidy margin has been determined as per the table given below.
- G. Program No. 8: Export Support Credit**
103. Petitioners have submitted that the said program is provided to exporters to receive credit, at concessional rates, based support on the exportation of certain goods. The export support will be applicable only to those exporters that are involved with the investors and have the capacity to repay the debt, the project must have completed the investment and construction stage and investor must have been evaluated by the Development Assistance Fund for financial plans and loan repayment plans.
  104. GOV has stated that the said program has been started in 2001 and terminated in 2007 and none of the responding exporters are benefited from the said program.
  105. Responding to the GOV contention, the petitioners have submitted that Article 8 and 9 of decree 32/2017 provides that loan repayment period is 12 years. In other words, the petitioners claimed that the program provided residual benefits. However, GOV and the responding exporters have not reported that there is any residuary benefit under the program.
  106. The Authority noted the contention of the petitioners. The Authority also notes the contention of the petitioners about medium and long-term investment loans under the program for investment projects of producing, manufacturing or processing export goods with export revenue accounting for at least 30% of total annual revenue. The Authority notes that the said program has been evaluated by other investigating authorities such as Canada in cold rolled, copper fitting; EU in polyester staple fiber, US in frozen warmwater shrimp cases and countervailed the same.
  107. The Authority holds that the benefit under this program is incumbent upon export performance and hence countervailable. Accordingly, the subsidy margin has been determined as per the table given below.
- H. Program No. 9: Preferential lending for investors**
108. The petitioners have contended that credits at preferential rates are provided to investors in Vietnam. The program is administered by Ministry of Finance, State Agencies, State Bank of Vietnam and Other Commercial banks, State capital investment corporation (SCIC); Vietin Bank (SOE Bank), Vietnam Development Bank.
  109. The petitioner has further contended that this program provides low interest loans by state owned commercial banks in Vietnam as the banking sector in Vietnam is controlled by State Bank of Vietnam, who sets maximum interest rates.
  110. The GOV submitted that Vietnam Development Bank is a state-owned commercial bank and was established by Decision 108/2006/QD-TTg on May 2006 and Decree No. 75/2011/NĐ-CP. The bank provides three key types of benefits, preferential lending to exporters is one of them. They have stated that it is completely inaccurate on the part of the petitioners to allege that a policy bank in Vietnam operates as per the directives of the State or the National government. The loan amount under the present program is provided under market-based interest rates and is not subsidized or reduced.
  111. Responding to the contentions of the GOV, the petitioners have submitted that the claim of the GOV regarding the interest rate being derived from market practices is not correct. The producers of the subject goods have acquired a loan from the GOV controlled bank at a subsidized interest rate. Petitioners have further stated that interested parties have either simply stated that they have not received any benefit under the said program or they are not eligible for benefit under this program without giving any explanation to support their statement.
  112. The Authority notes the contention of the domestic industry that loans are provided at concessional rates in Vietnam to the enterprises. While stating that the rates are fixed based on market practices, neither GOV nor the responding exporters have provided complete details of various loans obtained by the responding exporters, and

interest thereon to establish that these loans were in fact obtained at market prices. The GOV has also not provided showing documents relating to fixation of interest rates by its central bank.

113. The Authority notes that the said program has been examined by other investigating authorities such as in US-Certain Steel Nails and countervailed the same.
114. The Authority notes that the benefit under this program is countervailable. Accordingly, the subsidy margin has been determined as per the table given below.

#### **I. Program No. 10: Interest rate of the investment credit loans**

115. Petitioners submitted that GOV allows Vietnam Development Bank, to act as a policy bank. The Bank, as per Decisions 108/2006/QD-TTg allows for investment credit loans to be provided to enterprises that are seeking to invest into projects which are on the list of those eligible for investment credit stipulated by the Government.
116. The petitioners further submitted that Article 21 of Decree 75 specifies the lending interest rate provisions and under Clause (1) of the same it is stated that “export lending interest rates shall be reported by the Chairman of the Vietnam Development Bank Management Board to the Ministry of Finance for publication on the principle of compatibility with market interest rates.” Further, it cannot be said that the Central bank is not acting in accordance with the policies of the GOV.
117. Petitioners have also submitted that Decree No. 75/2011/NĐ-CP is only an updated legal text of Decree 151/2006/NĐ-CP and provides necessary changes to various provisions of the old Decree which includes the relevant provisions for both investment Credit and export credit programs of the Vietnam Development bank.
118. Petitioners also referred to Circular No. 76/2015/TT-BTC on Regulations on Credit Loans for Investment, which specifies the interest rate for investment credit loans and export credit loans.
119. The GOV stated that there are no such provisions that allow banks to operate on the state or national policy in Vietnam and that commercial banks make lending decisions independently after considering various factors with respect to the borrowers and these decisions have no correlation to the government authority.
120. The producers/exporters have stated not having acquired a benefit under the program. Further, the decree documents show that only certain types of investments, which are listed under Appendix 1 of the Decree No. 75/2011/NĐ-CP are eligible for the benefit.
121. The authority notes the submission of the petitioners. The Authority notes that the said program has been examined by other investigating authorities such as US- Certain Steel Nails and countervailed this program.
122. The Authority notes that the benefit under this program is countervailable. Accordingly, the subsidy margin has been determined as per the table given below.

#### **J. Program No. 11: On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises**

123. The petitioners have submitted that GOV provided investment support to foreign investors for establishing small and medium scale enterprises in order to facilitate and support the investment projects for small and medium enterprises.
124. The GOV has submitted that in order to facilitate development of small and medium sized enterprises (SMEs), GOV issued Decree 56/2009/NĐ-CP to provide guidelines for support of SMEs, which applies to SMEs throughout the country regardless of any form and type of business. The Ministry of Planning and Investment (MPI) acted as the body assisting the Government in performing the unified state management of assistance to the development of small and medium sized enterprises, and subsequently providing guidelines to implementation of the Government's policy regarding support for SMEs. Local authorities are responsible for designing and implementing SMEs support programs based on principles and guidelines from the central government.
125. GOV also stated that Vinlong Stainless Steel Company Limited qualify as a SME. Vinlong did not apply and has not got any benefit under programs. None of the responding exporters have availed the benefit under the said scheme.
126. The Authority also notes that the said program has been evaluated by other investigating authorities, such as US-Certain Steel Nails and countervailed the same.
127. The Authority notes that the benefit under this program is countervailable. Accordingly, the subsidy margin has been determined as per the table given below.

#### **K. Program No. 13: Financial Guarantees by Vietin Bank**

128. Petitioners submitted Vietin Bank, which is a state-owned commercial bank, provides financial guarantee on exportation of Vietnamese domestic goods, promoting the export performance of the enterprise.

129. The GOV has not provided any information relating to this subsidy program and has stated that none of the companies under investigation have received a benefit under the program. However, some of the responding producer/ exporters have admitted having availed the said benefit, but not for PUC.
130. The domestic industry has submitted that the program allows credit institutions to provide financial guarantee to enterprises fulfilling the requisite provisions. They have quoted the legal basis as under:

Article 3, Clause (1) defines bank guarantee as “a form of credit granting, which the guarantee party commits in writing with party receiving guarantee that it shall perform finance obligation of the guaranteed party upon the guaranteed party fails to perform or insufficiently perform the obligation committed with party receiving guarantee; the guaranteed party must take over debt and repay for the guarantee party as agreement.” Further, as per Article 11 clause (2) (a) the Credit institutions that are providing the guarantee benefit must be licensed by the State Bank to business in and supply such service.

131. The benefit under the present program allows enterprises to receive guarantees for the extension of the export business which has to be paid later on at a preferential interest rate to the Credit institution or commercial bank.
132. The Authority notes that the benefit under this program is countervailable. Accordingly, the subsidy margin has been determined as per the table given below.

**L. Program No. 14: Land Preferences for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones under Decree 142**

**M. Program No. 15: Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents**

133. The petitioners have submitted that the GOV has provided land based incentives to encourage enterprises to set up investment projects in areas of specially difficult socio-economic conditions. Enterprises involved in investment projects and located in specified zones, regions and who are listed as encouraged industries, are granted exemption and reduction from payment of land rent.
134. GOV has stated that, in order to encourage enterprises to invest into geographical regions or areas with especially difficult socio-economic conditions, the GOV pursues a policy of exemption and reduction of land rent for companies who have investment projects in such regions. Exemption of land rent also applies to investment projects in special cases such as construction of lodging houses for poor workers, dormitory for students in universities, agricultural land for minority citizens in mountainous areas, etc., as well as investment projects in encouraged industries. Based on their investment certificate or business registration, the relevant local tax authority determines the amounts payable by the land tenants. None of the responding exporters have availed the said benefit. However, no details of the relevant documents relating to administration of the program have been provided. Further, the GOV has provided no details showing non-granting of benefit to the responding or non-responding exporters of the PUC.
135. The Authority notes that the said program has been examined by other investigating authorities in the past, including evaluation done by Canada in cold rolled & copper fitting, EU in polyester staple fiber and countervailed.
136. The authority notes the following contentions of the GOV and the exporters with regard to provision of land for less than adequate remuneration:
- (i) if an investor, regardless of foreign or domestic, obtains the LUR from a private source including developer, to which a LUR was already granted, to establish factory or company premise, LUR transfer price would be determined by free negotiation between the two parties.
  - (ii) in the case where an investor obtains LUR of a parcel of land via Land Allocation and Land Lease from the State, price of land allocation and land lease will be determined mainly on the basis of on auction winner price. Starting price for auction would not be lower than the price list applicable to that land parcel promulgated by the Provincial People's Committee. The price list is officially promulgated by the Provincial People's Committee every five years on 01 January of the beginning year. (Article 114, Land Law 2013). Sample of price lists promulgated by four provinces of Hung Yen, Hanoi, Long An and Tien Giang is given in the Annex 7.2.
  - (iii) if no auction takes place, the Local Government will determine the price of that land parcel based on the actual value of the land under normal circumstances (“specific land price”), which involves participation of council for land price appraisal. The council for land price appraisal comprises the head of the Local People's Committee (provincial level) as the chairperson, representatives of relevant agencies, and an organization that provides consultancy on land price determination. (Article 114, Land Law 2013).
  - (iv) to ensure determined land prices are in line with market price, the GOV uses five land pricing methods, namely direct comparison method, subtraction method, income-based method, surplus-based method and land price coefficient method. Details of these methods and their application are given in Article 4 and 5 of Decree No. 44/2014/ND-CP on the regulations on land prices. These pricing methods are widely used all over the world and are

recognized internationally. They are applied not only in determining specific land price but also in constructing the land price lists by the provincial level authorities.

- (v) regarding the LUR revocation, the State can recover LUR in the following cases (Section 1, Chapter VI, Land Law 2013):

1. For national defense and security; socio-economic development in national and public interest; or
2. Due to violations of the law and regulations on land;
3. Due to termination of land use in accordance with law, voluntary return of land, or the risk of threatening human life.

Thus, if the recovery of LUR is made for national defense and security or for socio-economic development in national and public interest, the State shall compensate to the LUR owner for land and remaining investment cost on land of the LUR owner.

137. Thus, the GOV contended that neither the GOV has given any specific benefit like lower or no lease rental to the PUC (Welded Stainless Pipe and Tube) industry or to the regions where the PUC producers are located nor any of the PUC producer has availed any benefit under this program.
138. The Authority notes that land is owned by the GOV and price of land is determined by them and some authorities like EU, US and Canada have countervailed these programs.
139. The Authority notes that the benefit under this program is countervailable. Accordingly, the subsidy margin has been determined as per the table given below.

#### **Non-alleged Subsidy**

##### **“Import duty exemption for equipment for equipment and machinery to create fixed asset”.**

140. GOV stated in their questionnaire response that apart from the “Import duty exemption or reimbursement for raw material”, there are other “Import duty exemption for equipment for equipment and machinery to create fixed asset”. The said program is administered by Ministry of Finance department of Vietnam Customs(GDVC).
141. Import duty exemption on imports of equipment and machinery to create fixed assets is provided under the Law on Import and Export Duty 2016 Article 16.11 of the Law on Import and Export Duty 2016 and Article 14 of Decree134/2016/NĐ-CP provide that imported goods to create fixed assets for companies subject to investment preferences are exempt from import duties. These imported goods include machinery and equipment; components, parts, spare parts for assembly or operation of machinery and equipment; raw materials for the manufacture of machinery and equipment, components, parts, or spare parts of machinery and equipment; special use vehicles in a technological line directly used for a manufacture project; and building materials that cannot be domestically-produced.
142. GOV stated that Dai Duong only imported equipment and machinery to create fixed assets in 2010 and thus it only received this benefit in 2010, a point of time long prior to the POI. Since the benefit is conferred to capital assets the said benefit for average useful life and hence Dai Duong OSS have availed the said benefit.
143. The Authority notes that the benefit under this program is countervailable. Accordingly, the subsidy margin has been determined as per the table given below.

#### **Conclusion on CVD Schemes in Vietnam**

144. In view of the foregoing, the Authority finds that the Vietnamese producers are benefited from countervailable subsidies. On the basis of the investigations conducted, facts on record, and the investigations conducted in the past, and considering absence of full cooperation from few of the Vietnamese participating producers/ exporters of PUC, Authority has quantified various subsidy schemes and margin of subsidies therein as shown in table below. It is seen by the Authority that the quantum of CVD margins are significant and above de-minimus except in case of M/s Sonha SSP Vietnam Sole Member Co. Limited and M/s Steel 568 Co. Ltd.

P. No.	Name of the Program	Son Ha SSP Vietnam	Nam Cuong Vietnam and Tuan Dat Metal Company Ltd.	Dai Duong OSS Co. Ltd.	Gia Anh Hung Yen and Gia Anh Joint Stock Company
P.1	Income Tax Preferences under Chapter V of Decree 24 (Implementation of the Law on Enterprise Income Tax)	NIL			

P. No.	Name of the Program	Son Ha SSP Vietnam	Nam Cuong Vietnam and Tuan Dat Metal Company Ltd.	Dai Duong OSS Co. Ltd.	Gia Anh Hung Yen and Gia Anh Joint Stock Company
P.3	Exemption on corporate income tax for enterprises		NIL	0-5%	0-5%
P.2	Import duty exemption on reimbursement for raw material	NIL	NIL	NIL	NIL
P.5	Preferential lending to exporters	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
P.6	Export Promotion Program	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
P.7	Export credits from the Vietnam Development Bank	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
P.8	Export Support Credit	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
P.9	Preferential Lending for investors	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
P.10	Interest rate of the investment credit loans	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
P.11	On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises.	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
P.13	Financial Guarantees by Vietin Bank	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
P.14	Land Preferences for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones under Decree 142	0-5%	0-5%	0-5%	0-5%
P.15	Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents				
Other	Import duty exemption for equipment and machinery to create fixed asset	NIL	0-5%	0-5%	0-5%
<b>Total Subsidy Margin %</b>		De-minimus	***	***	***
<b>Total Subsidy Margin (Range %)</b>		<b>De-minimus</b>	<b>10-20%</b>	<b>10-20%</b>	<b>10-20%</b>

P. No.	Name of the Program	Ha Anh Stainless Steel Co. Ltd.	Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co. Ltd.	Steel 568 Co. Ltd	Residual
P.1	Income Tax Preferences under Chapter V of Decree 24 (Implementation of the Law on Enterprise Income Tax)	0-5%	0-5%	NIL	0-5%

P. No.	Name of the Program	Ha Anh Stainless Steel Co. Ltd.	Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co. Ltd.	Steel 568 Co. Ltd	Residual
P.3	Exemption on corporate income tax for enterprises				
P.2	Import duty exemption on reimbursement for raw material	NIL	NIL	NIL	NIL
P.5	Preferential lending to exporters	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
P.6	Export Promotion Program	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
P.7	Export credits from the Vietnam Development Bank	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
P.8	Export Support Credit	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
P.9	Preferential Lending for investors	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
P.10	Interest rate of the investment credit loans	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
P.11	On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises.	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
P.13	Financial Guarantees by Vietin Bank	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
P.14	Land Preferences for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones under Decree 142				0-5%
P.15	Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents	0-5%	0-5%	0-5%	
Other	Import duty exemption for equipment and machinery to create fixed asset	0-5%	0-5%	NIL	0-5%
<b>Total Subsidy Margin %</b>		***	***	De-minimus	***
<b>Total Subsidy Margin (Range %)</b>		<b>10-20%</b>	<b>10-20%</b>	<b>De-minimus</b>	<b>10-20%</b>

## H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

### H.1. Submission by the domestic industry

145. The submissions made by domestic industry are as follows:

- There has been a flood of imports from the subject countries, which have increased by 662% over the injury period.
- Within a period of only one year, the subject imports have increased to nearly 3.5 times from \*\*\* MT in 2016-17 to \*\*\* MT in the period of investigation.
- The imports from subject countries have increased in relation to domestic production from 27% in to 80% from 2016-17 to 2017-18.

- d. The increase in imports is way beyond the increase in demand for the subject goods.
- e. The imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling is positive and significant.
- f. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry. However, most of the domestic producers being part of the small-scale sector, the producers do not take an order unless they get some margins. Therefore, the aspect of price suppression or depression may not be as noticeable as is seen in general in chemical, petrochemical or steel industries.
- g. Despite the domestic industry increasing its capacity with expectation of catering to the increasing demand, it has not been able to increase its production and sales commensurately.
- h. The domestic industry had been operating at less than \*\*\*% capacity throughout the period despite there being ample demand in the market. The capacity utilization of the domestic industry has declined by \*\*\*%.
- i. The subject imports have eaten into the market share of the Indian industry.
- j. The domestic producers being part of MSME industry cannot allow a huge blockage of inventories and therefore produce only when they have orders or are sure of order booking.
- k. The profitability of the domestic industry has declined steeply over the period.
- l. The cash profits and return on investment of the industry have also witnessed a decline.
- m. All profitability parameters of the domestic industry have registered a decline and in case of volume parameters, the growth of the domestic industry has been sub-optimal.
- n. The imports have increased to 1.5 times of that in period of investigation in the 6 months post period of investigation.
- o. Owing to the small scale of operations and nominal margins, a number of domestic producers have been forced to import and some are even working as de-facto commission agents for the exporters for keeping their livelihood.
- p. The increase in imports post period of investigation has been prompted by communication of M/s Sonha SSP Vietnam Sole Member Co., Limited, wherein it has assured the importers that no duties would be levied on exported products at least for a period of 6 months and that it would reimburse any countervailing duty imposed.
- q. Imposition of tariff quotas by European Union, increase in tariff rates by US, and imposition of anti-dumping duty by Thailand and Turkey have created a further threat of aggravated injury to the domestic industry.
- r. Owing to the small investment required for producing the subject goods, the companies in China have responded to the imposition of duties on raw materials of PUC by India by increasing the exports of product under consideration (PUC).
- s. Since tariff duty on imports from China to Vietnam is nil under China-ASEAN agreement, the raw materials are exported to Vietnam and thereafter, the product under consideration is imported into India at concessional rate of duty.
- t. Injury to the domestic industry has not been caused by any other known factor.
- u. The causal link between subsidized imports and injury to the domestic industry is evident from the following:
  - i. There has been a significant increase in imports and such imports are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the Indian industry has lost its place in the market and it has not been able to increase its production commensurate to the increase in capacity and demand.
  - ii. The selling price of domestic industry has reduced and it is facing loss per unit sold.
- v. In response to the argument that the decline in capacity utilization was due to increasing demand, it was submitted that the domestic industry had not been able to increase its production in line with the increasing demand. Furthermore, the nature of the product under consideration is not such that the producers require significant time to optimize production capacities.
- w. The increase in capacity was justified in anticipation of increasing demand.
- x. Since profit before interest has also declined over the period, there is no merit in the argument that the return on investment has declined due to increase in capital employed.

- y. Since exports constitute less than 5% of its total sales, no injury could have been suffered due to possible deterioration in exports.
- z. With regard to arguments with respect to increase in employment and productivity, it was submitted that there is no change in the employment per unit of capacity and the increase in number of employees is in line with the increasing capacity and production. It was also submitted that the productivity per day was much lower than capacity per day.
- aa. With regard to arguments that Indian production of stainless steel grew from \*\*\*% from 2016 to 2017, and that the production of pipes and tubes increased from 2016 to 2018; it is submitted that none of the figures relates to product under consideration. In any case, the increase in imports is much more than the increases in production referred to.
- bb. As regards the argument that prices of stainless steel have increased, it was submitted that an increase in prices of stainless steel products as a whole is not indicative of the trend in price of subject goods in India as the DGCI&S data shows a decrease by \*\*\* % in the landed price of imports.
- cc. While the sales revenue of the domestic industry has increased, its selling price has reduced, leading to a decline in its profits.
- dd. Regarding the argument that volume of imports from Vietnam is not significant, it was highlighted that the imports from Vietnam constitute \*\*\*% of the total imports of subject goods and one-tenth of the market in India, which is not insignificant.
- ee. The fact that the supplier of subject goods export \*\*\*% of their goods to India shows that India is one of their major export markets.

## H.2. Submission by other interested parties

146. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link, are as follows:
- a. Despite claiming difficulties in identifying the MSME producers, the applicants have quantified the performance of such producers to evaluate market share, demand and consumption of subject goods, which is per se incorrect.
  - b. Despite increase in production capacities, capacity utilization has remained low, leading to increased cost of production. The applicants should be asked to furnish project report and reasons for abysmal capacity utilization.
  - c. Since production and sales of the applicants have remained constant, it is evident that there is no adverse impact on the production and sales of subject goods.
  - d. An increase in number of employees without commensurate increase in productivity has resulted in financial burden.
  - e. The capacity utilization is declining because the petitioners are increasing capacity. The production of the domestic industry has increased.
  - f. Injury is caused to the domestic industry by undue/unjustified increase in capacities as it is unable to stabilize its capacities which resulted in higher capital employed, negative return on capital employed and huge losses.
  - g. While domestic sales have increased by \*\*\*%; export sales show a decline of \*\*\*%, which has caused injury.
  - h. Inventory as number of days of sales and of production have declined.
  - i. Selling price declined with decline in cost of sales.
  - j. Goods from Vietnam are coming at the same price at which the goods are exported from other subject countries, whereas goods from China PR are coming at very low prices.
  - k. Price undercutting from Vietnam is negative which means subject goods from Vietnam are above non-injurious price.
  - l. China has a share of \*\*\*%, Vietnam only has a share of \*\*\*%. Low priced Chinese imports are causing injury to domestic industry and there is no causal link between imports from Vietnam and injury to the domestic industry.
  - m. Return on capital employed is positive during the injury period.
  - n. Number of employees has increased, as also productivity.

- o. Overall performance of the domestic industry is improving and injury to the domestic industry cannot be attributed to imports from subject country.
- p. There is no causal link between the imports of subject goods and injury to the domestic industry, which is being caused by low-priced goods from China.
- q. The injurious effects of other imports must be segregated from other factors.
- r. Indian industry did not suffer material injury from Vietnamese imports during the period of investigation.
- s. Domestic production of Stainless Steel in India grew at the rate of \*\*\*% from \*\*\* million tons to \*\*\* million tons from 2016 to 2017. The production of pipes and tubes increased from \*\*\* million MT to \*\*\* million MT from 2016 to 2018.
- t. Sale price of stainless steel products of all forms have been increasing from 2016 to 2017, due to increase in price of nickel, iron and scrap.
- u. The average price of subject goods from Vietnam increased by 10% from 2016 to 2017.
- v. Two of the largest producers in India, Ratnamani Metals & Tubes and Apex Tubes Pvt. Ltd. have shown a constant increase in revenue.
- w. The injury to the domestic industry may result from factors other than subject imports.
- x. The export sales of the Indian companies may be impacted by the effect of trade investigations initiated by other countries such as United States and European Union.
- y. Volume of imports of subject goods from Vietnam is not so significant so as to immediately dent the interest of the domestic industry.

### **H.3. Examination by the Authority**

- 147. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of imports from the subject countries. The analysis undertaken by the authority ipso facto takes into account the submissions made by the petitioners and opposing interested parties.
- 148. Injury information was filed by following companies post initiation of investigations in the form and manner prescribed by the authority
  - a. Maven Stainless Private Limited
  - b. Navbharat Tubes Limited
  - c. Jindal Quality Tubular Limited
  - d. SNP Steels
  - e. JNB Steel Industries Pvt. Ltd.
  - f. Remi Edelstahl Tubulars Ltd.
  - g. Bengal Pipe Manufacturing Co.
  - h. Ravi Stainless Steels
  - i. Quality Stainless
  - j. ASB Tubes
- 149. Data of following companies have been collectively considered for the purpose of injury determination as domestic industry for the purpose of present investigations:
  - a. Hisar Steels Pvt Ltd.
  - b. P.S. Raj Steels Pvt Ltd.
  - c. Vikas Stainless Pvt. Ltd.
  - d. Ramsons Stainless
  - e. Sanjhi Metals Pvt. Ltd.
  - f. Shiv Ganga Stainless
  - g. Paras Bhavani Steel Pvt. Ltd.
  - h. JSS Steelitalia Ltd.
  - i. Raajratna Ventures Ltd.
  - j. Suman Steel Industries
  - k. Tirupati Tubes Pvt. Ltd.
  - l. Maven Stainless Private Limited
  - m. Navbharat Tubes Limited
  - n. Jindal Quality Tubular Limited
  - o. SNP Steels
  - p. JNB Steel Industries Pvt. Ltd.

- q. Remi Edelstahl Tubulars Ltd.
- r. Bengal Pipe Manufacturing Co.
- s. Ravi Stainless Steels

a. **Assessment of demand**

150. Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all other countries. The demand so assessed is as follows.

<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>
Subject imports	MT	9,391	17,254	20,594	71,593
Other imports	MT	1,317	1,855	3,141	6,798
DI sales	MT	***	***	***	***
Other producers' sales	MT	***	***	***	***
<b>Demand/ consumption</b>	<b>MT</b>	<b>191,137</b>	<b>201,197</b>	<b>223,553</b>	<b>248,392</b>

151. It is seen that demand for the subject goods has increased throughout the injury period.

**I. Volume effect of imports**

152. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under.

<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>
China PR	MT	4,411	3,630	6,702	43,059
Vietnam	MT	4,980	13,624	13,892	28,535
Subject imports	MT	9,391	17,254	20,594	71,593
Other imports	MT	1,317	1,855	3,141	6,798
<b>Total imports</b>	<b>MT</b>	<b>10,708</b>	<b>19,109</b>	<b>23,735</b>	<b>78,392</b>
<b>Imports in relation to</b>					
DI production	%	***	***	***	***
Consumption	%	5%	9%	9%	29%
Total imports	%	88%	90%	87%	91%

153. It is seen that:

- a. There has been a significant increase in the absolute volume of imports from subject countries by 662%.
- b. The imports have increased sharply in relation to production of the domestic industry from \*\*\*% to \*\*\*%.
- c. The market share of subject imports has increased significantly and the imports account for 29% of the demand.
- d. The imports are largely from the subject countries accounting for 91% of share in imports.

**II. Price effect of imports**

154. With regard to the effect of imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. **Price undercutting**

155. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the net sales realization of the domestic industry for the investigation period. The price undercutting has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a whole.

<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>200 series</b>	<b>300 series</b>	<b>Weighted Average</b>
<b>China PR</b>				
Import volume	MT	33,438	9,094	42,532
Landed price	Rs/MT	101,245	151,589	112,010
Net sales realization	Rs/MT	***	***	***
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***
Price undercutting	Range %	10-20%	20-30%	10-20%
<b>Vietnam</b>				
Import volume	MT	2,611	25,923	28,535
Landed price	Rs/MT	111,606	159,348	154,979
Net sales realization	Rs/MT	***	***	***
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***
Price undercutting	Range %	0-10%	10-20%	10-20%

156. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. Further, the price undercutting is significant, except in case of import of PUC of 200 series from Vietnam. It is also noted that whereas 78% of Chinese imports were of 200 series, 91% of the Vietnamese imports were of 300 series. Based on domestic industry's selling prices, it is seen that the price difference between the 200 series and 300 series pipes is in the region of 75%.

**a. Price underselling**

157. The Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a whole.

<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>200 series</b>	<b>300 series</b>	<b>Weighted Average</b>
<b>China PR</b>				
Import volume	MT	33,438	9,094	42,532
Landed price	Rs/MT	101,245	151,589	112,010
Non-injurious price	Rs/MT	***	***	***
Price underselling	Rs/MT	***	***	***
Price underselling	%	***	***	***
Price underselling	Range	10-20%	10-20%	10-20%
<b>Vietnam</b>				
Import volume	MT	2,611	25,923	28,534
Landed price	Rs/MT	1,11,606	1,59,348	1,54,979
Non-injurious price	Rs/MT	***	***	***
Price underselling	Rs/MT	***	***	***
Price underselling	%	***	***	***
Price underselling	Range	0-10%	10-20%	10-20%

158. It is noted from the above table that the price underselling is positive, indicating that the imports have entered the market at injurious prices.

**b. Price suppression and depression**

159. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	88	96
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	88	95
Landed price	Rs./MT	1,43,488	1,38,290	1,29,110	129,136
Trend	Indexed	100	96	90	90

160. It is seen that both the selling price and cost of sales of the domestic industry have reduced. It is further noted that the landed price of imports declined by 10% over the injury period and is significantly below the selling price of the domestic industry and the cost of the subject goods. This shows that the imports are depressing the prices of the domestic industry and are preventing the price increases, which otherwise would have occurred.

**III. Economic parameters relating to the domestic industry**

161. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

**a. Production, capacity, capacity utilization and sales**

162. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization and sales was as under:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Capacity	MT	1,10,385	1,18,835	1,29,735	1,39,005
Production	MT	58,743	65,172	66,873	73,927
Capacity utilization	%	53%	55%	52%	53%
Domestic sales	MT	56,198	63,095	66,091	72,471

163. The Authority notes that

- a. The capacity of the domestic industry has increased over the injury period. Whereas demand for the product increased by \*\*\* MT, capacities with the domestic industry increased only by \*\*\* MT. However, the domestic industry was unable to increase its capacity utilisation and almost half of the capacity remains unutilized.
- b. The production of the domestic industry increased over the injury period. However, the increase in production was not commensurate with the increase in demand or capacity. Whereas capacity increased by \*\*\* MT, production increased only by \*\*\* MT. Resultantly, capacity utilization of the domestic industry remained quite low.
- c. The sales of the domestic industry have increased over the period. However, it is noted that whereas the Indian industry sales were earlier low in comparison to its capacities, due to absence of demand; the domestic industry suffered low volume of sales in the period of investigation despite significant increase in demand.

**b. Market share**

164. The market share of the domestic industry and domestic producers over the injury period was as under:

<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>
Subject imports	%	5%	9%	9%	29%
Other imports	%	1%	1%	1%	3%
Domestic industry	%	***	***	***	***
Other producers	%	***	***	***	***
Domestic producers as a whole	%	94%	91%	89%	68%

165. It is noted that while the market share of the domestic industry increased in 2015-16 and has been declining thereafter, the market share of domestic producers as a whole has declined over the period and market share of subject imports has increased significantly, particularly in the POI. The imports have taken away significant market share of Indian producers, despite existence of capacities in India.

**c. Inventories**

166. The data relating to inventories of the subject goods is as follows

<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***

167. It is noted that the average inventories increased in 2015-16, and have shown a decline thereafter.

**d. Profit or loss, cash profits and return on capital employed**

168. The profitability position of the domestic industry in terms of profit or loss, cash profits and return on investment was as under:

<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>	<b>2017-18</b>
Profit / Loss	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	-100	-610	-305	-241
Profit before tax	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	-100	-685	-359	-311
Per unit cash profit	Rs./MT	***	(***)	***	***
Trend	Indexed	100	-44	43	91
Cash profits	Rs. Lakhs	***	(***)	***	***
Trend	Indexed	100	-49	51	117
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	36	44	62

169. The Authority notes that:

- The domestic industry has been suffering financial losses throughout the injury period.
- The losses suffered by the domestic industry increased over the injury period, despite increase in sales.
- Cash losses and return on capital employed of the domestic industry have followed the same trend.
- The return during the period of investigation is much lower than that in 2014-15 and much below the reasonable level.

**e. Employment, wages and productivity**

170. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury period was as under:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	131	209
No of employees	Nos	***	***	***	***
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***

171. It is seen that the number of employees has increased over the injury period with an increase in wages and the productivity per employee.

**f. Growth**

172. The trends of volume and profit parameters of the domestic industry showed as under

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Production	%	-	11%	3%	11%
Domestic sales	%	-	12%	5%	10%
Profit per unit	%	-	-510%	50%	21%
Cash profit per unit	%	-	-149%	204%	130%
Return on capital employed	%	-	-64%	22%	41%

173. It is noted that the volume parameters of the domestic industry have shown growth. However, there has been a deterioration in price parameters. The profits, cash profit and return on capital employed have also shown a significant decline over the injury period. The profitability of the domestic industry declined steeply in 2015-16, and has not recovered fully thereafter.

**g. Ability to raise capital investment**

174. It is seen that the domestic industry has enhanced capacity for the subject goods over the period, making capital investment. However, despite increase in demand, the capacities are lying significantly underutilised. While the low capacity utilisation in the past was attributable to lack of demand, the present low capacity utilisation is due to increase in imports.

**h. Factors affecting domestic prices**

175. The Authority notes that the imports are undercutting the prices of the domestic industry. The market share of subject imports has increased over the period, whereas that of the domestic producers has declined. This shows that the imports are penetrating the market with low prices.

**IV. Conclusions on Injury**

176. The Authority notes that the imports have increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and have had a depressing effect on the prices of the domestic industry. The price underselling is also positive. While the market share of subject imports has increased significantly, that of domestic producers has declined. The capacity utilisation of the domestic industry is low. Even though performance of the domestic industry has improved in terms of production, sales and capacity; it is seen that the domestic industry is suffering from underutilised capacities. Further, the domestic industry has suffered losses and its return on investment is low. Accordingly, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

**V. Causal Link**

177. The Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

**a. Volume and prices of imports from third countries**

178. Since the imports from other countries are not significant, these could not have caused injury to the domestic industry.

**b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption**

179. The Authority notes that there is no contraction of demand. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement over the injury period. Further, there have been no changes in the pattern of consumption which could have caused injury to the domestic industry.

**c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

180. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**d. Developments in technology**

181. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate any change in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

**e. Export performance of the domestic industry**

182. The injury information has been considered separately for domestic and exports, to the extent the same could be segregated. Further, exports by the domestic industry are not significant in proportion to the total sales. In fact, it is seen that about 98% of the production has been sold in the domestic market. Possible decline in exports volume or profits could not have caused injury to the domestic industry. .

**f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry**

183. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration. Therefore, the performance of other products being produced and sold by the domestic industry is not relevant.

**VI. Conclusions on causal link**

184. While known other factors listed under the rules do not appear to have caused the injury, the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the subsidized imports.

- The imports are entering the domestic market at prices materially lower than the domestic industry prices, due to the subsidization of the subject goods.
- The imports are undercutting the prices of the domestic industry. As a consequence of price undercutting, the selling price of the domestic industry has declined as the imports depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which otherwise would have occurred.
- The positive price undercutting resulted in an increase in the market share of the foreign producers. As a result, there is decline in market share of domestic producers.
- While the production, sales and capacity of the domestic industry have increased over the injury period, the increase is not commensurate to the increase in demand for the subject goods. The domestic industry is faced with underutilisation of production capacities.
- The domestic industry has suffered losses and its return on investment remains low and inadequate.

185. Accordingly, the Authority concludes that there is a causal link between subsidised imports and the injury suffered by the domestic industry.

**I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

186. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed price of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the period of investigation. The injury margin thus determined is as under

**China**

Particulars	Unit	Jiuli	Residual
Non-injurious price	Rs./MT	***	***
Landed price	Rs./MT	1,51,589	1,00,398
Injury margin	Rs./MT	***	***
Injury margin	%	***	***
Injury margin	Range	15-25	20-30

**Vietnam**

Particulars	Unit	Son Ha SSP Vietnam	Nam Cuong Vietnam and Tuan Dat Metal Company Ltd.	Dai Duong OSS Co. Ltd.	Gia Anh Hung Yen and Gia Anh Joint Stock Company
Non-injurious price	Rs./MT	***	***	***	***
Landed price	Rs./MT	1,54,578	1,57,938	1,53,889	1,48,009
Injury margin	Rs./MT	***	***	***	***
Injury margin	%	***	***	***	***
<b>Injury margin</b>	<b>Range</b>	15-25	10-20	15-25	15-25

Particulars	Unit	Ha Anh Stainless Steel Co. Ltd.	Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co. Ltd.	Steel 568 Co. Ltd	Residual
Non-injurious price	Rs./MT	***	***	***	***
Landed price	Rs./MT	1,48,785	1,62,304	1,31,740	1,31,740
Injury margin	Rs./MT	***	***	***	***
Injury margin	%	***	***	***	***
<b>Injury margin</b>	<b>Range</b>	20-30	10-20	15-25	30-40

**J. POST DISCLOSURE COMMENTS**

187. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under

**K.1. Submission by the domestic industry**

188. The domestic industry reiterated its submissions with regard to scope of domestic industry, inclusion of producers that have imported the subject goods, excess confidentiality claimed by exporters, suppression of facts by exporters and injury. In addition, the domestic industry submitted as under:

- The domestic industry was not allowed adequate access to relevant information, documents and submissions. The submissions filed by interested parties in response to submissions of the domestic industry, queries raised by the Designated Authority, rejoinder submissions and verification reports issued to the interested parties have not been disclosed to the domestic industry.
- Due to excessive confidentiality, the petitioners are handicapped in defending their interests.
- In case of Vietnam, the subsidies in raw material have not been captured.
- US has now set tariffs as high as 456 percent on Vietnam steel imports using material from South Korea and Taiwan, due to abuse of Rules of Origin.
- The Vietnamese producers have benefited from subsidised steel available to them, but this aspect has not been examined.
- The Vietnamese producers have procured steel from other countries, and claimed a value addition of 55%, despite value addition for process involved usually being only 15%.
- Two producers have procured raw material from their related entity in China.
- The questionnaire response of the GOV is restricted to only responding producers/ exporters and not country as whole and therefore, does not relate to non-participating exporters.
- When Zhejiang Jiuli had not disclosed all subsidies received by it, then its response cannot be accepted.

- j. In the absence of a response by related parties, the response filed by Steel 568, Sonha, Jiuli, OSS Dai Duong and Ha Anh cannot be accepted.
- k. It is essential that related parties that are themselves producer of subject goods, parent companies, input suppliers and any other related party that transferred a subsidy to the exporter must participate, failing which the exporter cannot be treated as cooperative. This is in line with the practices in other jurisdictions such as US, Brazil, European Union, Australia and Egypt.
- l. The manufacturing capacity in Vietnam for subject goods has increased drastically, due to availability of subsidized inputs from China.
- m. Zhejiang Jiuli has not exported the subject goods, but seamless stainless steel pipes and tubes.
- n. The Countervailing Duty Rules provide for levy of duty, adequate to remove injury to the domestic industry. However, the non-injurious price determined would not protect the domestic industry..
- o. The non-injurious price should be determined on the basis of actual cost of production.
- p. There is a need for redetermination of non-injurious price, taking into account the raw material cost incurred and actual capacity utilization.

## **K.2. Submission by other interested parties**

- 189. In addition to reiterating their earlier submissions, the interested parties submitted as under:
  - a. The reason that most of the importers in the list to whom questionnaire response were sent have not filed the importer questionnaire response is that they have been importing stainless steel flat products namely coils and sheets falling under HS Code 7219 and 7220 whereas HS code for the product under investigation is 7306.
  - b. BIS compliance is not required for product under consideration but for the input used in them. If BIS was required for product under consideration, most of the companies that have joined in the petition are not registered under BIS for the product. Lam Khang Joint Stock Company, a non-participating producer/exporter procures the raw material from AIFTA member Pt. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, Indonesia who are BIS compliant.
  - c. It is not possible to manufacture all sizes of welded tubes and pipes by only making minor changes in the tooling as separate range of machines with particular range of diameter and thickness will be required to produce desired size with desired tolerance.
  - d. The size and the production of the industry cannot be judged based on the capacity or sales of a sole raw material producer and supplier. Further, the absence of data reveals the fact that the domestic industry is not following the standard rules and regulations laid down by the concerned authorities and there by the government is losing revenue from the said industry.
  - e. In the absence of the supporting data by the domestic industry in regards to production, sales, revenue/employment generation, market share, level of injury etc, it is clear that the sole beneficiary of this investigation is single corporate entity.
  - f. Producers are maintaining good quality in terms of welding, polishing and roundness/flatness of tubes have been able to sell at fair price. This makes it clear that the domestic industry is lacking in terms of quality parameters and therefore, imports are made out of necessity.
  - g. The conclusion of the Authority that few of the participating producers/ exporters have not provided the requisite details asked from them during the verification is factually incorrect as no verification was carried out at the premises of Vinlong. The additional documents were sought and no extension was granted inspite of request.
  - h. Further, the conclusion to quantify various subsidy schemes and margins on the basis of facts available due to absence of full cooperation by Vinlong is factually incorrect. Vinlong has submitted complete Questionnaire Response and was open for verification. No deficiency was pointed out by the Designated Authority during the course of investigation
  - i. Scheme wise comments for the alleged subsidies of Vietnam are as follows: -
    - i. For Program 1 and Program 3 of the alleged subsidy schemes, the Authority has determined that some of the producers have availed the benefit. The Authority is requested to provide the name of the producers who have availed benefits under them.
    - ii. For Program 2, the import tariff at the time of importation of raw materials is 0% in accordance with China-ASEAN Free Trade Agreement (ACFTA) and ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA).

Hence no duty was payable and no benefit was received. Vinlong is an Export Processing Enterprise and is not subject to any import/export duties or VAT on any materials or goods imported or exported according to Law.

- iii. For Program 5, the Authority has concluded its finding based on the finding of US-Laminated Woven Stacks, which is for a different product examined by different Authority with different facts and different period of investigation. Further, there is no direction by the Government of Vietnam to the banks to provide loans at concessional rates. Even if there is a direction, it alone cannot be termed as financial contribution by the government or any public body.
- iv. For program 6, steel industry is not under the scope of the scheme, and none of companies under investigation received any supports from that scheme.
- v. For Program 7, none of the companies have availed benefit under Export Credit from Vietnam Development Bank. Further, Export Credit by Vietnam Development Bank was regulated by Decree 75/2011/NĐ-CP on State investment credit and export credit, which was applicable upto May 14, 2017. Decree 32/2017/NĐ-CP on State Investment Credits came into effect on May 15, 2017 has replaced Decree 75.
- vi. For Program 8, this program was terminated on 16 January 2007 as provided under Decree 151/2006/NĐ-CP.
- vii. For Program 9, the exporters have filed complete questionnaire responses and it was the responsibility of the Authority to conduct on-site verification of all the co-operating producers/exporters and collect & verify the required information from their Books of Accounts. Even in the further information sought for, the latest published Annual Report of State Bank of Vietnam was provided which gives the trends of short term and long-term interest rates prevailing in the country.
- viii. For Program 10, none of the producers/exporters of subject goods fall under any of the subheads and hence are not eligible for any benefit.
- ix. For Program 11, none of the co-operating producers/exporters fall under the definition of Small and Medium Scale Enterprises, except one producer, namely Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co., Ltd., who had provided all the information as part of its Exporters Questionnaire Response and had not applied for or received any benefit under this scheme.
- x. For Program 13, the producers/exporters have not availed any benefit for subject goods/PUC, its effect cannot be taken to and applied in this investigation.
- xi. For Program 14 and Program 15, Vietnam's market economy status has been recognized by over 70 countries as well as by India in 2009 and therefore also accepted that the price of land use-right and the banking services provided by commercial banks are operated under market principles.
- xii. Under Import duty exemption for equipment and machinery to create fixed assets which has not been alleged, to calculate any amount of benefit under this scheme, the benefit should consider allocating the benefit over the life of assets. Further, in case of multi product company, allocating such amount into one subject goods will be highly unjustified.
- xiii. With regard to all the subsidy schemes alleged, the petitioner could not establish the existence of the financial contribution by a government or public body; benefit; and specificity.
- j. Vinlong has been shipping very small quantities of the PUC India and that too at the most expensive price. The share of imports made from Vinlong is hardly 5% in the total imports from Vietnam.
- k. Vinlong has different products lines such as Slotted welded tubes, Sanitary welded tubes, Big diameter welded pipes, Big and thick structural welded tubes and these are also sold under the same HS code. The Indian mill cannot produce all the products manufactured by Vinlong. The authority is requested to clarify the difference between the products and not recommend the duty on products not manufactured by the Indian mill.
- l. Gia Anh Hung Yen Co. Ltd, Ha Anh, Tuan Dat, Nam Cuong, OSS Dai Duong and Gia Anh JSC have stated that inspite of them fully co-operating with the Authority, the Authority should not apply the usage of facts available in their case. This would be inconsistent with the Customs Tariff Rules 1995 and the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.
- m. Gia Anh Hung Yen Co. Ltd, Ha Anh, Tuan Dat, Nam Cuong, OSS Dai Duong and Gia Anh JSC have submitted that since they did not receive any benefit during the period of investigation, the calculation of subsidy margins for them is fully inconsistent with the actual facts pertaining to them.

- n. The DSB rulings indicate that certain types of statements and assertions are not adequate to meet this standard including among others the following:
- Simple assertions unsubstantiated by relevant evidence are not adequate.
  - General information about government policy, with no direct connection to the subsidy programme, is not “sufficient evidence” of specificity.
  - The fact that a company is the user of a program is not evidence that it is the sole or one of the limited users of the program thereby demonstrating specificity.
  - In the absence of information on the allocation of the benefit of the subsidy to the proposed investigation period, much less the inclusion of any evidence in this regard, the requirement to demonstrate the existence of a benefit in the expected investigation period is not met.
- o. As per Trade Notice 13/2018 dated 27th September 2018, supporting firms/ companies are required to submit data/ information in the prescribed format as laid out in Annex-I and Annex-II at pre-initiation stage. On inspection of the public file, no supporting letters were available. The fact that the interested parties have not been given an opportunity to comment on the data of the 19 petitioner companies constituting the domestic industry and 86 supporting companies is violation of principal of natural justice.
- p. It is hereby submitted that no sufficient notice to GOV and the participating producers/exporters verified was given. 10-day notice to prepare for the onsite verification for GOV and three working day time to producers/exporters to prepare for verification is grossly insufficient. Hence, the verification visit was conducted in violation of the provisions of SCM Agreement, Annex VI para 5 and Para 8.8.5 (v) of the Manual of Operating Practices issued by DGTR.
- q. Out of the 9 companies who filed complete exporter questionnaire responses, 6 companies were not verified during the course of verification. Additional information was sought from the unverified producers and exporters and effectively only one working day was given to the unverified exporters to file a voluminous data. Extension requested by Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co., Ltd. was not granted.
- r. As per Para (8) of Rule 7 of the countervailing duty rules, the investigation authority may record its findings on the basis of facts available in case an interested party:
- refuses access to; or
  - does not provide necessary information within a reasonable time; or
  - significantly impedes the investigation.
- s. The producers/exporters have provided all the information and are ready to provide further information. The Director General must categorically clarify which information was not provided in the prescribed format and mere making a statement that the information was not provided in the prescribed format is not enough.
- t. The conclusion has been drawn based on investigations conducted in the past by other investigating authorities for different product and different period.
- u. The authority while using the 'facts available' in a countervailing duty investigation must take into account all the substantiated facts provided by the interested party, even if those facts may not constitute the complete information requested of that party. Further, the 'facts available' to the authority are generally limited to those that may reasonably replace the information that an interested party failed to provide.
- v. The provisions of the Article 12.7 are to ensure that in case the interested party fails to provide the necessary information, the investigation should not be hindered. Thus, the provision permits the use of facts on record solely for the purpose of replacing information that is missing to arrive at an accurate subsidization or injury determination.
- w. Same facts and level of participation by all the producers/exporters from Vietnam was made and the same verification report was issued by the Authority, still NIL subsidy margins has been given to two companies and information submitted by remaining seven companies have been rejected. This shows an inconsistent approach followed by Authority.
- x. Authority must issue a corrigendum Disclosure Statement, disclosing the computation/methodology for injury margin.
- y. The Authority declined the request made by Zhjeian Jiuli Hi-Tech Metals for extension of time to file questionnaire response. However, the Authority has discriminately allowed the domestic producers to file their data after the stipulated time and at a belated stage. The consolidated data of 22 producers was filed at the stage of oral hearing. Therefore, the data should be rejected.

- z. The consolidated information/data purportedly submitted by said producers has not been made available. The Authority is requested to record the date of the submission filed by the Applicant wherein consolidated information of 19 eligible producers was furnished and provide this information to Jiuli so that adequate comments in this regard can be submitted prior to final findings.
- aa. The Authority is requested to consider the submission made by Jiuli concerning the determination of subsidy rate for LTAR and take into account the data for determination of the LTAR subsidy rate.
- bb. It is submitted that the grants received by the company do not automatically qualify as countervailable subsidy and therefore grants received by the company concerning other products does not qualify as countervailable subsidy for the present investigation.
- cc. Rule 2 (b) of CVD Rules does not allow the inclusion of importers within the scope of 'domestic industry'. Importers should have been excluded from the scope of 'domestic industry', at the stage of initiation itself. Therefore, the present investigation is vitiated being based on false and misleading facts/data.
- dd. The support letters filed by domestic producers after the stage of initiation should be rejected. The support letter filed by domestic producers does not meet the requirement stipulated in Trade Notice 13/2018 issued by DGTR.
- ee. The Authority is requested to reject the information concerning total production as estimated by Jindal Stainless Corporate Management Services Private Limited and must revisit the manner in which the estimates of domestic production have been arrived at since the same is unjustified.
- ff. The Authority is requested to disclose all economic parameters not claimed as confidential (including production, capacity, capacity utilization, domestic sales, export sales, inventory, etc.) in the Final Findings.
- gg. Data concerning economic parameters as reflected in disclosure statement does not reconcile with data filed by the domestic producers.
- hh. The authority is requested to upload list of interested parties on DGTR website.
- ii. In terms of the CVD Rules, duty should not be levied when the injury on account of imports is absent. Therefore, to implement the same, Authority is requested to recommend a reference price /benchmark form of duty in the present investigation.
- jj. It is quite evident that the domestic producers are themselves importing the subject goods and causing injury to other Indian producers.
- kk. The Authority should have considered data of all 86 supporting producers for arriving at injury analysis, as it would have enabled the Authority to arrive at a conclusion based on higher participation of domestic producers.
- ll. The Designated Authority should follow 'lesser duty rule' and recommend duty at a rate lower than the margin of subsidy (i.e. to the extent of injury margin as the same is adequate to remove injury), if at all there is any determination of injury.
- mm. The Authority has sought details from Jiuli about the nature of domestic entities/ suppliers of input material. The said data submitted by Jiuli clearly demonstrate that the input materials were sourced from private entity as well as SOE's and confirms that the government of China is not a monopoly supplier of input materials.
- nn. The Authority has not disclosed the area/location in Thailand used to compare the price of land in China. If the benchmark prices of 2010 are indexed, it would show that the rate of subsidy is negligible (0.10%) % and therefore, no subsidy rate should be determined for the Land program. Further, CVD Rules do not permit compounding of benefit on land to determine subsidy rate. Accordingly, Jiuli reiterates that the Authority should not consider land use rights as countervailable subsidy.
- oo. Program 51 - VAT deduction on fixed assets is applicable to entities located in central region. Jiuli is not located in the central region and hence the scheme is not applicable.
- pp. The finance raised through issuance of convertible bonds falls outside the scope of loans provided by the Government of China and should be excluded from the scope of countervailable subsidy.
- qq. Benefit under Program No. 32 for China has not been availed by Jiuli as it has been submitted earlier in the questionnaire response as well.
- rr. Program No. 39 for China alleged is not related to the PUC and hence is not a countervailable subsidy.
- ss. It can be seen from the Appellate Body Report, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, WT/DS379/AB/R, where WTO held that state ownership is not a

sole decisive criterion for determination of 'public body'. Therefore, the loan obtained from the State-Owned Commercial Banks (SOCB) falls outside the preview of subsidy.

- tt. The decline in capacity utilization of the domestic industry is on account of some intrinsic factors. On account of low productivity of domestic industry, the consumers are forced to import subject goods. Therefore, the Authority is requested to investigate the reasons for low capacity utilisation during the period prior to POI and its cascading impact on performance of 'domestic producers'.

### **K.3. Examination by the Authority**

190. As regards submission that no sufficient notice to GOV and the participating producers/exporters was provided for verification, it is noted that the Authority has granted sufficient notice for onsite verification to the GOV as well as to the concerned exporter who agreed for verification. The Authority proceeded for verification only thereafter. According to the GOV's communication addressed to the Authority on 04.06.2019, it is amply clear that the GOV knew well in advance about the verification to be conducted from 17<sup>th</sup> June, 2019 onwards. The participating producers/exporters were also intimated well in advance giving them time of 7-10 days for preparation of verification. In addition to written communication, oral intimation was given to the legal representatives much before the actual verification. In fact, representatives of the GOV and exporter were called about the verification to be taken up by the Authority
191. With regard to the submission that sufficient time was not granted to Vinlong Stainless Steel and no extension was granted by the Authority for submission of documents, the Authority notes that the exporter had requested for 4 extra days for submitting the information and the request was not denied by the Authority. But the exporter failed to file the required information even after the expiry of 4 extra days.
192. The authority notes that verification of M/s Son Ha SSP and M/s Steel 568 was conducted since these companies accounted for highest volume of exports to India. These producers/ exporters furnished all the information sought by the Authority at every stage of the investigation. However, the remaining seven exporters out of total nine exporters did not provide the same and accordingly the Authority has applied facts available, wherever applicable, in the case of these seven exporters.
193. In case of M/s Dai Duong, it may be noted that its response has not been rejected by the Authority. But, wherever the concerned exporter has not provided the information as required by the Authority at any stage of the investigation, the Authority has applied facts available.
194. The issue of BIS compliance is not relevant to the issue of subsidization of the subject goods and injury to the domestic industry.
195. Some interested parties have contended that it is not possible to manufacture all sizes of welded tubes and pipes by only making minor changes in the tooling and separate range of machines with particular range of diameter and thickness will be required to produce desired size with desired tolerance. The Authority notes that this alone does not establish that some product type should be excluded from the scope of the product under consideration.
196. It is seen that the volumes of imports have increased significantly over the injury period and market share of domestic producers as a whole has declined significantly. The petitioners submitted that majority of the production of the product is in MSME category. It has not been established by interested parties that the imports of the product are due to quality considerations. No verifiable evidence has been provided to that effect.
197. Authority holds that a verification is not a substitute for information required to be provided by a party for the purpose of present determination. In fact, verification is only for the satisfaction of the authority. Authority is fully justified in calling information instead of collecting it at the time of verification. Verification is not an opportunity with the interested party to provide information required for determination..
198. As regards the contention that Indian industry cannot produce all products manufactured by Vinlong, Authority notes that no such claim has been established by the company. In fact, no such claim was made at the stage of initiation, nor any evidence has been provided showing exports of a type for which like article is not supplied by the domestic industry. In the absence of any specific claims and evidence, a belated claim with regard to exclusion of some product cannot be accepted. In any case, request for exclusion is very generic and no specific claim has been made in this regard.
199. The Rules do not require the Authority to make data of individual producers of the domestic industry available to other interested parties. The rule requires an opportunity to interested parties to comment on information relating to domestic industry as a whole. It has been consistent practice of the Authority to make available information with regard to domestic industry as a whole and not individual constituents of the domestic industry.
200. Adequate time and opportunity have been provided to the GOV and the participating producers/exporters to prepare for verification. In addition to written communication, oral intimation was given to the legal representatives much before the actual verification. Further, in addition to written communication specifying

requirement for verification of documents, the legal representatives of the parties were orally informed several times about the requirements. It is also noted that it was obligatory on the part of these parties to provide information to the Authority in the initial questionnaire response itself. It is noted that the initial questionnaire responses were highly sketchy and did not contain all relevant information. It is noted that the Authority had very clearly specified in the questionnaire itself that all relevant information and evidence should be provided along with the questionnaire response.

201. In regard to the contention that data of the ten additional producers should not be accepted, it is noted that the issue has already been examined earlier.
202. As regards subsidy margin in case of Jiuli, the domestic industry in its comments to the disclosure statement has submitted that M/s Jiuli has exported only seamless tubes & pipes (NPUC) to India and not the welded one (PUC). After receiving the comment, the Authority called for the import data from D.G. Systems also and has found that not all export transaction for the PUC export to India reported by M/s Jiuli during the POI do appear therein. It is also noted that the rate reported by M/s Jiuli for these export transactions as a whole is too high than average export price of PUC from China PR. In view of the submissions made by the domestic industry and the analysis as done by the Authority, the export price of M/s Jiuli cannot be accepted for determination of injury margin. Accordingly, the Authority has used the facts available for determination of injury margin of M/s Jiuli. However, the Authority has accepted most of the information as submitted by M/s Jiuli in its EQR for the purposes of determination of subsidy margin for M/s Jiuli.
203. As regards the contention by some of the participating companies regarding non-exclusion of the companies which had imported the PUC, it is noted that the Authority has excluded such entities for the purpose of DI standing. However, even after exclusion of such entities the standing requirement of domestic industry is met even at the initiation stage.
204. As regards the contention that the gross domestic production reported by Jindal Stainless Corporate Management Services Private Limited be not accepted, it is noted that none of the interested parties has provided any other information with regard to gross domestic production. In the instant case, 12 companies provided their injury information at the stage of initiation, while additional 86 companies supported the petition. Post initiation, 10 companies provided their injury information. It is noted that even if producers importing the product under consideration is excluded, then also the companies forming part of domestic industry constitute a major proportion within the meaning of the rules.
205. As regards list of interested parties' placement on the website, the Authority has already listed names of all the exporters and importers who have participated in the present investigations. Further, all the relevant information was placed in public file and access to the same was provided to the interested parties during the course of the investigations.
206. As regards recommendation of benchmark form of duty is concerned, it is noted that appropriate form of duty is recommended by the Authority depending on factual matrix of the case.
  
207. With regard to subsidies in land use right, it is noted that the benefit on land use has been determined as per Annexure IV of the CVD Rules. Further, as regards the claims that the benchmarking of 2010 prices will show negligible subsidy, the authority notes that the concerned exporter has not substantiated its claim with any documentary evidence. In the absence of any such evidence, the authority has determined the benefit based on facts available.
208. With regard to the contention that the subsidy determination made in other investigation cannot be applied to the present investigation, it is noted that the authority has only proceeded on the basis of facts available where requisite information has not been produced by the exporter/producer.
209. Some interested parties have contended that the decline in capacity utilisation of the domestic industry is on account of some other factors. However, no such factor have been identified nor any evidence has been provided to demonstrate that the decline in capacity utilisation is on account of some intrinsic factors and not on account of subsidized import.
210. With regard to the contentions raised in respect of subsidy schemes of Vietnam, the issues raised and concerns expressed by the interested parties have been dealt herein as under:
  - i. In regard to the contention that the name of the producers availing benefits under Program 1 and Program 3 should be identified, it is noted that the subsidy margin has been imposed on the producers/exporters of the subject goods as mentioned in the relevant table.
  - ii. With regard to the contentions raised in Program 5, the Authority notes that loans can be provided at concessional rates by a bank which may be Govt. owned or privately controlled and that even if a bank is

- privately controlled, it cannot be said that there is absence of countervailability if the private bank offers loan at the concessional rate at the direction of the central bank/ government.
- iii. With regard to the contentions raised in Program 6, the Authority notes that the program is not product/ sector specific as claimed.
  - iv. With regard to the contentions raised in respect of Program 7, 8 and 10 that the steel sector is excluded from the benefit under Decree 75/2011/ND-CP on state investment credit and export credit, which was applicable up to May 14, 2017, it is noted that Decree 75/2011/ND-CP has been replaced by Decree 32/2017/ND-CP on State Investment Credits with effect from May 15, 2017 which continues to exclude steel sector from the benefit. However, it is noted that this benefit is given to the steel industry under a different scheme namely “Steel Industry Development Master Plan”
  - v. With regard to Program no.11, the Authority notes that the GOV should not restrict its response to only responding producers/exporters. The benefit under the scheme is provided to the SMEs. Neither the GOV nor the exporter has provided appropriate reasons as to why Vinlong Stainless Steel Company Limited despite being a SME eligible to avail the benefit under the scheme has not applied or availed the benefit under the scheme.
  - vi. With regard to contention raised with respect to Program 13, it is noted that neither the GOV nor the exporters have disputed the existence of this programme and therefore it is countervailable for residual category of Vietnam based producer(s) /exporter(s).
  - vii. With regard to Program 14 and Program 15- relating to grant of land/land use rights at less than adequate remuneration, it has been contended that Vietnam has been given market economy status by the Government of India and accordingly no such benefit has been conferred on the producer(s)/exporter(s) of the PUC. In this regard, authority notes that grant or otherwise of market economy status to the exporting country has no relation with operation of such programs less than adequate remuneration.
  - viii. With regard to the scheme of import duty exemption for equipment and machinery to create fixed assets, it is noted that the GOV has accepted the existence of this programme and has mentioned M/s Dai Duong having availed this benefit. M/s Dai Duong however has not reported this benefit and accordingly the authority has proceeded on the basis of facts available.
  - ix. With regard to the request for declaring Vietnamese exporters as non-cooperative on account of non-submission of information/ data/details in respect of their related parties, it is noted that the domestic industry have failed to substantiate that input(s) for the PUC have been sourced from any such related parties and accordingly the authority does not deem fit to declare Vietnamese exporter as non-cooperative on this ground.
  - x. In regard to the contention of the domestic industry that the Vietnamese producer/exporter of the PUC are violating rules of origin criteria by misdeclaring the value addition achieved on imported inputs, the authority notes that examination of this issue is outside the purview of the current investigation.

## **K. CONCLUSIONS**

211. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that
- i. The product under consideration has been exported to India from subject countries at subsidized value, thus resulting in subsidization of the product.
  - ii. The domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the product under consideration.
  - iii. The material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

## **L. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS AND OTHER ISSUES**

212. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
213. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization and create level playing field.

## M. RECOMMENDATION

214. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including Government of China PR and Government of Vietnam and adequate opportunity was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury and causal links in favour or against thereof. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from China PR and Vietnam in the form and manner described hereunder.
215. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the definitive countervailing duty as mentioned in Col 7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Vietnam.

DUTY TABLE

S.No.	Heading/sub heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount as a % of CIF Value
1	73064000, 73066100, 73066900, 73061100, 73062100	Welded stainless steel pipes and tubes	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd.	21.74
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S.No. 1	29.88
3	-do-	-do-	Any country other than China PR and Vietnam	China PR	Any	29.88
4	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited	NIL
5	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Nam Cuong Metal Company Limited	11.04
6	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	OSS Dai Duong International Joint Stock Company	11.10
7	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co., Ltd.	10.33
8	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Steel 568 Co., Ltd.	NIL
9	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Ha Anh Stainless Steel Company Limited	11.96
10	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Gia Anh Hung Yen Co., Ltd.	11.96

11	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer other than 4 to 10 above	11.96
12	-do-	-do-	Any country other than Vietnam and China PR	Vietnam	Any	11.96

216. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
217. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Add. Secy. & Designated Authority